साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Phone : +91 731 2015827

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 11 अंक 51 | प्रति सोमवार इंदौर, 31 जुलाई से 6 अगस्त 2017 | पृष्ठ 12 | मूल्य 2/- रुपए

मोदी जनधन बाप की जागीर नहीं, जिससे मौज उड़ाओ, मीडिया पर लुटाओ

सूचना अधिकार के १२ वर्ष बाद भी, सरकारें क्यों नहीं बतातीं, दिखाती अपना हिसाब

जनता को आधार कार्ड अनिवार्य उसको बैंक खाते से मोबाइल से जोड़ों, हर लेन-देन नगदीहीन करो? बताओ कमाया कहां से, खर्च कहां किया, धूर्त गिद्धों तुम जनता को हर तरह से नोचों, हर दिन मीडिया का मुंह बंद रखने हजारों करोड़ के विज्ञापन बांटो, जानकारी मांगने पर आवेदकों को डराओ-धमकाओ। धारा 4 का पालन 12 वर्ष बाद भी क्यों नहीं हुआ?

भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी आजाद भारत के इतिहास का सबसे कम पढ़ा-लिखा, बकवादी, पूंजीपतियों का सबसे बड़ा रखैल, घोर राक्षस प्रधानमंत्री सिद्ध हुआ, जिन बातों के लिये ये शूकर कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की घोर आलोचना करता था। जालसाजी और ब्लैक मेलिंग से सत्ता हथियाने के बाद जनता को निचोड़ने के लिये कांग्रेस की ही आधी अधूरी पड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है। चाहे वो इस श्वान की आधार कार्ड योजना हो जिसके विरुद्ध इस जालसाज ने 26/09/2013 की आम सभा में बोला था, किये जनता की निजी जिंदगी का हनन होने के साथ विदेशी आक्रांताओं नागरिकों को भी भारतीय नागरिक बनाकर भारतीय नागरिक सुविधायें प्रदान करने के साथ ही, देश की सुरक्षा के लिये भारी खतरा सिद्ध होगी और खतरा सिद्ध हो रही है। कोई भी पाकिस्तानी भारत में घुसकर सबसे पहले आधारकार्ड बनवाकर, एक तो भारतीय नागरिक बन जाता हैं, फिर आसानी से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने लगता है। पिछले 5 पकड़े गये अधिकांश पाक नागरिकों के पास 3 से 5 अलग स्थानों के आधार कार्ड भी मिलें, दूसरी ओर अब व्यक्ति के खाते से आधार कार्ड के नं. के आधार पर चारों तरफ जालसाजी की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। पहले आधार कार्ड फिर उससे मोबाइल, मोबाइल से बैंक खाते निकालकर आसानी से सेंध लगाई जा रही हैं, न केवल देश में वरन् देश के बाहर से भी आधार कार्ड धारियों के साथ ठगी हो रही है और पुलिस की सायबर अपराध शाखा, अपराध शाखा, पुलिस थानों में कर्मचारियों को न तो भारी प्रशिक्षण मिला हुआ हैं, न ही बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, न व इंजीनियर्स हैं। बेशक वो खाकीवर्दी के सरकारी अपराधी हैं। जिनके विरुद्ध या जिनकी ढिलाई, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण 70% अपराधी न केवल आसानी से बच निकलते हैं। वरन् वे ही पुलिस के सबसे बड़े दानदाता भी होते हैं। इसलिये ये स्वयं उन्हें पालते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो ये हैं कि स्वयं सरकार के पास सारे डाटा को संग्रहित करने का स्वयं का सर्वर नहीं है। दुनिया के अधिकांश देशों की जानकारियां पहले सीधे अमेरिका पहुंचती हैं। माइक्रोसाफ्ट के डाटा सेंटर पर, फिर 130 करोड़ के आधार कार्ड का डाटा भी लाख सरकार घोषणा करे, कि उसकी सुरक्षा पूरी है। परन्तु डाटा सुरक्षा की व्यवस्था पूर्णतः बकवास हैं, (शेष पेज 9 पर)

चीन को दबाने, घेरने के लिए आवश्यक है कि अविश्सनीयता प्रसारित करे

सबकुछ टिका है विश्वास और अविश्वास पर, प्रसार करो चीनी षड़यंत्रों का

चाहे घरेलू संबंध हो,सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या व्यावसायिक समृद्धि का मामला हो

हमारे राष्ट्र के नीति नियताओं, नेताओं, अधिकारियों, सेना और जनता सभी जानते हैं कि चीन के सामने हम हर तरह से कमजोर पड़ रहे है। और वो भारत को घेरने, बर्बाद करने के लिए हर हथकंडे अपना रहा है। उसमें कुछ भी नहीं है। चीन की नीचता कमीनेपन, दोगलेपन और अविश्वसनीय का न केवल सहस्त्रों वर्ष पुराना इतिहास को पुख्ता ही कर रहा है।

जिसके शासक अपनी जनता के सगे नहीं हैं, तो ओर फिर किसके सगे हो सकते हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार है, जिसके उपयोग में आपको टैंक व बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं वरन जितना पैसा मोदी अपने को बचाने में मीडिया प्रबंधन

को कर रहा है उसका 10 प्रश भी चीन की नीतियों और उसके सामान की अविश्सनीयता पर खर्च करे तो उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जा सकती है। जब उसका सामान विदेशी बाजारों में अविश्वसनीयता की नीयत से देखा जाता है तो उसकी इस अविश्सनीयता को ही बाजार में खुलकर प्रचारित करना है। (शेष पेज 9 पर)

घोंटू सर्विस टैक्स अंबानी की जागीर पेट्रोल अलग क्यों?

40 लाख करोड़ के बदले मोदी लाया जीएसटी

जैसे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 06 में हुआ था रुपए 20-25 लाख करोड़ की कमाई, जिसका मोदी और उसकी भाजपा सरकार बनने से पहले विरोध करते थे, प्रधानमंत्री बनते ही मोटी कमाई को देख मुंह में पानी आ गया और थोप दिये जनता को बर्बाद करने

विश्व के अधिकांश लोकतंत्रों में सत्ता पूंजीपतियों की कठपुतली होती है, चाहे वो अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, भारत व अन्य कोई भी देश हो, स्वाभाविक है सत्ता को नचाने वाले ये पूंजीपति अपनी

में सत्ताधीशों श्वानों को टुकड़े डालकर न केवल उनका मुंह बंद रखते हैं वरन जब तक सत्ताधीश उनके इशारों पर नाचकर दुम हिलाते रहते हैं। तब तक उनको ये भरपूर सदुपयोग करते हैं। सत्ता के साथ जनहितों से खिलवाड़ करते हुये सत्ताधीशों को भी अपने व्यापार को दुनिया में फैलाने के लिए सत्ता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों तक को अपना व्यावसायिक प्रतिनिधि बनाकर सत्ता से सत्ता के जिन पर घूमने लाभ के समझोतों पर हस्ताक्षर करवा राष्ट्र के संसाधनों को गिरवी करने, संसाधनों का दुरुपयोग करने से नहीं चूकते, वैसे तो ये हर लोकतांत्रिक राष्ट्र की कहानी है। (शेष पेज 10 पर)

पिछले 12 वर्षों में 56 प्रजाति के 600 करोड़ कटवा, 6 करोड़ पेड़ लगाने की नौटंकी

पुराने पाप धोने, 6 करोड़ वृक्षारोपण का ये कैसा विश्व रिकार्ड..?

2014 में भी 1 करोड़ वृक्ष लगाये थे, कितने बचे, वर्ष भर क्या करता है, वन और वानिकी विभाग फिर एक पेड़ पर रुपए 100 की प्राथमिक लागत, ढुलाई, कार्रवाई मानवश्रम व प्रशासनिक लागत रुपए 200 का खर्च जन-धन से लूटे करों से। कहां से आयेगी 6 करोड़ पौध/वन विभाग और उद्यानिकी व वानिकी में तो 2 करोड़ भी पौधे नहीं वास्तविकता में। सारे रिकार्ड कागजों पर ही बनें।

मप्र के इतिहास में तीसरी बार चुनाव जीतने और लगातार 12 वर्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने का इतिहास, तो मुख्यमंत्री रहते हुये शिवराज ने रच दिया जो कि निहायत साधारण ग्रामीण परिवार से था। स्वाभाविक था सत्ता की चकाचौंध से दिमाग बोरा गया। मंत्रालयों में बैठे जिस धूर्त ने जो पढ़ाया, मोटी रकम हजम करने कर दिया। कितना ज्ञान किस-किस विभाग का प्राप्त करें, जब भा. प्रताड़ना सेवा, भारतीय वन भक्षण सेवा, भारतीय अपराधी संरक्षण जो सब मोटा महीना जन-धन के वेतन से लेने के साथ ही अन्य माध्यमों से हजम करते हैं। भारी ज्ञानी-ध्यानी माने जाते हैं। कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। भारतीय वन भक्षण सेवा के अधिकारियों ने कहा कि जन से जून तक सूखे मौसम में 52 प्रकार के वृक्षों की कटाई छूट दे दी, अब 1 वर्ष में प्रदेश के बचे खुचे 3 लाख है. पर वनों से 56 प्रकार के वृक्षों की आड़ में कीमती सागौन के वर्ष भी काटे (शेष पेज 10 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

स्थानांतरण उद्योग का धंधा रहा मंदा
अब चुनाववाद 2020 में ही होंगे

स्थानांतरण के मौसम में भी बच गये हर विभाग के मोटे भ्रष्ट

अधिकांश विभागों में 5 वर्ष से ज्यादा समय से जमे बाबू, उपयंत्री, छोटे अधिकारी जमे हैं, बच गये 3 वर्ष में स्थानांतरण हो जाने से भ्रष्टाचार, निकम्मापन और जालसाजियां कम होती है। काम नियमानुसार और स्टॉफ भी चुस्त दुरुस्त बना रहता है

मप्र के इस स्थानांतरण के मौसम में शासकीय विभागों में मात्र 5-7 प्रतिशत ही स्थानांतरण हुये उसमें भी अधिकांश चाहने वालों के ही। जबकि स्टॉफ को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने के लिए न्यूनतम 20 प्रश और अधिकतम 33 प्रश स्थानांतरण हर वर्ष होते रहने चाहिये ताकि कार्य भी नियमानुसार हो भ्रष्टाचार जालसाजियां और स्टॉफ के निकम्मेपन में कमी आये। परंतु 2013, 2014 में चुनावों के कारण ज्यादा स्थानांतरण नहीं हो सके 2015 में थोड़े बहुत हुये, 2016 में सिंहस्थ के कारण नहीं हो सके। लंबे समय तक एक ही स्थानों पर जमे रहने से चाहे बाबू, चपरासी से लेकर पटवारी, तहसीलदार, निरीक्षक, सहायक जिलाधीशों, उपजिलाधीशों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, छोटे मोटे अधिकारियों तक में न केवल घोर निकंमापन, बत्तमीजी, जालसाजियां और भ्रष्टाचार बढ़ता है। वरन कार्य की गति मंद होने और कार्य समय पर न होने से सरकार के सिर बदनामी का ठीकरा भी फूटता है। फिर विधानसभा, लोकसभा के सत्रों में इससे उत्पन्न परिणामों की भी खासी पूछ-परख और प्रश्नोत्तरी भी होते हैं। जिससे सत्ताधीशों को भारी परेशानी झेलना पड़ती है।

इसमें भी महिला कर्मचारियों, अधिकारियों को हिलते-डुलते 12 बजे तक आने 1 से 3 बजे तक लंच मनाने और साढ़े चार-पांच बजे तक किसी भी बहाने चले जाने रोज की आदत दूसरे स्टॉफ को भी निकम्मा और कामचोर बनने के लिये मजबूर कर देती है। जबकि अधिकांश महिला कर्मचारी एक ही स्थान पर 10-20 वर्ष तक गुजार देती हैं। पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ उनका स्थानंतरण नहीं करती। स्वाभाविक प्राकृतिक कमनीयता के वशीभूत बचकर और बचाकर चलने के फलस्वरूप देश व देश की जनता का भारी नुकसान करते हैं। फिर यौनाकर्षण के वशीभूत को नहीं, चाहे भारतीय प्रताड़ना सेवा का अधिकार, मंत्री, आयुक्त, संचालक, प्रमुख अभियंता, इसका लाभ मिलता है, और दिया जाता है। उसके सामने, कानून नियम, न्याय, नैतिकता सब बकवास है। जिसका महिलाकर्मी न सिर्फ भरपूर फायदा उठाती हैं दूसरी और देर से आकर चली जाने या कार्य न करने पर कोई अधिकारी पूछताछ कर लें या थोड़ी सी कड़क आवाज में बात कर लें तो तो इनका सर्वश्रेष्ठ हथियार होता है आंखों से दो बूंद लुढ़का कर बखेड़ा खड़ा करना जिससे सारे अधिकारी कर्मचारी करते हैं। अपनी गल्ती न स्वीकारना और बवाल खड़ा कर अधिकारियों को उल्टे ही डराना-धमकाना स्वाभाविक है। सारे कार्यालय का माहौल बिगाड़ने और बदनाम करने वाली ऐसी महिला कर्मचारी अधिकारियों को दो वर्ष से ज्यादा कहीं नहीं रखना चाहिये, जबकि सभी विभागों में मंत्रालयों से चलकर गांवों के स्कूलों, पंचायतों तक हर विभाग में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को स्थान परिवतन किये जाते रहने से जनता को सुविधायें मिलने, कार्य शीघ्र होने, भ्रष्टाचार और लेटलतीफी फाइलें अटकाने से काफी राहत मिलती है।

मप्र वाणिज्यकर विभाग में ही उपायुक्त सं.क्र. 3 अब्दुल मजीद को 5 वर्ष से ज्यादा एक ही स्थान पर जमे हैं। ऐसे कई अधिकारी जो 4 वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हैं। जबकि पूरे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों कर्मचारी अधिकारियों का 4 वर्षों के बाद भी स्थानांतरण नहीं किया गया है। कई ने 10-20 वर्ष से ज्यादा एक ही शहर में गुजार दिये। सबसे बुरा हाल जिला पंचायतों, जिलाधीश कार्यालयों, महिला बाल विकास, खनिज, खाद्यान्न, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, जल संसाधन गृह, गृह व ग्राम निवेश, नगर पालिकाओं, निगमों, रेशम पंजीयन, परिवहन ग्रामीण विकास रेशम, नर्मदा घाटी, विकास प्राधिकरणों में बैठे पूरे प्रदेश में लाखों कर्मचारियों ने एक ही स्थान पर न केवल 5 वर्ष से ज्यादा पूरे कर लिये वरन हजारों ने वो 20-20 वर्ष पूरे कर लिये, जिससे भ्रष्टाचार और निकम्मापन चारों तरफ हर विभाग में स्थानांतरण न होने के ही कारण छाया हुआ है। जिससे लेट-लतीफी हर कार्य में बढ़ी है। फाइलें अटकाने, कार्यों को समय पर संपन्न न करने न होने देने में सबसे बड़ा कारण यही तीन वर्ष के बाद 20-20 वर्ष तक स्थानांतरण न करना ही है।

इस वर्ष विभागीय पोर्टल पर अपने आवेदन देकर मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण की सुविधायें दिये जाने से स्थानांतरण में कमाई का धंधा मंदा हुआ। परंतु जिनके स्थानांतरण सरकार ने अपनी मर्जी से किये थे उन्होंने रूकवाने बदलवाने में अवश्य पैसा खर्च किया। जिसके लपेटे में अधिकांश प्रथम व द्वितीय श्रेणी कर्मचारी ही आये। उन अधिकारियों ने मुख्यालयों में पैसा देकर स्थानांतरण रद कार्य खाद्य व औषधि में अनेकों खाद्य व औषधि निरीक्षक 10 वर्षों बाद भी धन खर्चकर जमे रहने में सफल रहे।

भर्तियां न होने व सेवानिवृत्ति के कारण अधिकांश विभागों में 60% कर्म. अधि. का अभाव

म.प्र. शासन के सभी विभाग ध्वस्त होने के कगार पर, कैसे चलेगी सरकार

लो.नि., जल संसाधन, लो.स्वा.यां., वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रा.यां. वाणिज्य कर, राजस्व, न.घा., वि.प्रा., खाद्य व औषधि, खनिज, पंचायत व ग्रामीण विकास न्यायालय, पुलिस, आबकारी, कृषि आदि अधिकांश विभागों में चपरासी, बाबुओं से लेकर अधिकारियों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, नर्सों का 50 से 70 % अभाव, अधिकांश कार्य ठेका मजदूरों जिसमें बाबु से इंजीनियर, डॉक्टर तक।

म.प्र. के साथ पूरे देश में 1991 में हुए धूर्त विश्व व्यापार संगठन के इशारे पर समझौते के अंतर्गत 30% कटौती के चक्कर में पूरे देश में चल रहे सभी मंत्रालयों के सभी विभागों में कर्मचारियों अधिकारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, निरीक्षकों, पुलिस, शिक्षक आदि की स्थायी भर्तियां न होने से केन्द्र व राज्यों में शासन के 90% सरकारी कार्यालय में 70% कर्मचारी अधिकारी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक सेवानिवृत्त हो गये, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, मृत्यु बीमारी के चलते विभागों से अलग हो गये, जबकि जनसंख्या के बढ़ते तकनीकी बदलने, कार्यपद्धति बदलने कानूनों में परिवर्तन, वक्त बदलने से स्थाई कर्मियों की आवश्यकता 4 गुना तक बढ़ गयी, मूल विभागों में समय की आवश्यकता के अनुसार कई अनेकों विभागों का जन्म हो गया, परन्तु कार्य पुराने अधिकारियों को दाये-बाये कर ही कार्य चलाया जा रहा है, अकेले लोक निर्माण विभाग में सेतु, विद्युत यांत्रिकीय, राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ म.प्र. सड़क विकास निगम, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई की अलग शाखा खोल सैकड़ों इंजीनियरों को इसमें स्थानांतरित कर दिया गया, वर्तमान हालात ये हैं कि यहां मुख्य अभियंता ही 2-3 से ज्यादा परीक्षेत्रों का कार्य संभाल रहा है। 100 से ज्यादा उपयंत्री, सहायक यंत्रियों का और 35 से ज्यादा सहा. यंत्री, कार्यपालन यंत्री के प्रभार में और 10 से ज्यादा कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं। यही हाल म.प्र. जल संसाधन, म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, ग्रमीण यांत्रिकीय का भी हैं, जहां उपयंत्री और सहायक यंत्रियों के सैकड़ों पद खाली हैं। वर्षों से, यहां तक कि नियमों के विपरीत का.यं. बोरासी म.प्र. लो.नि.वि. के व्यावसायिक संगठन म.प्र. सड़क डकैती विकास निगम में गृह जिले में बैठ 7 वर्षों से संभागीय प्रबंधक क्र. 1,2 के साथ इंदौर, उज्जैन संभाग के परिक्षेत्र का महाप्रबंधक का पद भी संभाल रहा है। जबकि न केवल भारी भ्रष्ट, निकम्मा होने के साथ ही घोर मूढ़ होने के साथ कार्य बने न बने गुणवत्ता कैसी भी हो, ठेकेदारों के हिसाब से चलो, वसूली अपने हिसाब से करो और वसूली का 50% हिस्सा आकाओं के चरणों में सादर समर्पित कर दो, ताकि मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ आंखें मूंद अपना हिस्से की बोटी चूसता बैठे और हर कुकर्म पर अपने आप को बचाने इसे भी बचाये। म.प्र. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में तो हाल इससे बुरा है, यहां पर 70% उपयंत्रियों, सहा. यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों, अधीक्षण व मुख्य अभियंताओं का अभाव होने के साथ ही एक-एक कार्यपालन यंत्री के पास 3 संभागों का प्रभार है। अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता ढंग सेहिन्दी नहीं पढ़ सकते तो आंग्ल और अभियांत्रिकीय की बात तो दूर की कोढ़ी है। अ.यं. बीबीएस परिवहार जो घोर मक्कार और कामचोर होने के साथ भारी भ्रष्ट भी है। सेवानिवृत्ति के 6 वर्ष बाद भी न.घा.वि.प्रा. के मुख्यालय में सलाहकार और सचिव के रुप में संविदा नियुक्त पर बैठा है। वही हाल अभियांत्रिकीय, शिवहरे का भी है। सेवानिवृत्ति के बाद भी 3 वर्ष से समय विस्तार पर चल रहा है। यही हाल म.प्र. जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ग्रामीण यांत्रिकीय, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, म.प्र. लोक स्वा. यांत्रिकीय विभाग, विद्युत मंडल, सभी निगमों, विकास प्राधिकरणों और के.वि. निगम में भी इंजीनियरों का हैं। यदि स्वास्थ्य विभाग में सेवानिवृत्ति और शिक्षा विभाग में प्राध्यपकों की आयु बढ़ाकर 65 की जा सकती हैं, तो इन विभाग में भी अच्छे कार्य करने वालों और सेहतमंद लोगों की आयु भी 65 कर दी जानी चाहिए अन्यथा 17-18 में 80-90 के दशक के 80% इंजीनियर सेवानिवृत्त हो जाने से भी तकनीकी विभागों के अच्छे इंजीनियर सेवानिवृत्त हो जायेंगे जिससे सारे उपरोक्त तकनीकी विभाग ध्वस्त हो जायेंगे जो म.प्र. की 7.5 करोड़ जनता और देश 130 करोड़ जनता के लिये आधुनिक जीवन की नागरिक सुविधायें जिसमें सड़कों से लेकर नहरें, बांध, भवन, नालियों, जल आपूर्ति और निकासी प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम पालिकाओं से लेकर लो.नि., लो.स्वा. यांत्रिकीय, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, पंचायत, प्राधिकरण व राज्य के सभी विभागों में कम्प्यूटर ऑपरेटरों से लेकर, शिक्षकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, चपरासियों, बाबुओं तक की संविदा पर ठेके पर दैनिक मजदूरी के आधार पर जो पूरे प्रदेश में संख्या में साढ़े तीन लाख से ज्यादा है। उनसे न्यूनतम वेतन पर कार्य लेकर उनका तिहरा शोषण कर रही हैं। यथा तकनीकी और विशेषज्ञ कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तो दूर 7 से 8 हजार देकर उनका वर्षों तक उपयोग करती हैं, जिससे वो किसी दूसरी सरकारी नौकरी के लायक भी नहीं रहते। उनकी उम्र गुजर जाती है। बाद में उन्हें ठेका श्रमिकों में परिवर्तित कर उनका वेतन को 25 से 30 % तक ठेकेदार हजम कर जाते है। जिससे उनकी हालात बंधुआ मजदूरों से भी गई गुजरी हो जाती है। इसका आर्थिक व सामाजिक दुष्परिणाम उन साढ़े तीन लाख से ज्यादा अस्थायी कर्मियों को तो भोगना ही पड़ रहा है। दूसरी तरफ सरकार को और जनता को अपने जनधन के भारी दुरुपयोग और भ्रष्टाचार में बर्बादी का भारी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। क्योंकि न केवल सरकार व जनता, अस्थायी कर्मचारियों से किसी जिम्मेदारी, विश्वास और गुणवत्तापूर्ण कार्य की अपेक्षा नहीं कर सकती। स्वाभाविक है अस्थायी कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक लेखापाल, लिपिक, चपरासी तक सभी अस्थायी हैं। तो वो खुलकर भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि सरकार उन्हें हटाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते।

दूसरी तरफ ऐसे अस्थायी कर्मचारियों का स्थायी स्टॉफ खुलकर भ्रष्टाचार, जालसाजीपूर्ण कार्यों में उपयोग करता है। उनका तन,मन, धन से न केवल शोषण करता है वरन् उनको कोई भी मान, सम्मान तो दूर 99% महिला कर्मियों का स्थायी स्टाफ से लेकर अधिकांश बड़े अधिकारी तक यौन शोषण भी करते हैं। महिला कर्मचारी चुपचाप अस्थायी होने के कारण मजबूरी में अपना तन समर्पित करती हैं। जो चाहता है उसके सामने जिसके लिये स्वयं केन्द्र व राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

विश्व व्यापार संगठन जो कि धूर्त पूंजीपतियों का वैश्विक गिरोह हैं, जो अपने लाभ के लिए हर देश की सरकार में बैठे मंत्रियों, नेताओं और बड़े अधिकारियों को खरीद भ्रष्टाचार में धन बांट अपनी नीतियां लागू करने पहले वहां की सुचारु चलती व्यवस्थाओं को चौपट करने अपनी शर्तें थोप कर अपनी मनमर्जी चलाने, उन देशों की जनता को लूटने शासकीय तंत्रों को कमजोर करने सबसे पहले वहां के विभागों के स्थायी कर्मचारियों, अधिकारियों की संख्या जरूरत से आधी या एक तिहाई करवाने की चाल चलता है, जो उसके लूट के व्यवसाय में आने वाले कल में बाधा उत्पन्न करेंगी, 1990 के बाद के दशक में मोटा कमीशन बांट, पहले समझौतों पर हस्ताक्षर करवा और भर्तियां इसीलिये बंद करवा दी ताकि आने वाले कल में उन्हें वैधानिक अवैधानिक तरीके से पैर पसारने, लूट का तांडव करने, प्राकृतिक व मानवीय स्त्रोतों व क्षमताओं का शोषण कर दोहन करने में कोई रोक-टोक न करें। वो आसानी से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई सरकारों के नेताओं को खरीद और मोटा कमीशन बांट, कानून बनवायें, कानूनों की आड़ में अपना तांडव कर, मोटा धनार्जन करें, इसी कारण विदेशों में, जहां की जनता समझदार थी, इन विश्व व्यापार संगठन का भारी विरोध किया गया, पर बिकाऊ मीडिया ने विश्व व्यापार संगठन का ये राक्षसी रुप कभी प्रदर्शित व प्रकाशित नहीं किया, परिणामस्वरुप भारत में ही केन्द्र व राज्य सरकारों में 300 से ज्यादा विभागों, उपक्रमों में लगभग डेढ़ करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों, अधिकारियों का अभाव होने के कारण न केवल केन्द्र को व 30 से ज्यादा राज्यों की सरकारें ध्वस्त होने के कगार पर आ गई है। बहुराष्ट्रीय कं. भी यही चाहती हैं, ताकि हर कार्य वो अपने तरीके से करने और सरकारें करवाने के लिये बाध्य हो जाये, टी.सी.एस. विप्रो से लेकर माइक्रोसाफ्ट ने अपनी सेवायें और अपना माल बेचने के लिये इन्हीं षड्यंत्रों के सदुपयोग से हजारों करोड़ का पूरी देश की केन्द्र व राज्य सरकारों में काम इसी दम पर किया और बदले में सैकड़ों करोड़ कमीशन के आई.ए.एस. लॉबी अने और मु.मं. व नेताओं ने हड़पा, यदि सरकार के पास अपना साफ्टवेयर इंजीनियरों का स्टाफ होता तो जनधन के साफ्टवेयर बनाने में हजारों करोड़ रु. बर्बाद नहीं होते, विप्रो ने अचल संपत्ति का साफ्टवेयर तो मात्र रु. 50 लाख का भी नहीं था रु. 550 करोड़ में बनाया, वहीं सीएस ने वाणिज्यकर का कोषालय, लो.नि.वि. अन्य विभागों के 25 से ज्यादा बकवास और परेशानी एक आधे अधूरे साफ्टवेयर बनाकर करीब रु. 2000 करोड़ का चंदन पिछले 10 वर्षों में लगाया, जबकि स्वयं के दम पर कुछ करोड़ रु. का वेतन खर्च करके भी स्वयं साफ्टवेयर बनाये जा सकते थे। एक तरफ सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों की कमी का रोना रोती है। दूसरी तरफ करोड़ों को रोजगारों का स्थाई भर्तियां नहीं की जाती हैं। जिससे सरकार का प्रबंधन बिगड़ रहा है और भ्रष्टाचार और लूट बढ़ रही है।

लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग, परि. क्रि. ई., भवन व पथ, सेतु, भ्रष्टाचार का तांडव

सारे इंजिनियर घोर भ्रष्ट, भ्रष्टों को दे रहे पूरा संरक्षण

50 से ज्यादा सहा. यंत्री कार्यपालन यंत्री को प्रभार में, सड़के भवन निर्माण में मापदंडों का पालन नहीं, डिजाइन कुछ, कार्य कुछ, स्तरहीन माल, गुणवत्ता बलाये ताक, अग्रवालों ने कर दिया चौपट

मप्र लोक निर्माण विभाग यथार्थ में भ्रष्टाचार निर्माण विभाग बन चुका है। यहां बैठे धूर्त सचिव प्रमोद अग्रवाल जो बड़वानी और शिवपुरी के सहा. यंत्रीयों से सीधे वसूली कांड में लिप्त रहे हैं। जिसकी जांच प्र.स.रा.श. जुलानिया ने की थी, अखबारों में दो वर्ष पहले काफी सुर्खियां बटोर चुके दूसरे स्तर पर सचिव चप्र अग्रवाल नाम भले ही कहीं न आया हो परंतु अपने हिस्से का पाइप लाइन का पैसा बिना हो-हल्ले के हजम किया, तीसरे स्तर के प्र.अ. अखिलेश अग्रवाल जो सन् 2011 तक का. यं. था अपनी जालसाजियों, भ्रष्टाचार से कमाये धन से प्रमुख अभियंता बन गया, जो सहा. यंत्री रहते कुछ काम नहीं करवा पाया वो प्रमुख अभियंता बनने के बाद निकंमा केवल अपने मोटे कमीशन की ताक में रहता है। इसलिए उसने 40 से ज्यादा सहा. यंत्रियों को कार्यपालन यंत्री का प्रभार देकर प्रदेश के 55 से ज्यादा भवन और पथ कार्यों की देखरेख, निर्माण, मरम्मत आदि के संभागों में बैठा रखा हैं जो इसे अपने पद की रायल्टी के रूप में मोटी रकम चुकाते हैं। स्वाभाविक है वो जालसाजियां करेंगे ही। हालात ये हैं कि हर संभाग में शासकीय कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से काम करवाने के नाम पर करोड़ों रुपए का बिटुमन, इमल्सन, मेटल की खरीदी की जाती है। सड़कों की मरम्मत के करने के नाम पर जो बाले-बाले ही बेचकर हजम कर ली जाती है। इसलिये वर्षों से हर संभाग और उप संभागों में भंडार खाता ही नहीं बनाया जाता। जबकि भवनों की मरम्मत के लिये सीमेंट रेती, रंगाई, पुताई के लिए रंग, रोगन, ब्रश चूना, डिस्टेंपर आदि की छोटे-मोटे कार्यों के लिए खरीदी और कार्यों को इसी दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की टीम से करवाने का प्रावधान है, परंतु अधिकांश ऐसे कार्य हर संभाग में ठेके पर किये जाकर करोड़ों रुपए का धन, का.यंत्र अधीक्षण यंत्री, प्रमुख अभियंता, सचिव, प्रमुख सचिव से होता हुआ मुख्यमंत्री तक भी पहुंचता है। दूसरी ओर हर संभाग में निविदा, स्वीकृति पत्र जारी होते ही, अनुबंध 15 दिन में हस्ताक्षरित होने की अपेक्षा 95 प्रश अनुबंध 15 दिन के बाद ही हस्ताक्षरित किये जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच, जबकि ऐसी अवस्था में सुरक्षा निधि जप्त कर द्वितीय न्यूनतम को लाभ व कार्य दिया जाना चाहिये, इसके विपरीत का.यं. महीने से 6-6 माह तक अनुबंध हस्ताक्षरित करते है। इससे शासन की दोहरी हानि उठानी पड़ती है। इसीलिए जानबूझकर प्रभारी का.यं. बैठाये जाते हैं कि वे अपने भ्रष्टाचार में हिस्सा दे न दें परंतु उच्च पद पर बैठने की रायल्टी इन सूकर प्रजाति के भ्रष्टाचारियों को अवश्य पहुंचाते रहे। बेशक इस जमावट के पीछे का दिमाग भी मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे सचिव विवेक अग्रवाल का ही है, जो कि अपना शेरू हिस्सा स्वयं डकार रहा है। इसलिये इन हरामखोर शूकरों की फौज कभी भी सूचना के अधिकार आवेदन का आवेदनानुसार जवाब समय पर नहीं देती।

प्रधान सचिव, प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री कार्यालयों में बैठे सभी अधिकारी है। तो घोर धूर्त और कमीशन खोर अपने अधीनस्थों से महीना खाकर उन्हें हर से बचाते हैं। यही कारण है कि ये स्वयं भी घोर भ्रष्टाचार के चलते सूचना के अधिकार में अपने कुकर्मों का स्वयं प्रमाण रूपी दस्तावेज देने से बचते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट सिद्ध हुआ प्रमुख अभियंता मुख्यालय और प्रमुख सचिव कार्यालय यहां बैठे ये अग्रवाल बनियों की बपौती है। सरकारी धन और सरकारी कार्यालय इसलिये जानकारी के नाम पर सिर्फ बहाने और बहाने। पिछले तीन साल से वहां बैठे हरामखोरों ने चाहे वह सिहंस्थ में अरबों रुपए की बंदरबांट हो या सड़कों के निर्माण, मरम्मत पुर्ननवीनीकरण सबसे मोटा कमीशन हजम किया गया। अपने चहेते ठेकेदारों को ठेके दिलवा, स्तरहीन कार्य करवाया जा रहा है। दूसरी ओर ऑनलाइन निविदायें जारी करना और ऑनलाइन निविदायें भरवाकर निश्चित समय के बाद ऑनलाइन ही टेंडर खोलने की प्रक्रिया में भारी जालसाजियां, मुख्यालय स्तर पर की जाने लगी हैं जिन ठेकेदारों को बाहर करना है, किसको निविदा स्वीकृति पत्र देना है, किससे स्वीकृति में कितना कमीशन मिलेगा पर निर्भर होता है। इसमें भी ठेकेदारों को पूर्व के कार्यों के आधार पर काली सूची में डालना मोटा पैसा वसूलकर फिर बहाली करना। इसमें भी मुख्यालय में भारी खेल चल रहा है। इधर परियोजना क्रियान्वयन ईकाई में 90 प्रश लो.नि.वि.का भवन व पथ का घोर निकम्मा और जालसाज स्टॉफ जो अतिरिक्त परियोजना संचालक या मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री या सहायक परियोजना संचालक से लेकर संभागीय परियोजना यंत्री के रूप में बैठाई गई सारी महाधूर्त, जालसाज फौज, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था, आदिम जाति, अनु. जाति के छात्रावासों के निर्माण, व अन्य शासकीय विभागों के कार्यालयों के विद्यालयों न्यायालय कक्षों, उत्कृष्ट विद्यालयों, स्टेडियम, चिकित्सालय भवन आदि के भवनों का निर्माण कर रही है, जिसके अकेले इंदौर, उज्जैन संभाग के 900 से ज्यादा भवन निर्माण चल रहे है। या हो चुके हैं। भारी जालसाजियां, भ्रष्टाचार और स्तरहीनता के शिकार है। भवन की नियोजित संरचना कुछ, बनाया कुछ, इंदौर के ही गांधी नगर, में बनने वाले विद्यालय के 36 कमरे बनने थे, बनाये गये 27 कमरे। फिर लाल अस्पताल में मलबा फेंकने, भवन निर्माण में टनों से लोहा कम डाला गया, पूरा डिजाइन बदला गया, यही हाल उज्जैन, देवास, शाजापुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, आगर, इंदौर के, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन के हर काम में या सभी शासकीय भवनों के निर्माण में किया और खुले में 30 से 40 प्रतिशत का मार्जिन हड़पने हर बार ठेकेदारों के साथ मिलकर स्तरहीन खिड़की-दरवाजे, लाइट फिटिंग, स्तरहीन ट्यूबलाइट, पंखों, व अन्य सामानों में मोटा कमीशन हड़पा जा रहा है। यही कारण है कि यहां बैठा अ. परि. संचालक और अप्रैल के पूर्व के एपीडी गुप्ता जो कि उल्टे-सीधे स्तरहीन कार्यों को संपन्न करवाकर वसूली के लिये कुख्यात हैं। सूचना के अधिकार में दिये गये आवेदनों और अपीलों का न तो जवाब देते हैं न ही अपने भ्रष्टाचारों को बचाने उनकी सुनवाई करते हैं। इंदौर के कार्यालय में एपीडी ने ऐसे चपरासी बैठा रखे हैं। जो बिना पैसा लिये दिये कार्य नहीं करते हैं और अन्य किसी को घुसने व बात तक नहीं करने देते हैं। जब चपरासियों का ये हाल है तो बाकी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां पर समयवृद्धि, भाव, बजट वृद्धि में भारी लेन-देन की खबरें आती रहती है। 70 प्रतिशत का.यं. सं. परि. यं. न केवल भ्रष्ट, निकम्में, जालसाज बैठे होने से अधिकांश भवनों की छतों, फ्लोरिंग, प्लास्टर, खिड़की, दरवाजों से लेकर बिजली फिटिंग, ट्यूबलाइट, फिक्सचर पंखें, संबंधित विभाग को सौंपने से पूर्व ही अपनी स्तरहीन का परिचय, ठेकेदार, डी.पी.ई. सहा. यं. उपयंत्री जो अधिकांश ठेकेदार के मोटे कमीशन पर नौकरी या संविदा कर्मी होते हैं। आदि जो निर्माण के लिये जिम्मेदार हैं। अपनी भ्रष्ट कार्य शैली के रूप में दे देते हैं। बेशक प्रधान सचिव प्रमोद अग्रवाल ने कई बार भवनों का औचक निरीक्षण किया, पर उद्देश्य गुणवत्ता की देखरेख नहीं वरन गुड़ की मिठास बटोरना ही रहा, भवनों की डिजाइन के साथ फाउंडेशन से लेकर अंतिम साजसज्जा, खिड़की, दरवाजों, टाइल्स, फिटिंग तक सबकी जांच, संबंधित विभाग के जिम्मेदारों को अपनी स्वतंत्र एजेन्सी से करवाई जानी चाहिये।

यही हाल इस विभाग सेतु संभागों का है। मप्र के सेतु परिक्षेत्र में आने वाले सभी 8-10 सेतु संभागों में भी कोई भी कार्य डिजाइन और निश्चित समयावधि में कभी पूर्ण नहीं होता। सेतु निर्माणों में जानबूझकर समयवृद्धि से भाव वृद्धि और डिजाइन डीपीआर में फैरबदल कर सेतु निर्माण कार्यों को अत्याधिक धीमी गति से किया जाकर हर का.यं. ठेकेदार के साथ मिलकर मोटी रकम हजम करता है। फिर इंदौर में बैठा का.यं. रा.ना. मिश्रा जो कि 5 वर्षों से ज्यादा समय से मंत्री राजेन्द्र शुक्ला के दम पर जमा था, जिसका अधिकांश कार्याकाल, सं.क्र.1, रा.रा. व सेतु में ही इंदौर में पूरा हुआ है अपने भ्रष्टाचारों, बत्तमीजीपूर्ण व्यवहार के लिये वर्षों से कुख्यात था, जिसे पूर्व में लो.नि.मं. रहते हुए विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने रीवा पहुंचाया था। उनके जाते ही पुनः इंदौर में आ गया था। वैसे लोकायुक्त दिलीप सिंग ने मात्र मोबाइल की रिकार्डिंग के आधार पर प्रकरण बनाने का षड़यंत्र अवश्य किया है, जो न्यायालय में औचित्यहीन सिद्ध होगा। इस अत्याधिक सयाने को वरिष्ठता के आधार पर प्रमुख अभियंता होना चाहिये था, जो 18 में कां.यं. से सेवानिवृत्त हो जायेगा।

सेतु परिक्षेत्र में मु.अ. अधीक्षण यंत्री, का.यं., सहा. यं. कार्यालयों में, बेशक स्टॉफ की कमी तो है ही, परंतु वर्षों से जमे हैं। इस कारण भी पूरे सेतु संभागों चाहे वो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, सागर आदि में बैठे घोर निकम्मों का स्टॉफ कार्य से नहीं वेतन से मतलब रखता है। सूचना के अधिकार में आवेदन देने पर आवेदक का ये श्वानों की फौज देखते ही गुर्राने और डरानें-धमकाने के अंदाज में बात करती है। ताकि आवेदक यदि आवेदन दे भी दे तो उसे जानकारी न देना पड़े, उस पर यदि का.यं.रा.ना. मिश्रा, लो. सू.अ. हो तो जानकारी तो दूर ये शूकर उल्टे ही आवेदक से उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुये जवाब व सवाल करने लगता था।

यथार्थ में सरकार में शीर्ष पर बैठे मंत्री जो करोड़ों रुपए खर्च कर चुनाव जीतकर बड़ी मुश्किल से मंत्री पद प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक हैं कि उन्हें विभाग का मंत्री बनने की आड़ में विभाग से नहीं वरन् अपनी मोटी वसूली से मतलब होता है। इसलिये वो जानबूझकर शीर्ष पर घोर भ्रष्टों को बैठाकर अपनी मोटी वसूली के साथ संरक्षण देते हैं। हालात ये है कि विभाग में 40 प्रतिशत स्टॉफ मुख्य अभियंता से लेकर उपयंत्री, बाबू, चपरासियों तक की कमी है। 80 प्रतिशत स्टॉफ सहायक यंत्रियों, उपयंत्रियों से लेकर बाब, चपरासियों तक एक ही स्थान पर 5 से ज्यादा वर्षों से जमे हैं। स्वाभाविक है कि घोर निकम्में और भ्रष्ट हो चुके हैं। 80 प्रतिशत महिला कर्मचारी अधिकारी तक 12-12.30 तक कार्यालय आती है। लंच के नाम 1 बजे से तीन बजे तक गपियाती बाजार में खरीदारी करती है और 4.30 बजे तक यदि रिश्वत की व्यवस्था नहीं हे तो सैकड़ों वाहनों के साथ समय पर निकल लेती है। ऊपर से स्टॉफ की कमी जो 2018-20 तक 40 प्रतिशत रह जायेगा, काम कौन करें।

खनिज अधिकारी, निरीक्षक कर्मचारी ही देते हैं डकैती की पूरी छूट

खनिज विभाग में बैठे जिला अधिकारी निरीक्षक और वहां वर्षों से अजगर की तरह कुंडली मारे बैठे कर्मचारी से खनिज, माफियाओं, ठेकेदारों को अपनी मोटी कमाई के लिये स्वयं ही तरीके बताकर रेती, गिट्टी पत्थर से लेकर अन्य कीमती खनिजों के अवैध उत्खनन से डकैती डालने की छूट देते हैं। छोटी-छोटी खदानें लेकर बिना रायल्टी चुकाये चौगुनी से 100 गुनी तक लूट करवाते हैं। यही कारण हैं कि यहां बैठे शूकरों की फौज जानकारी देने के नाम न केवल आनाकानी करती हैं वरन् अपील लगा देने पर यदि जिलाधीश थोड़ी सी भी ईमानदारी से कार्य करता है और निःशुल्क जानकारी देने के लिये भी लिख देता है तो भी ये हरामखोरों की फौज महीनों बाद भी आधी अधूरी जानकारी देकर टरका देती है। फिर फोन लगाने पर उठाती नहीं। इस संदर्भ में इंदौर, देवास, धार-उज्जैन में पत्र दिये गये। इंदौर में खनिज अधिकारी खन्ना के कहने के बाद भी वहां बैठे डोंडवे बाबु ने जवाब नहीं दिया। जब अपील की गई तो निःशुल्क देने के लिये कलेक्टर ने आदेशित किया तो भी जि.ख.अ. खन्ना ने आजकल करते-करते डेढ़ महीने गुजारने के बाद बाबु डोंडके ने आधे-अधूरे जवाब की सीडी बड़ी मुश्किल से दी।

अवैध रेत खनन ट्रकों और ट्रालियों के पकड़े जाने के मामले में देखा गया कि अधिकांश में कम नाप जो क्यूबिक मीटर या फुट में होनी चाहिए थी वर्गफुट में दिखाकर वसूली की जाती है। साथ ही में वसूली भी जब होती है जब ट्रक, ट्राली, से सौदे नहीं पर पाते अन्यथा 80% मामलों में निरीक्षक ऊपर लेन-देन कर छोड़ देते हैं। दूसरी ओर सूचना अधिकार के इस संबंध में आवेदन देने पर इंदौर में ही एसडीएम ने जांच पड़ताल की तो 90% खदानों में आवंटित जमीन से कई गुना ज्यादा जमीन में पहाड़ों पर बिना अतिरिक्त भूमि के आवंटन और रायल्टी के अवैध उत्खनन कर लिया गया था, बेशक ये हाल पूरे प्रदेश के और देश के हर जिले का है। फिर जब खनिज मंत्री राजेन्द्र शुक्ला स्वयं ही बड़ा खनिज माफिया हो, तो खनिज विभाग में डकैतों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

दूसरी ओर अधिकांश सरकारी कार्य विभागों यथा लो.नि.वि., जिसके भवन और पथ के हर निर्माण व मरम्मत कार्य में, म.प्र. सड़क डकैती विकास निगम के भी हर सड़क निर्माण मरम्मत कार्य, परि. क्रियान्वयन इकाई के हर भवन के निर्माण कार्य में जहां रायल्टी हर निर्माण से मरम्मत, पुर्न नवीनीकरण के बिलों में से स्वयं विभाग को ही स्त्रोत पर काटनी चाहिए 70÷ कार्यों में ठेकेदारों के फर्जी प्रमाण पत्रों और शपथ पत्र पर कटोत्रा नहीं किया जाता और ठेकेदारों के साथ मिलकर न केवल लो. वि. बि. लो. स्वा.यां, पंचायत, जल संसाधन, विद्युत कं., ग्रामीण यांत्रिकीय, गृह निर्माण मंडलों, नगर निगमों, पालिकाओं, विकास प्राधिकरणों में, रेल्वे के. लो.नि.वि. में रु. 2 से 5000 करोड़ की रायल्टी हजम कर ली जाती है। जिसके अंकेक्षण की शासकीय स्तर पर खनिज विभाग की कोई व्यवस्था नहीं है। केन्द्र व राज्यों के अंतर्गत बीओटी सड़कों में हजारों करोड़ की रायल्टी चोरी पर भी खनिज विभाग का कोई नियंत्रण न होने से इन बीओटी में पिछले 10 वर्षों में पूरे प्रदेश में ही रु. 5000 करोड़ से ज्यादा चोरी की गई। परन्तु खनिज विभाग के जिला कार्यालय के अधिकारियों, निरीक्षकों को नियमित लूट से ही फुर्सत नहीं।

साप्ताहिक समय माया

स्वच्छता अभियान जनता की जेब पर चल, नगर निगमों, पालिकाओं का खेल डकैती करना

जनधन की लूट, पार्षद, महापौर, आयुक्त उपायुक्त, लेखाधिकारी तक सब करोड़पति

सतना में कथूरिया के पकड़े जाने से स्पष्ट है कि चारों तरफ पार्षदों से लेकर कर्मचारियों, अधिकारियों की भ्रष्ट गिद्ध फौज बैठी है, जो हर कदम नोंच खसोंट से अरबों रुपए जनता से लूट कर बर्बाद करने और बटोरने में लगी है

प्रदेश व देश के नगर निगमों और पालिकाओं में लूट का तांडव मचा हुआ है। पूरे देश में ऊपर से मोदी के सफाई अभियान से सफाई कर्मचारियों से लेकर सभी अधिकारियों, डॉक्टरों, इंजिनियरों, निगमायुक्तों, सहा. निगमायुक्तों, बाबुओं, लेखाधिकारी के साथ पार्षदों, उनसे जुड़े नेता, ठेकेदारों, महापौरों को भी दिन दूनी रात चौगुनी कमाई में प्रतिदिन गाड़ियों में लगने वाले पेट्रोल, डीजल,फिनाइल, क्लोरीन की ही कमाई चौगुनी हो गई, यथार्थ में पहले अभियान की शुरूआत में एक मिनी ट्रक 10 चक्कर लगाता था, अब तक वह 1-2 चक्कर लगाकर ट्रकों, ट्रालों, मिनी ट्रकों का 8 बार का खर्च दिखाकर पूरा पेट्रोल,डीजल बाजार में बेंचकर हजम कर रहा है, जिसमें चालक, परिचालक से लेकर पार्षदों, महापौर और निगमायुक्तों का भी हिस्सा है। जो अकेले इंदौर में ही रुपए करोड़ों से ज्यादा का होता है। सफाई के नाम पर से जनता की जेब की सफाई महीना वसूल और चालान बनाकर भी की जा रही है। जबकि नगर निगम संपत्तिकर के रूप में भी सफाई कर के रूप में भी जनता से वसूली अलग से करती है। इसके साथ ही ये निगम व पालिकाओं के साथ ही केन्द्र सरकार भी जनता से पेट्रोल, डीजल गैस व अन्य सामग्री पर भी जनता 0.5 प्रतिशत का अधिभार वसूलकर जनता की जेब की सफाई कर रही है।

मोदी की सफाई ने अपने प्रिय मित्र वाहन निर्माता टाटा के भी एक लाख से ज्यादा ट्रकों की खरीदी कर उससे न केवल मोटा कमीशन ऐंठा वरन प्रदेश के शहरीय विकास मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी, महापौर और निगमायुक्तों ने भी मोटा कमीशन प्राप्त किया और जनता के सीने पर सफाई के नाम पर सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हल्ला मचाते कान फोड़ते नगरों की गलियों, मोहल्लों की सड़कों पर घूमते, उनके शराब पिये कर्मचारी घर की कचरा डालने वाली और गली मोहल्ले में रहने वाली सड़कों पर गुजरने वाली महिलाओं को घूरते छेड़ते फिरते थे, जो बोले उस पर उल्टा ही प्रकरण लाद दें, इसलिए 2-3 महीनों में तो मिनी ट्रकों की आवाजाही भी 8-10 चक्करों से घटकर 1-2 पर ही आ गई, जब उनके ठेके पर चलने वाले ड्राइवरों से पूछताछ की गई तो बदबू मारते हुए बोला क्या करें सिर सबसे ज्यादा हमारा ही पक जाता है पर नौकरी करना है। पेट भरना हैतो न केवल हल्ला वरन् ट्रक में भरे कचरे की बदबू भी सारे दिन पीकर काम करने को मजबूर कर देती है।

अगर न पिये तो इतना स्पीकर का शोर और सड़ांध की बदबू झेलना एक पल भी संभव नहीं होता। आखिर नगर निगम और पालिकायें ये स्पीकर लगाकर जनता के साथ उन कर्मियों पर क्यों घोर अत्याचार कर रही है। क्या यही स्वच्छ पर्यावरण की परिभाषा है, जिसमें 14 घंटे गाड़ियां भारी प्रदूषण फैलाती घूमती रहे और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक भारी ध्वनि प्रदूषण के अत्याचार से पीड़ित करती रहे। अकेले इंदौर नगर निगम में ही रुपए 300 करोड़ से ज्यादा के वाहन खरीदी व रिक्शें, कचरे के डिब्बों और लगाने पर खर्च किए गए स्वाभाविक था 10 से 20प्रतिशत से ज्यादा का भुगतान कर 10-20 प्रतिशत कमीशन हजम किया गया। जबकि सफाई के नाम पर सन् 2006 में भी एडीबी के कर्ज से रुपए 200 करोड़ के ट्रक नाली और सीवरेज मशीनी ट्रकों से लेकर कचरा पेटियों के ट्रक 8 डिब्बों वाले रिक्शे और हाथ चलित गाड़ियां खरीदी गई थी। उन 500 से ज्यादा रिक्शों से लेकर ट्रकों का पता तक नहीं है। अर्थात वो सारे गायब है। बेचकर खत्म कर दिये गये। वर्तमान में खरीदे गये ट्रक साल के अंत तक पहुंचते-पहुंचते आधे रह जायेंगे। एक वार्ड में दो ट्रक आवंटित किये गये थे। जो अब एक रह गये ।स्वच्छता के नाम पर प्रथम पुरुस्कार जीतने का खामियाजा न केवल जनता की जेब की सफाई से भुगतना पड़ रहा है दूसरी तरफ ध्वनि प्रदूषण का प्रकोप झेलने के साथ ये सफाई के ट्रक बड़ी-बड़ी गलियों में खड़े कर सामान्य यातायात भी बाधित कर रहे हैं, जो बदबू का प्रदूषण फैला रहे हैं। गलियों में बेकलेन में सड़कों का कचरा 05 से 15 दिन तक नहीं उठ रहा हैं। यह है वर्तमान सफाई की हालत इंदौर की व अन्य देश के नगरों व महानगरों की, सफाई का बुखार उतर चुका हैं।

निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षदों और महापौर सब अपनी लूट में जुटे है। सीसी सड़कों पर डामर, गिट्टी बार-बार बिछाकर मोटे बिलों में लूट, शासकीय निगम के बगीचों में पहले वृक्षों को काटना, सीमेंट की कुर्सियों को तोड़ना, फिर टाइल्स लगवाना, उखड़वाना, अनावश्यक क्रांकीट जंगल खड़े करना। निगम की जमीनों पर कब्जे कर क्रांकीट का निर्माण करवाना और मोटे बिल बनवाकर पैसा ठेकेदार के माध्यम से स्वयं भी लूटना। इन गिद्धों को स्वयं जल आपूर्ति दो दिन में एक बार आधे घंटे करके भी रुपए 300 का बिल वसूल कर रहे है। जो रहवासी अपने बोरिंगों से काम चला रहे है। उनके बोरिंग भी जन-फर तक सूखने लग जाते हैं। ये इन हरामखोर भ्रष्टों को नहीं दिखता।

डकैती के नमूने में एक नमूना चंद्रभागा पुल इंदौर का देखिये, जिस पुल की जो मात्र रुपए 50-60 लाख में तैयार हो सकता था रुपए 5 करोड़ स्वीकृत किया। जिसमें एक खंभे से भी कार्य पर्याप्त हो सकता था। एक तरफ ये लूट और डकैती का तांडव है तो दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद निगम सफाईकर्मी महिला पुरूषों को जो वास्तविकता में 20-30 वर्षों से सफाई कार्यों में लगे हैं। मात्र रुपए 4 हजार 5 हजार वेतन दिया जा रहा है। उनके नियमितीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। जो संख्या में हजारो हैं। जबकि 70 प्रश फर्जी भाई-भतीजों जो नेताओं के पट्ठे हैं लगातार सारे वेतन भत्ते नियमित और कलेक्टर दर पर मिलने के साथ ही उन्होंने सभी सफाईकर्मियों को काम नहीं दिया। ऐसे 2000 से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन भत्तों में से नियमित बंदरबांट होती है।

स्मार्ट सिटी के नाम पर भी अरबों रुपए का कमीशन महापौरों, निगमायुक्तों से लेकर इंजिनियरों और बाबुओं ने डकारा। जालसाजों ने अपनी मोटी कमाई के लिए सहस्रों लोगों को न केवल बेघर किया वरन दाने-दाने के लिए मोहताज कर दिया। अपनी तोड़फोड़ और चौड़ीकरण के नाम पर जबकि इन जालसाजों के पास कोई ठोस प्लान नहीं। मेप के अनुसार नालियों की ाल निकासी की व्यवस्था नहीं है। सिटी इंजिनियरों को शहर की व्यवस्थित जो 50 वर्षों के लिए उपयुक्त हो से नहीं वरन् तत्काल में उल्टे सीधे तरीके से बड़े-बड़े ठेके देकर बिल वसूली से है। जिसमें रुपए 200 करोड़ का लेन-देन किया जा चुका है। अकेले इंदौर में। जिसका सीधा सा नमूना है। 11 किमी की रुपए 300 करोड़ की बीआरटीएस सड़क बेरिकेटिंग पर रुपए 1250 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रुपए 600 करोड़ हजमकर लिये गये। जिसमें न तो स्टार्म वाटर लाइन ढंग से डाली गई न जल निकासी की उचित व्यवस्था की गई। परिणाम सामने है। थोड़ा सा पानी गिरा नहीं कि अधिकांश सड़क स्वयं झील की अपेक्षता तालाब बन जाती है, जिसमें घुटनों से ऊपर वाहनों के टापरों और इंजिन तक पानी पहुंचने लगता है। पिछले वर्षों में रुपए 3000 करोड़ से ज्यादा जन-धन, एडीबी ऋण के इस नगर में खर्च कर दिये गए। पर जल निकासी की व्यवस्था और जल आपूर्ति की व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। जबकि आपूर्ति के लिए नर्मदा तीसरे चरण का पानी भी गायब हो गया। टैंकरों से आपूर्ति केवल मोटी कमाई के लिए ही की जाती है। जालसाज शूकरों की फौज से सूचना अधिकार में जानकारी मांगी तो बहानों की लंबी सूची जारी कर दी जाती है, जैसे नगर निगम के इन अधिकारियों के बाप की जागीर हो। सतना में उपनिगमायुक्त पर पड़े लोकायुक्त छापे जिसमें रुपए 50 लाख का लेन-देन पकड़ा गया तो इंदौर में अकेले ही 1400 टन कचरे का बिल भुगतान करवाता रहा। अभी भी 800 टन जो कि दुगुने से अधिक है भुगतान हो रहा है। महापौर, पार्षदों पर, अधिकारियों पर एक साथ छापे मारे जायें तो कम से कम रुपए एक हजार करोड़ से ज्यादा का नगद पकड़ा जा सकता है। पर जन से लूट गये धन से रुपए 50 लाख से ज्यादा का भुगतान होता है। समाचार पत्र मालिकों और टीबी चैनलों को जबकि विज्ञापन का भुगतान अलग से किया जाता है। तो इनकी जालसाजियों, भ्रष्टाचार और लूट के कांड कौन छापेगा। इस लेख में मात्र सफाई और स्मार्ट सिटी की लूट के बारे में लिखा गया है जबकि निगम के सारे विभागों में न केवल इंदौर, मप्र और देश के हर जिलों में ऐसी ही नोंच-खंसोट, भ्रष्टाचार और लूट का तांडव मचा हुआ है। जिसमें भवन अनुज्ञा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यानिकी, बाजार, निगम संपत्तियों, निगम कर, निगम विद्युत व्यवस्था, रोजगार, गंदी बस्ती उन्मूलन, निर्माण कार्य, कॉलोनी सबमें तांडव और डकैतों के पोश अड्डे हैं। जिसमें जन-धन का अरबों रुपए हजम किया जाता है हर वर्ष।

सूचना के अधिकार को सरकार बना रही मजाक, अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी करते हैं बचने की कोशिशें

सबसे बड़े जालसाज, भ्रष्ट होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, बचने के लिए मांग रहे आधार कार्ड

अरबों रुपए हजम कर गये, 12 वर्ष में सूचना अधिकार के चुन-चुन कर महामक्कार, कामचोर अधिकारी सूचना अधिकार कक्षों में

सूचना का अधिकार अधिनियम 05 को प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर पंचायतों तक बैठे सरपंचों, सचिवों तक को सत्ता और जनधन का मक्खन खाने वालों को सबसे बड़ा अभिषाप लगता है, जानकारी देने के नाम प्रधानमंत्री मोदी, उसके मंत्रालय में बैठे धूर्तों की फौज से लेकर सभी मंत्रालयों में बैठे प्रमुख व प्रधान सचिवों, सभी मंत्रालयों के आयुक्तों, संचालक, प्रमुख अभियंताओं, सभी उपक्रमों यथा बैंकिंग, बीमा, तेल कंपनियां, संचार दूरदर्शन, आकशवाणी आदि आयोग्यों आदि जो सीधे ही सरकार के अंतर्गत कार्यरत है के साथ ही सभी शासकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों व उनके अंतर्गत सभी विभागों न्यायालयों, गृह मंत्रालयों से लेकर दूरराज की ग्राम पंचायतों तक सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वो आवेदकों को सारे जनधन से मोटी तनख्वाह के अतिरिक्त भत्तों के साथ भ्रष्टाचार की मलाई चाटने वाले ऐसे शत्रुभाव से देखते हैं जैसे भ्रष्टाचार के जंगल के राजाओं अर्थात शेर की मांद में श्वान घुस आया हो, उनका बस नहीं चलता वरना वे सूचना के अधिकार का आवेदन लेकर कार्यालय में प्रदेश कस्बों वालों को तत्काल हजम कर जाये।

सूचना के अधिकार की वैसे तो धज्जियां उधेड़ने में केन्द्र व राज्य सरकारों के विधायी, व्यक्तिगत कष्ट निवारण और पेंशन मंत्रालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारे भ्रष्टों ने जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय सर्वोपरि है। अपने भ्रष्टाचारों की हर कदम-कदम पर जानकार मांगने वालों के माध्यम से सच सामने आने से से रोकने के लिए चालबाजियों जालसाजिया करने के अतिरिक्त उस अधिनियम को ही समाप्त करने की कोशिशे भी 2005 से लेकर वर्तमान तक कई बार कोशिशें की जाती रही है।

भारत के असली सत्ताधीश भारतीय प्रशासनिक बनाम प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों को सबसे बड़ा अभिषाप लगता हैं। सूचना का अधिकार जो जिला पंचायतों से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालयों तक घोर भ्रष्टाचारी, जालसाज बैठे आईएएस बनाम इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों को सबसे बड़ा अपमान और अभिशाप है। इन हरामखोरों, जालसाजों को आपने अगर सूचना अधिकार में पत्र दिया तो और इनके कार्यालय के अंर्तगर्त कार्य कर रहे कर्मी, पहले पत्र तो लेने से मना कर देंगे, यदि ले भी ले लिया तो उसे बिना ये बतायें कि ये जानकारियां कहां से मिलेगी शूकरों की फौज उसे निरस्त कर भेज देगी। जबकि संभागायुक्त कार्यालयों में बैठे आयुक्तों को हर दिन 15-25-50 लाख की रिश्वत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जिलाधीशों, जिला पंचायतों, शहरीय विकास से लेकर महिला बाल विकास आदिम जाति, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, राजस्व, भूमि प्रकरणों, भूमाफियाओं तक सबसे चाहिये, यदि सचमुच ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो 12 वर्ष बाद भी अपने संभाग के हर विभाग की जानकारी, सू.अ.अ.05 की धारा 4 के अंतर्गत क्यों नहीं पूरी साइटों पर डलवाई जाती है तुम्हें कोई आवेदन ही नहीं देता, यही हाल सामान्य प्रशासन विभाग से लेकर हर मंत्रालयों में बैठे प्रधान सचिव, सचिवों और आयुक्तों का भी है। चाहे वाणिज्यकर, लो.नि.वि., जल संसाधन, लो.स्वा.यां, महिला बाल विकास, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी, राजस्व, परिवहन, वित्त, वन, पशु चिकित्सा, आदिम जाति, ऊर्जा, नर्मदा घाटी, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पंचायत व समाज सेवा आदि सभी विभागों का है, जो जन-धन को नोंच कर हजम करने वाली गिद्धों की फौज अरबों रुपए हजम कर जाती है। भ्रष्टाचार में आवेदन देने अपीलों का जवाब देने तक की तकलीफ नहीं उठाना चाहती, जैसे जन-धन और कानून इनके बाप की जागीर हो जैसे चाहे उसे उपयोग करें, ये जनता के सेवक नहीं जनता को नोंचने कर रक्त पिपासु दानवों की फौज है, जो शासन में पहुंचते ही शंहशाह बन जाती हैं। यही हाल जिलों के जिलाधीश कार्यालयों और जिला पंचायत के मु.का.अ. का भी है। यहां वर्षों से बैठी जिसमें कुछ तो 20 वर्षों से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर कुंडली मारे बैठे है और अरबों की संपत्ति के मालिक है। पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं इसलिए यहां बैठे हरामखोरों की फौज कैसे जवाब दे, मजाक बना दिया, इस अधिनियम को फिर मुख्यमंत्री शिवराज हो या प्रधानमंत्री मोदी जो अपने हर दिन कुकर्मों को ढांकने हजारों करोड़ के हर दिन विज्ञापन बांटते हैं ताकि कोई भी समाचार पत्र इनके भ्रष्टाचारों और जालसाजियों पर अंगुली न उठाये, इसलिये सूचना अधिकार कक्षों में चुन-चुन कर महामक्कार, भ्रष्टों और निकम्मों की फौज बैठाई जाती हैं ताकि आवेदकों को कोई जानकारी न देनी पड़े।

हर तरह से लूट का तांडव होता है, सबको बंटता है महीना

देशभर में पंपों से नापने में चोरी, मिलावटी पेट्रोल-डीजल व गैस

सभी पेट्रोल पंपों पर पाइप के मुंह पर कांच और गाड़ी चक्की वाली पाइप क्यों नहीं, गैस आपूर्ति में भी लीटर से देने की बजाय किलो के नाम से गैस नहीं पेट्रोल-डीजल में 25 से 90 प्रतिशत तक की मिलावट पर कोई नियंत्रण नहीं, रुपए 20 का पेट्रोल 80 प्रली. फिर भी मिलावट और कम नाप

पूरे देश में पेट्रोल और गैस पंपों पर हो रही कम नाप और मिलावट की लूट के बारे में सन् 2000 से समयमाया लगातार लिखता रहा है। परिणामस्वरूप सन् 2004 में इंदौर के तत्कालीन जिलाधीश मो. सुलेमान ने प्रयास किया था कि हर डीजल और पैट्रोल की पाइप का 1 फुट से 6 इंच का हिस्सा कांच का हो ताकि पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता और आपूर्ति को ग्राहक देख सके, परंतु तेल कं. ने इस चोरी और मिलावट की हकीकत को बचाने से साफ मना कर दिया, दलीले दीं कि पेट्रोल, डीजल और गैस विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। बिना उनकी आज्ञा के संभव नहीं, इसके विपरीत उन्होंने स्टील या धातु वाले हिस्से में भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने पाइप में कांच और खड़ी चूबी लगानी शुरू कर दी। जिससे पेट्रोल, डीजल की गुणवत्ता के साथ आपूर्ति के समय वह चूबी घूमती हुई दिखने से उपभोक्ता यह संतोष उसके रंग और घूमती चक्री को देखकर कर लेता है कि पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता क्या है और वह टंकी में जा भी रहा है कि नहीं, पर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों ने यह व्यवस्था अभी तक नहीं की है।

पूरे देश के पेट्रोल पंपों ने नोटबंदी के समय जो भूमिका अदा की उससे इनकी महत्वपूर्णता का पता तो जनता को मात्र 10 प्रश ही लगा जबकि दूसरी तरह इन पेट्रोल पंपों के नोट स्वीकारने और नये नोट देने का सबसे बड़ा लाभ इन प्रधानसचिवों, सचिवों, आयुक्तों से लेकर जिलाधीशों, उपजिलाधीशों, सहायक जिलाधीशों, खाद्य नागरिक आपूर्ति चपरासी निरीक्षकों, बाबुओं, सहा खाद्य अधिकारियों और जिला खाद्य नियंत्रकों ने अपने लाखों रुपए के पुराने नोट बदलने से भरपूर उठाया, जबकि पंपों के क्षेत्रों के निरीक्षकों सहा खाद्य अधिकारियों से लेकर नियंत्रकों, सहायक, उप व जिलाधीशों तक ने अपनी महीना वसूली भी दुगुनी कर वसूली की। वही हाल नाप तौल निरीक्षकों से लेकर उप संचालकों, संयुक्त संचालकों, संचालक, सचिव और प्रधान सचिव से मुख्यमंत्री के पास तक भी परंपरा के अनुकूल पहुंचती रही। अब जब पेट्रोल, डीजल में मिलाकर 10 से 90 प्रश तक मिलावट करने के साथ ही आपूर्ति की पाइप में लगे लीवर से छेड़खानी करना 10 से 90 प्रश तक की नाप में मीटर पूरा दिखाकर लूटना पुराना धंधा हो चुका है। पेट्रोल-डीजल पंपों में चोरी के लिये चिप के प्रयोग के भी सैकड़ों प्रकरण उप्र, पंजाब, हरियाणा में पकड़े गये अनेकों पंपों पर छापे मारे गये। पर यथार्थ में पेट्रोल डीजल में नाप में चोरी करने के लिये चिप की आवश्यकता ही नहीं वह तो बिना चिप के भी हॉकर आसानी से कर लेता हैं क्योंकि 70 प्रश पेट्रोल पंप वाले न केवल हॉकरों को 8 घंटे की नौकरी के दौरान मिलने वाली मजदूरी का भुगतान दो शिफ्टों के प्रति पाइंट प्रति कर्मचारी रुपए 10-12 हजार का जो भुगतान कंपनियां करते हैं उसको तो वह हजम कर ही जाता है। साथ ही वह अधिकारी कर्मचारियों को ही नौकरी पर रखता है और प्रति ली. डीजल 2 रुपए, 5 रुपए अलग से जो बिक्री हो के हिसाब से अलग से वसूलता है अब बेचारा हॉकर नाप में चोरी न करे तो क्या करें, भूखा मरे। इसलिये बड़ी आसानी से मीटर सेट करने लीवर खोलने में 10-20 सेकंड में ही वह 10 से 50 प्रश चोरी कर लेता

हैं। इसी चोरी का हिस्सा बंटता है जो 70 प्रश पंपों पर प्रति व्यक्ति या हॉकर हजारों में होता है। अब अगर इंदौर में 300 पंप है तो नाप तौल 10 निरीक्षकों में से 1 के पास 30 पंप है। क्षेत्र के रुपए 5000 प्रति रुपए 1,50,000 प्रति माह की वसूली में से रुपए 50 हजार उपसंचालक को जिसने निरीक्षक को वहीं बैठाया, साथ ही उसकी वसूली कामचोरी, अचानक छापामार कर मशीने न जांच कर व भविष्य में शिकायत होने पर उसे बचाया जाये उसके हर कुकर्म पर लीपा-पोती की जाये। यही हाल प्रदेश के हर जिले के पेट्रोल पंपों का है। यह 50,000 पंपों की 30 वर्ष पुरानी है अब रुपए 10 से 20 हजार प्रति माह भी हो सकती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तौल मी. की जांच के लिए नाप तौल निरीक्षक न तो हार्डवेयर इंजीनियर है और न ही नाप तौल की इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों को जांचने के इनके पास साधन। फिर महीना वसूलते हैं। तो सारे गुनाह माफ, साथ ही गैर पंपों पर पूरे प्रदेश में लीटर से देकर प्रति किलो 300 ग्राम गैस कम दी जा रही है। इसक बारे में समय माया लगातार 10 वर्षों से लिख रहा है। परंतु सारे प्रशासनिक टुकड़खोरों को महीना मिल रहा है। आखिर जनता की जेब पर डाली जा रही डकैती का ही तो है,तो फिर हर बेईमानी भी ईमानदारी से ज्यादा है, फिर तेल कं. यथा बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, के क्षेत्रीय प्रबंधक से लेकर इन सभी कं. के मुख्यालयों से होता हुआ ये अवैध लूट का धन जो अरबों रुपए में होता है मंत्री और उजाड़ेगा, फिर मंत्री जानता है तो 5 वर्ष का मेहमान है,जितना मिल रहा है। अंटी कर वरना इससे भी हाथ धो बैठेगा। ये लूट पाट और भ्रष्टाचार नहीं होगा तो अगले चुनाव लड़ने के लिए धन की व्यवस्था कहां से होगी? इसलिये जो मिलता है,मिलने दे, खुशी न दिखा, विवाद न कर, जनता लुटती है तो लूटने दे।

अब मिलावट के संबंध में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आपको 58 आवंटन का पेट्रोल मिलना चाहिये जो पिछले 40 वर्षों से जनता को नहीं मिल रहा परन्तु पैसा 58 आवंटन का लिया जाकर मात्र 38-40 का पेट्रोल आपूर्ति कर रही थी भारत सरकार नवरतन तेल कं. सन् 2005 तक पर जबसे सारी सरकारी कं. आई ने अटल सरकार के नवरत्न स्व. प्रमोद महाजन ने पेट्रोलियम मंत्रालय संभाला था। सारी सरकारी कं. अंबानी के रिलायंस रिफायनरी की विपणन कं. बनकर गई और 30-32 आक्टेन का पेट्रोल 4 गुनी कीमत पर बिकवा रही है। इसके बाद भी चैन नहीं पड़ा तो पंप मालिकों ने वर्षों तक पेट्रोल में 60 से 90 प्रश मिट्टी का तेल और सॉल्वेंट मिलाकर जो गुजरात से सीधे और 30 प्रश टैंकर राजस्थान और महाराष्ट्र से आकर मिलाये जाते रहे। कांड में रुपए 650 करोड़ की विक्रय कर चोरी पकड़ी भी गई, मामला सीबीआई को भेजा गया और मोटा लेन-देन कर उन जालसाज सीबीआई वालों ने आसानी से यह कहकर मामला समाप्त कर दिया कि मोल बुक जरूर किया परन्तु माल की आपूर्ति ही नहीं की गई तो काहे की वाणिज्य कर की चोरी और कैसा केस, कहकर प्रकरण का खात्मा लगा दिया। जबकि हर दिन मप्र के विभिन्न नगरों के पेट्रोल पंपों पर 2000 से ज्यादा टैंकर भास्कर लिखकर आपूर्ति करवाते रहे। इस बात की समय माया ने 2004 में भी उठाया था कि 500 टैंकर सालों व अन्य पेट्रोलियम तरल मप्र में रुपए 500 प्रति टैंकर चुकाकर घुस रहे थे। तो आखिर माल कहां जा रहा था। कई बार परिवहन विभाग वालों ने भी टैंकर पकड़े पर भास्कर लिखे होने से हर कोइ बर्र के छत्ते में हाथ डालने से बचता रहा और जनता मनचाही कीमत देकर भी लूटती रही। समय माया में लगातार प्रकाशित करने के बाद जिलाधीश सुलेमान जो उस समय इंदौर के प्रभाव में तेल टैंकर खाली कराने से पूर्व उसकी गुणवत्ता जानने के लिए सारे खाद्य निरीक्षकों की ड्यूटी पेट्रोल पंप पर लगा दी थी जो टेंकर खाली होने से पूर्व लगाए जाते थे सील और गुणवत्ता की जांच करने पर ही भूतल के टैंकरों से मिलाते थे पर बात में ऐसे साइलेंट कटिंग कर भी रुपए 10000 निरीक्षकों को देखकर मिलाने जाने लगे और बाद में वह व्यवस्था ध्वस्त हो गई वर्तमान में महाभ्रष्ट फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा खाद्य नियंत्रक आर.सी. मीणा भी जो पूर्व में 15 वर्ष से ज्यादा समय तक निरीक्षक के रूप में पदस्थ रह चुका वसूली में ही व्यस्त रहता है पेट्रोल पंप डीजल पेट्रोल की गुणवत्ता जांचने के लिए वर्षों से नहीं लिए जबकि 50 रुपए पेट्रोल पंप मिलावटखोरों 99 प्रतिशत जनता को 20 से 40 % माल कम देते है इसीलिए जालसाज पेट्रोल पंप वाले नापतोल निरीक्षक को महीना बांटते हैं।

दूसरी तरफ निरीक्षकों का कहना है कि हमने अपने हाथ 4 नमूनों में से दो में 30 से 70 प्रश मिट्टी का तेल मिलाकर भी भेजा जाता तो भी पेट्रोल-डीजल व गैस की गुणवत्ता सही बताई जाती है। मप्र में नापने की प्रयोगशाला 70 वर्ष बाद भी नहीं बन सकी है। सारी प्रयोगशालायें सरकारी तेल कं. की, विक्रेताओं को क्यों बदनाम करेगी। इसलिये नमूनों पर अमानक होने के बाद भी मानक बताकर पंप मालिकों को बचा लेती है। फिर जनता तो लुटने के लिये ही पैदा हुई हैं हम नहीं लूटेंगे तो दूसरा कोई लूटेगा। इसलिये

मप्र सड़क परिवहन निगम शुरू नहीं सर्वोत्तम न्यायालय और केन्द्र सरकार के आदेश के बाद भी शुरू नहीं किया

मु.मं. चौहान के साथ नेताओं की बसें और निजी बसों का मोटा महीना सबको

हर शहर की मुख्य सड़कों अनेकों बस स्टैंड निगम की संपत्तियों की नीलामी की तैयारी

मप्र सरकार को न केवल केन्द्र सरकार वरन सर्वोच्च न्यायालय भी पिछले वर्षों में अनेकों बार अनेकों याचिकाओं के निर्णयों के माध्यम से आदेशित कर चुका है कि मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम को पुनः शुरू किया जाये, पर मप्र सरकार के महाभ्रष्ट, लुटेरे डकैत मु.मं. शिवराज व अन्य मंत्रियों के साथ मप्र शासन के मुख्य सचिव और परिवहन सचिव व मुख्य आयुक्त परिवहन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, जो कि म.प्र. में सड़क परिवहन निगम की बसें नहीं चलाई जा रही, जबकि इसके विपरीत हर महानगर में शासन के जालसाज जिलाधीश आयुक्त, महापौर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उप जिलाधीशों ने मिलकर लूट के लिये अपनी फर्जी कं. जिनका सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लाभ-हानि खाता और चिट्ठा तक नहीं बनता है। एक तरफ जेएनआरयुएन का रुपए 1250 करोड़ से ज्यादा से इंदौर में बीआरटीएस पर भी बर्बाद किया, तो दूसरी तरफ बसें ठेकेदारों की उस बीआरटीएस पर ठेकेदारों की चलाई जा रही है। उन बसों का मिला पैसा भी सैकड़ों करोड़ में हजम कर लिया गया, दूसरी तरफ सारे कर्मचारी कंडक्टर ड्राइवर सब ठेकेदारी पर नौकरी कर रहे हैं। जिन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा और कार्य भी 10 घंटे से 14 घंटे लेकर घोर शोषण किया जा रहा है। इस लिमिटेड कं. का पंजीयन प्रमाण पत्र, व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र, चिट्ठा, लाभ-हानि खाते का भी विधि अनुसार न तो प्रकाशन किया गया और न ही वहां बैठे शूकरों की फौज किसी को आज तक सूचना अधिकार में देती हैं। जबकि प्रबंध मंडल में स्वयं जिलाधीश, आयुक्त, महापौर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधीश जो कई वर्षों से संदीप सोनी हैं, होते हैं चूंकि सभी सरकारी पदों पर है। तो दूसरे किसी लाभ के पद पर कार्य करना ही इनको असंवैधानिक बना देता है, इसके विपरीत ये सब इस एआईसीटीसीएल में दुगुने-तिगुने किराये पर पूरे मप्र में और बाहर तक बसें चलकर मोटा लाभ की बंदरबांट में जुटे है। यही हाल मप्र के सभी बड़े जिलो के हैं। जिसमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन आदि हैं। वर्षों से संवैधानिक पदों पर बैठ इस अवैधानिक कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। बेशक कमाई का मोटा पैसा, मुख्य मंत्री तक पहुंचाकर स्वयं भी हजम किया जा रहा है। इसके विपरीत ये जालसाज मुख्यमंत्री शिवराज जो कदम पर, घोर भ्रष्टाचार में लिप्त सिद्ध हो जाने के बाद भी 11 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर डटा हुआ है, और खुले में सर्वोच्च न्यायालय के और केन्द्र सरकार के निर्णयों की घोर अवमानना करते हुये मप्र राज्य परिवहन निगम की शुरूआत इसीलिये नहीं कर रहा ताकि एक तरफ निजी बस मालिकों से परमिट के नाम पर तो दूसरी तरफ मप्र टूरिज्म की, बड़े-बड़े नगरों में खुले इन जालसाजी पूर्ण कं. के माध्यम से जनता को लूटा जा सके, क्योंकि परिवहन निगम के शुरू होते ही उसकी पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर बड़ी डिपो की जमीनों, भवनों, वर्कशॉप की जमीनें, बस अड्डों की जमीनों को बेचकर अरबों रुपए धन हड़पने का मौका तो समाप्त होगा ही,फिर ये सारी कं. जो शहरीय विकास केन्द्रीय व राज्य मंत्रालयों से हजारों करोड़ की धन हड़प रही हैं। बंद हो जायेगा, दुगुने तिगुने किराये वसूलने की लूट खत्म। निजी बसों से परमिटों की आय समाप्त हो जायेगी, आखिर ये जालसाज शिवराज 12 वर्ष से तानाशाह बन सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र सरकार के आदेशों-निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुये न केवल प्रदेश के यात्रियों जो लगभग बसों के माध्यम से 80 लाख यात्रि प्रतिदिन करते हैं। उनका शोषण कर उनसे मनचाही लूट करवा रहा है, तो दूसरी अरबों रुपए की लूट हर महीने करवा कर दोनों हाथ धन बटोर रहा हैं।

निजी बसों के तांडवों के चलते और अधिकृत परिवहन निगमों बस अड्डों की जमीनों को भूमाफियाओं के इशारे पर कब्जे करवाकर प्रदेश के हर नगर को जगह-जगह गाड़ी अड्डों में परिवर्तित कर रहा है। अकेले इंदौर में ही सौ से ज्यादा बसों के खड़े होने के अड्डों में परिवर्तित किया जाकर एक और यातायात बाधित करते हैं तो दूसरी तरफ यात्रियों को भी निजी बसों को पकड़ने के लिए शहर के अलग-अलग कोनो पर जाना पड़ता है। इससे अनावश्यक धनहानि और समय की बर्बादी होती है। निगम के बस अड्डों पर निगमों और पालिकाओं के प्रबंधन के चलते सुविधायें तो दूर असुविधायें और नगर निगम, पालिकाओं की लूट और अरबों रुपए के भ्रष्टाचार से धन हजम किया जा रहा है। जिसे देखने सुनने वाले भी कोई नहीं दिखता। आखिर पूरे देश में हर राज्य की परिवहन सेवायें चल रही है। केवल मप्र को छोड़कर पूरे देश में मप्र ही इकलौता ऐसा राज्य है। जहां पूरे राज्य के परिवहन निगम को मप्र के भूतपूर्व मु.मं. दिग्गी दानव से लेकर शिवराज ने और उके परिवहन मंत्रालय के धूर्तों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर अपनी व नेताओं की बसों के लिये लूट का मैदान बना दिया। जिसे तत्काल पुर्नजीवित किया जाना चाहिये।

साप्ताहिक समय माया

जिलाधीशों, मु.का.अ., जि.शि.अ. से लेकर मंत्री, सचिव, मु.मं. तक देते हैं, लूट की पूरी छूट

शासन ने शिक्षा को बना दिया डकैतों का अड्डा, फिर भी स्तरहीन शिक्षा

गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय भूखा रहे, उठाता है, शिक्षा का खर्च, शिक्षा में बाल मंदिर से लेकर उच्च शिक्षा तक माफियाओं के चंगुल में, जानबूझकर शासकीय शिक्षकों को वर्षभर झोंके रखते हैं, उल्टे-सीधे अन्य शास. कार्यों में, दैनिक मजदूरी से कम वेतन पर, ताकि शासन अधिकारियों को मोटा कमीशन के साथ भोग प्राप्त हो, और जनता निजी संस्थाओं की लूट का शिकार हो

शासन और प्रशासन के अधिकारियों ने शिक्षा जैसे अत्याधिक गंभीर विषय को भी सफेदपोश माफियाओं का अड्डा बना दिया, यह केवल मप्र का ही नहीं पूरे देश का है जिसमें न्यायिक प्रक्रिया भी आंखें मूंदे बैठे, पालकों का वर्तमान और आने वाली पीढ़ी का भविष्य चौपट कर रही है। देश का प्रधानमंत्री मोदी स्वयं तो 8-10वीं पास भी नहीं, कोरी भाषणबाजी कर पूरा देश नीलाम करने पर तुला है। जब सरकार केन्द्र की पेट्रोल डीजल और गैस के साथ अन्य वस्तुओं व सेवाओं पर 2 प्रश शिक्षा उपकर पिछले 15 वर्षों से वसूल रही है। डीजल, पेट्रोल की चौगुनी कीमत वसूल रही है तो कम से कम 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क प्रदान करें, परंतु भगवा पाखंडी की भुखेरा जन पार्टी तो केन्द्र से लेकर राज्यों तक एयर इंडिया, रेलवे, संचार निगम से लेकर गांवों, तहसीलों में बने सरकारी चिकित्सालयों और स्कूलों तक को बेचने और ठेके पर देने पर तुली होकर जनता और भावी पीढ़ी को गिद्धों के हाथों में सौंपने पर तुली है। चाहे वो केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो या राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों में, केन्द्रीय विद्यालय हों या स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्रालय सब में दलालों का और माफियाओं का साम्राज्य है। जहां पर बैठे बाबुओं, अधिकारियों से लेकर शिक्षा,सचिव, प्रधान सचिव और मंत्री घोर लालची और रंगीन मिजाज है। इसलिये निजी शिक्षण संस्थानों जो इन्हें मोटा धन, सुरा सुंदरी समर्पिक कर सारे उल्टे-सीधे कार्य करने, भवन निर्माण, शुल्क, महंगी निजी संस्थानों की मोटी और स्तरहीन पुस्तकें,कापियां, गणवेश, खेलकूद अन्य गतिविधियों आदि के अनेकों शुल्क वसूलते हैं। पर मान्यता देने वालों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय निरीक्षण करने व अन्य देखरेख करने वाले शासकीय अधिकारियों की भ्रष्ट, लोलुप फौज, जिसमें जिलाधिकारी, मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उपजिलाधीश व अन्य उपरोक्त कार्यालयों के बाबू चपरासी जो दलालों की कठपुतली होते हैं। चुपचाप अपने स्वार्थ पूरे कर, देखते रहती हैं। जबकि 90 प्रश स्कूलों के पास न तो समुचित कमरे होते हैं, न खेलने का का मैदान न पर्याप्त शिक्षित शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्राचार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, यहां तक कि स्वच्छ पानी, पीने की व्यवस्था तो बड़े-बड़े स्कूलों में भी नहीं होती। न साफ स्वच्छ मूत्रालय और शौचालय बच्चों या विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार नहीं होते। फिर भी दिखाने, पालकों को लूटने के लिए नर्सरी, केजी-1, 2 से लेकर 5वीं कक्षा की पुस्तकें व कॉपीयां निजी लेखकों और प्रकाशकों की रुपए 3 से 5 हजार की मात्र मोटा कमीशन जो 40 से 60 प्रतिशत तक थोप दी जाती है। जितने विषय की पुस्तकें खरीदवायी जाती है। वो किसी एक ही विक्रेता के पास उपलब्ध होती है। जिसकी पर्ची के साथ विक्रेता का नाम बता दिया जाता है। ताकि कमीशन लेन-देन में आसानी हो वही हाल ड्रेस का भी होता है। मोटे कमीशन की वसूली के लिए हर वर्ष पुस्तकें व ड्रेस बदल दी जाती है। ताकि पुरानी पुस्तकों और घर के अपने भाई बहन भी न कर सकें। हालात ये हैं कि देश की आबादी के 40 प्रश मजदूर, किसान वर्ग, जिनकी कुल आय रुपए 20,000 मासिक से ज्यादा नहीं, बच्चों की शिक्षा के नाम पर स्वयं भूखा रहकर मुश्किल से बच्चों की निजी स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर है, इसके विपरीत इतनी लूट के बाद भी निजी संस्थाओं में विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों और हर शहर में खुल रहे निजी विश्वविद्यालयों तक में पढ़ाने, वाले विशेषज्ञ शिक्षकों, अध्यापकों और प्राध्यापकों का घोर अभाव हैं परिणाम 8वीं, 10वीं के बच्चों को लिखना, पढ़ना नहीं आता। तकनीकी महाविद्यालयों से विश्व विद्यालयों से निकले विद्यार्थियों की डिग्रीयां बी.ई., बी.टेक की बाबु बनाने लायक भी नहीं छोड़ती, जबकि अपनी संस्था की बदनामी और व्यवसाय ने की जेड वो धड़ल्ले से पास करते जाते हैं।

शासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से जिलाधीश पढ़ाने की अपेक्षा अन्य कार्य करवाया करते है। पूरे वर्षभर, कभी जनता की, कभी जानवरों, कभी तालाबों, कुयें आदि की गणना, कभी सर्वे में जोत कर, जानबूझकर शिक्षा सत्र बिगाड़ने पढ़ाई के समय ही वोटर आईडी, आधार आदि से उलझाकर पूरा समय बर्बाद करते हैं। ताकि शासकीय स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद होने के डर से माता-पिता भूखे रहकर भी निजी शिक्षण संस्थाओं में भेजने के लिये मजबूर रहें, बदले में शासन-प्रशासन में बैठे अधिकारी कर्मचारी निजी संस्थाओं से भी रकम वसूलते रहें। दूसरी तरफ अधिकांश निजी संस्थायें, नेताओं, बड़े अधिकारियों, जालसाज माफियाओं को ही होती हैं। तो उनमें हाथ डालने से जिला शिक्षाधिकारी, जिलाधीश संयुक्त, संचालक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आदि-आदि कतराते हैं। इससे इन शिक्षा माफियाओं का तन, मन, धन से शोषण करने के बाद भी छात्राओं का यौन शोषण तक करते है। बात जब शिकायत तक पहुंचती है तो ये शिक्षा माफिया, गुंडे मवालियों को भेजकर डराते-धमकाते हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकरण पेशेवर पाठ्यक्रमों यथा चिकित्सा, अभियांत्रिकीय, विज्ञान, कृषि महाविद्यालयों में बैठे लंपट व्याख्याता, परीक्षा अधीक्षकता खूब करते हैं। जिसके सैकड़ों मामले सतह पर आकर कहर बरपाते हैं।

शिक्षा माफिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण मप्र में हुआ व्यापम कांड है। जिसमें हत्याओं, आत्महत्याओं की 277 घटनाओं हुई और 1050 से ज्यादा लोगों ने जेलों की जिंदगी जी, सारे बड़े मगरमच्छ जिसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल था, सर्वोच्च न्यायालय केन्द्रीय भाजपा जांच अर्थात सीबीआई द्वारा बचा लिया गया। साथ ही कोचिंग रूपी सारे आधार स्तंभों ने भी करोड़ों रुपए खर्च करके अपने आपको बचा लिया। जबकि व्यापमं कांड और दलाली की शुरूआत, दलाली और प्रवेश परीक्षा पास कराने का खेल की शुरूआत वहीं से होती है। 1980 से चल रहा ये कांड जिसका अंतरप्रांतीय माफिया श्रीकृष्णा कोचिंग के यादवों का खानदान है। जिसका 1980 से पूरे मप्र, उप्र, राजस्थान, दिल्ली व अन्य प्रदेशों में जाल फैला हुआ था। उस पर आज तक नहीं आई, वही हाल इंदौर की गुप्ता, आकाश व अन्य कोचिंग संस्थानों का भी था। आखिर इन बड़े दलालों पर एसटीएफ, लोकायुक्त, एटीएस, सीबीआई की जांच में लपेटे में क्यों नहीं लिया गया।

जबकि दूसरी तरफ सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर बहानों की सूची थमा दी गई। जिला शिक्षाधिकारी इंदौर, देवास, उज्जैन के विरुद्ध अपीले की गई। जिसमें उज्जैन ने तो जानकारी भिजवाई आधी अधूरी, परंतु देवास जिला पंचायत ने तीन बार सुनवाई में बलवा दो-तीन घंटे खड़ा करने के बाद भी मु.का. अ. की अनुपस्थिति मं अति. मु.का.अ. द्वारा अपनी जालसाजी दिखाते हुए उसे बचाने के लिए समय दे दिया। इंदौर के जिला पंचायत में बैठे हरामखोरों ने अपीलों की सुनवाई ही कई वर्षों तक नहीं की। यहां के जिला पंचायत कार्यालय में अधिकांश मु.का. अभी भ्रष्ट और जालसाज ही बैठाने के साथ, वर्षों से जमे महाभ्रष्टों को भी महीना मिल जाता है, तो वो भी कुंडली मार के बैठ जाते हैं। यही हाल शासकीय महाविद्यालयों का भी है।

प्याज नीलामी में रुपए 300 करोड़ का भ्रष्टाचार

खुशी इस बात की है किसान 4-5 फसलें ले रहा है। दुख इस बात का, फसल का मूल्य न मिलने से आत्महत्या करने का सिलसिला बढ़ रहा है। इंदौर खा. नि. मीणा का फर्जी जाति प्रमाण पत्र की वर्षों से लंबित जांच कब समाप्त होगी

पूरे मप्र में कृषि व उद्यानिकी विभाग के कृषि विस्तार अधिकारियों का जाल ग्राम पंचायत स्तर तक फैले होने के बाद भी, कृषि विभाग की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते गांवों के किसानों ने क्या बोया और कितनी आवक समावित है। इसके समकों का संकलन समय पर न किये जाने से कृषि उत्पादनों के विपणन की उचित व्यवस्था समय पर नहीं की जाती। जबकि भारतीय कृषि मंत्रालय से लेकर राज्यों के कृषि मंत्रालयों तब बड़े-बड़े दावे किये जाते हैं। पिछले 10 वर्षों से मप्र का मुख्यमंत्री शिवराज कृषि को लाभ का धंधा बनाने की करते 3 चुनाव जीत गया परंतु कृषि को लाभ का धंधा बनाने की वो दूर किसान समय पर कृषि के लिये गये ऋणों के समय पर न चुका पाने के चक्कर में हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं को नहीं रोक पा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा की केन्द्र व राज्यों में बैठी सरकारें अपने कुकर्मों, भ्रष्टाचार और नाकामियों को छुपाने, प्रचार-प्रसार माध्यमों को सच न छापने, प्रकाशित प्रसारित न करने के लिये हर दिन रुपए 1500 करोड़ से 3000 करोड़ के 5 से 8 पेज के विज्ञापन समाचार पत्रों और टीवी चैनलों को 60 मिनिट से 120 मिनिट के विज्ञापन जरूर बांट सकती है। जबकि अपने चुनावी चंदे देने वाले पूंजीपतियों के रुपए 50 लाख करोड़ के ऋण माफ कर सकती है। रुपए 50 लाख करोड़ों से ज्यादा मोदी की विदेश यात्राओं में बर्बाद कर सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज पंडितों के कहने पर रुपए 2000 करोड़ से ज्यादा नर्मदा यात्रा पर बर्बाद कर सकता हैं इसके विदेशों में विज्ञापन के होर्डिंग लगवा सकता है। रुपए 40000 करोड़ जो वाणिज्य कर से प्राप्त होता है। 60 प्रश पैसा प्रचार-प्रसार में बर्बाद कर सकता है, पर रुपए 1000 करोड़ के किसानों के ऋण, माफ नहीं कर सकता।

बेशक सिंचाई सुविधायें बढ़ने से प्रदेश का किसान वर्ष भर में 4-5 फसलें लेने लगे हैं हालात ये हैं कि आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों जिनसे कभी सरकारें बदल जाया करवाती थी। दो-पांच रुपए किलो में खरीददार तो दूर, किसानों को खेत से मंडी लाना भारी पड़ जाता है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भेड़ चाल चलने वाले किसानों ने भारी मात्रा में जबकि गर्मी में मूंग व अन्य फसलें ली जा सकती थी। भारी मात्रा में प्याज का उत्पादन किया। सरकार को खबर थी, सरकार को मई के अंतिम सप्ताह से ही इसकी खरीदी और पूरे देश की मंडियों में नीलामी की व्यवस्था 15 जुलाई तक के करने के निर्देश जारी करने चाहिये थे, परंतु नर्मदा यात्रा में अपने पाप धोने व ढांकने में व्यस्त शिवराज के निर्देश जारी करने चाहिये थे, जब दंगे प्रदर्शन और झगड़े होने शुरू हो गये। रुपए 8 प्रति किलो में खरीदने की घोषणा हुई और खाद्य व नागरिक आपूर्ति के मालवा के हर जिले के खाद्य नियंत्रकों और जिला खाद्य अधिकारियों को सक्रिय किया गया, साथ ही रुपए 2 प्रति कि. तक तत्काल बेचने की न्यूनतम दरें निर्धारित की गई जबकि न्यूनतम रुपए 3 प्रति किलो की दर निर्धारित की जा सकती थी, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आसम, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा के व्यापारियों के हाथ रुपए 4 से 6 प्रति किलो में ही गया। पर क्षेत्रीय व्यापारियों का ही पूल बनाकर जिसमें बड़े-बड़े किसान भी शामिल थे एक ही किसान ने तीन बार अपना ही प्याज बेचकर इंदौर, देवास, धार, शाजापुर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर आदि जिलों में जालसाजी पूर्ण तरीके से सरकारी खजाने को रुपए 300 करोड़ की चोट पहुंचाकर जिला खाद्य अधिकारियों से निरीक्षकों तक ने मोटी कमाई की। बेशक संरक्षण मोटे हिस्से के साथ जिलाधीशों का भी था। यदि किसान के कुल उत्पादन और बिक्री के सारे तथ्य इकट्ठे किये जाये, बुआई और उत्पादन के रकबे के अनुसार तो मालूम पड़ेगा कि उत्पादन से दुगुनी खरीद हुई, एक ही प्याज कागजों पर कई बार खरीदकर वहीं के वहीं रुपए 2.15, 2.30, 2.50 में बिक्री दिखाकर, अलग-अलग खातों में पैसा हस्तांतरण किया जाकर रुपए 2 से 4 तक प्रति किलो कमीशन हजम किया जाता रहा। इंदौर में ही फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे आरसी मीना ने भी रुपए 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। यह पूर्व में भी 15 वर्ष तक इंदौर में जमा रहा था। मात्र लूटो और लुटाओ के दम पर। इसके जाति प्रमाण पत्र की जांच जारी है। पर राज्य जन जाति आयोग के सदस्य भी मोटा कमीशन कर ऐसी जांचे वर्षों तक दबाये रखते हैं। और आरोपित आराम से आरक्षण का लाभ लेकर लूटपाट करते हुये लूटता-लुटाता सेवानिवृत्त हो घर चला जाता है। मु.मं. शिवराज ने मानार कि एक ही ब्याज कई बार बिका। आवक से दुगुनी खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ, फिर वही जुमला, भ्रष्टों को बख्शा नहीं जायेगा, पर जिसकी कॉलर क्या पूरी कमीज के साथ तन, मन भी भ्रष्टाचार और जालसाजी में तर-बतर हो वो क्या किसी को बख्शेगा और पकड़वायेगा। बेशक प्याज खरीदी कांड में रुपए 300 करोड़ के भ्रष्टाचार में से रुपए 50 करोड़ तो मु.मं के हाथ भी आये ही होंगे। अब किसानों का आत्महत्या का रोग तो सदियों पुराना है। भले ही किसान कर्जे से आत्महत्या कर रहा हो परंतु सरकारी आंकड़े तो प्यार, मोहब्बत, बेवड़े होने, जुआ, सट्टा की आदत, बीमारी के कारण, पति-पत्नी के झगड़ों में ही आत्महत्या कर परंपरा का ही निर्वहन कर रहे हैं।

इंदौर में न.घा. वि.प्रा. संभागीय कार्यालय खोला जाये

मु.मं. व प्र.स. के लिए दुधारू गाय, लूट भ्रष्टाचार से धनार्जन

रुपए 76 लाख के कार्य में रुपए 85 करोड़ का भुगतान बिना मशीनों के अग्रिम भुगतान ढाई वर्ष का कार्य 5 वर्ष में में भी पूरा नहीं। पुर्नवास में भी हजारों करोड़ का घोटाला

समय माया नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में मु.मं. व प्रधान सचिव के कार्यालय से लेकर नीचे संभागों, उपसंभागों में होने वाले भ्रष्टाचार और ठेकेदारों के साथ मिलकर जन-धन की लूटखसोट के बारे में लगातार पिछले 30 वर्षों से नजर रख, 17 वर्षों से लगातार प्रकाशित कर रहे हैं। परंतु पूर्व मु.मं. अर्जुन सिंग के समय से शुरू हुई इन परियोजनाओं में वर्तमान शिव भ्रष्ट राज चौहान तक लूट का तांडव अनवरत चल रहा है। चाहे वह जबलपुर का रानी अवंतिबाई सागर या बारगी बांध हो या मान जोबट, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर बांध के साथ सैकड़ों किमी लंबी नहरों के निर्माण रखरखाव से लेकर वर्तमान में सरदार सरोवर में चल रहे सबसे बड़े विस्थापन में तृतीय चरण में 193 गांवों और निसरपुर तहसील को खाली करवाकर लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों को मुआवजे के बाद बसाना है, जबकि विस्थापितों को झोपड़ी और मकानों का मुआवजा तो बांटने की पुष्टि विस्थापित के साथ सरकार भी कह रही है। परंतु कृषि भूमि के मुआवजे की मांग पर शासन न केवल चुप है वरन मीडिया जिसमें दृष्य, श्रव्य, दूरदर्शनी श्रृंखलायें और मुद्रित प्रसार माध्यमों के भुखेरे श्वानों ने पूर्णतः चुप्पी साध रखी है। सभी बड़े माध्यमों को सरकार मोटा जनधन खर्च कर हर दिन 4 पेज विज्ञापनों के साथ मुंह पर ताले लगाये हुए है। न केवल देशी माध्यमों पर वरन विदेशी माध्यमों को भी पूर्ण रूप से खरीदा जा चुका है। यहां तकनीकि गूगल अर्थ पर भी इन क्षेत्र निसरपुर तहसील और उसके गांवों को भी नक्शे से गायब करवा दिया गया है। विस्थापन के ठिकाने भी गूगल अर्थ से गायब हैं जो कि बिना मोटी रकम दिये गायब नहीं करवाये जा सकते जो कि रुपए 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक हो सकती है जो नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास की कहानी स्वयं बता रहा है। इस विस्थापन के कांड में रुपए 5000 करोड़ से ज्यादा हजम किया जायेगा, टेंट, तंबू, बिजली, पानी, शौचालय, भोजन आदि की व्यवस्था में इस संबंध पुर्नवास आयुक्त कार्यालय से लेकर, क्षेत्रों में कार्यरत पुर्नवास हेतु लोक निर्माण की शाखा में भी सारे भ्रष्ट और जालसाजों को ही पदस्थ किया है। जिसमें से एक है जो कि लोकायुक्त में आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्त में आय का.यं. आनंद प्रकाश राणे और उसका ठेकेदार भाई विजय प्रकाश राणे, इनके साथ ही यह कार्य मप्र लोक निर्माण को भी सौंपा गया है। धार जिले के का.यं. आर के जैन नई बनने वाली कॉलोनियों के न.घा. के लोक निर्माण के अंतर्गत पुर्नवास का कार्य चलाया जा रहा है। 193 गावों के पुर्नवास के लिए अस्थाई टीन शेडों में बिजली, पानी, निवास आदि के लगभग 1 लाख लोगों की व्यवस्था के नाम पर आवंटित लगभग रुपए 200 करोड़ में से कार्य पटांग तरीके से करवाया जाकर मोटा धन हड़पा जा रहा है। दूसरी तरफ नर्मदा बचाओं आंदोलन के कार्यकर्ताओं की मांग है कि स्थाई पुर्नवास किया जावे तब ही गांवों को खाली किया जा सकेगा, जबकि इस सरदार सरोवर की आधार शिला 1961 में स्व. जवाहर लाल नेहरू ने रखी थी, पुर्नवास तब ही से निश्चित था तो 56 वर्षों में मप्र सरकार के लोक निर्माण, नर्मदा घाटी विकास विभाग, जिलाधीशों धार, झाबुआ, बड़वानी ने क्या किया। फिर मप्र के मुख्यमंत्रियों ने तो केवल गंभीरता से इसकी आड़ में केवल क्रीम चाटी परंतु गंभीरता से पुनर्वास की तरह ध्यान ही नहीं दिया गया अब जबकि नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री गुजरात से है तो अपने प्रदेश की जनता को पेयजल के साथ सिंचारू और उद्योगों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति कर मप्र की जनता की बलि चढ़ायेगा ही पूरी डूब मप्र की होगी, जिसमें 57 प्रश बिजली देने का वादा है। बाकी बांध से निकलने वाली दांयी बाई तरफ की नहरों के जल से गुजरात ही सिंचित होगा और डूबाया मप्र की करीब डेढ़ लाख है. भूमि जिसमें 193 गांवों, 1 पूरी हरसूद तरह की निसरपुर तहसील 70 हजार से ज्यादा कृषि भूमि, लगभग 80000 है. से ज्यादा वन भूमि, राजस्व, पड़तत, नजूल और रहवासी क्षेत्र केवल मप्र का ही डूब में जा रहा है। देश विदेश मं इस डूब और बर्बादी के सच का हल्ला न मचे, मप्र की सरकार ओर उसके मंत्रालयों ने अरबों रुपए गूगल को बांट नक्शे क्षेत्र है. सबकुछ साफ करवा रखा है, इससे यथार्थ ही मालूम नहीं पड़े कि कहां कितना, कौन-कौन से गांव, तहसील, वन,खेत, नजूल, सड़के डूब रही है। कौन से पुर्नवास स्थल बनाये गये हैं, बिजली पानी के स्थाई व अस्थाई कैम्पों, कॉलोनियों, की क्या और कैसी व्यवस्था है ताकि भ्रष्टाचार और कुकर्मों की सरकारी बत्तमीजियों का यथार्थ क्षेत्रीय, प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर कोई न जान सके, और ये आवंटित रुपए 450 करोड़ में से रुपए दो सौ करोड़ हजम कर सके। न्यायालयों को झूठे दस्तावेज दिखाकर अपनी अवमानना और मानव सभ्यता को नष्ट करने जो सहस्त्रों वर्षों से उस क्षेत्र की नर्मदा घाटी व्यवस्था में नर्मदा के किनारे विकसित हुई थी, एक तरफ सरकार आदिवासियों के विकास और समृद्धि के वादे करती है दूसरी तरफ अपने लालच मोटी कमाई के लिए उनकी बस्तियों की बस्तियां लाखों लोगों की उजाड़ दी जाती हैं। जैसा कि पूर्व में इंदिरागांधी सागर की डूब में पुनासा से लेकर बलड़ी, हरसूद, खिड़किया, मूंदी तक बसे कोरकू आदिवासियों का जो मूल क्षेत्र था पूरी तरह जलमग्न कर दिया गया। उससे बनने वाली बिजली जो कि 51 प्रश प्रदेश की थी और 49 प्रतिशत रा. जल विद्युत निगमे की जिस पर पहला हक मप्र का था, अपने मोटे कमीशन के चलते नहीं खरीदी जा रही, इसमें में भी 50000 है.से. ज्यादा के वन और 40000 है. से ज्यादा कृषि भूमि वन व राजस्व ग्राम 150 से ज्यादा खंडवा, देवास, और हरदा के गांव डूबो दिये गये। उसमें भी लगभग क्षतिपूर्ति पुर्नवास में सैकड़ों करोड़ बिचौलिये दलालों से लेकर पटवारी, तहसीलदार, सहायक, उप व जिलाधीशों से लेकर संभागायुक्तों, मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों, प्रधानसचिवों ने हजम किया वही हाल अभी सरदार सरोवर की डूब में चल रहा है। यही कारण है कि यहां प्रमुख सचिव, उपाध्यक्ष के रूप में बैठे रजनीश बैश्य से लेकर, सदस्य अभियांत्रिकीय द्वितीय विस्तार से लेकर पुर्नस्थापना व पुर्नवास आयुक्त, रैनु पंत व अन्य सभी संचालक व उपसंचालक, वन व पर्यावरण वित्त आदि सभी में चुन-चुन कर भ्रष्टों और जालसाजों की फौज बैठाई गई है, जिन्हें वास्तविक कार्य से कम और कमाई से ज्यादा मतलब होता है। इन हरामखोर जालसाजों को जिनकी जिम्मेदारी थी कि नर्मदा घाटी की वेबसाइट पर सारी जानकारी स्वयं डालते, जानकारी तो शूकरों ने डाली ही नहीं, वरन सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर पत्रों का जवाब ही नहीं देते। दूसरे यदि अपील लगाओ तो अपीलीय अधिकारी भी उन्हें नचाने, उल्टे-सीधे जवाब देकर आवेदक को चलता कर देते हैं। वो जालसाज परिहार जिसने केवल जीवन में हरामखोरी और चापलूसी की और अभी भी इसी सदगुण के आधार पर समय विस्तार पर सभी शासकीय सुविधाओं का का लाभ उठा रहा है। वैसे भी नर्मदा घाटी के यांत्रिकीय और निर्माण में जलसंसाधन व अन्य विभागों के चुन-चुन कर सभी भ्रष्ट, जालसाज इंजीनियरों की फौज बैठाई गई है। इसलिये अपील लगाने पर सुनवाई की सूचना भी सुनवाई की तीथि निकल जाने के बाद भेजनी है फिर सारे दस्तावेजी सबूतों को दरकिनार कर अपीलें करने में ही अपनी महानता समझती है।

ऐसे ही एक अपील की सुनवाई मंडल क्रमांक 8 सनावद में अ.यं. एच.आर. चौहान ने सं. क्रमांक 21 के विरुद्ध सुनी गई, सं.यं. ने स्वीकार किया कि समय रहते का पत्र नहीं भेजा, इसके विपरीत इस जालसाज ने अपील में निःशुल्क का और क्षतिपूर्ति आदेश देने की अपेक्षा सं.यं. गुप्ता सं. क्रमांक 21 से पुरानी तारीख में पत्र जारी कर व शुद्ध की मांगकर ली गई यही हाल उसके दिये पत्र और उसकी अपील की सुनवाई में अपने अधीनस्थ का.यं. को बचाने के लिए पुरानी तीथियों में समय देकर जवाब देकर बचाने की कोशिश की जा रही हैं। जिसमें सं.क्र. 23 जो भोपाल मुख्यालय के अभियांत्रिकीय विभाग में वाहनों के किराये पर लिये जाने अन्य सामानो की खरीदी से लेकर नई दिल्ली स्थित नर्मदा घटी के विश्राम गृह में जहां अरबों रुपए की हर महीने धुलाई, भोजन, रखरखाव के लाखों रुपए के फर्जी बिलों के भुगतान के लिए कुख्यात हैं। स.क्र. 21 तो अपने सनावद की कॉलोनी के, ओंकारेश्वर के विश्राम गृह में लाखों रुपए के रखरखाव, फर्जी लाखों की, मरम्मत, सुधार कार्यों के भुगतान 1990 से अभी तक करता आ रहा है के साथ ही बीके बिहानी, कर्ण सिंग व अन्य ठेकेदारों को दिये खुदाई, कांक्रीट के मूल अनुबंध की राशि के दुगुने से लेकर तीन गुने तक भुगतान करवाने के बाद भी ढाई वर्ष का कार्य 12 वर्ष में भी पूरा नहीं करवाने के लिये कुख्यात रहा है। वही हाल खंडवा कं.स. क्रमांक 13 और पुनासा व नर्मदा पुरवा के 25 व 28 नंबर संभागों का भी है। यहां बैठा का.यं. जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करते हुए 10 वर्षों से ज्यादा समय से मोटी कमाई और नीचे से ऊपर तक बंटाई के चलते कुंडली मारे बैठा है। इंदिरा सागर नहरों में बैठा मु.अ. राजन रोहित भी महाराष्ट्र निकम्मा हरामखोर भी सूचना के अधिकार को पत्रों का जवाब देने तो दूर ये शूकर अपीलें भी पी जाता है। कार्यालय में बैठेगा तो भी बस मोबाइल पर उन्हें सीधे वीडियो देखा करेगा परंतु आवेदक को मिलने से भी मना कर देगा। यही हाल नागोद, सतना, मंडला के संभागों के साथ रा.आ.बा. सागर नहरों बांध में बैठे, मु.अ., अ.यं. व सभी का.यं. के भी हैं। सतना सं. में रुपए 76 लाख के ढाई वर्ष के कार्य का रुपए 8.5 करोड़ भुगतान कर दिया गया, परंतु 5 वर्ष में भी कार्य पूरा नहीं हुआ। परंतु शूकरों की फौज के सरदार रजनीश बैश्य, सदस्य अभि. 1 शिवहरे से लेकर किसी के माथे पर शिकन तक नहीं आई, क्योंकि सबने फर्जी भुगतान में बंदरबांट की थी। यही हाल निचली नर्मदा परियोजना में भी धड़ल्ले से चल रहा है। नर्मदा गंभीर परियोजना का कार्य धामनोद, मंडलेश्वर और बड़वाह से चलाया जा रहा है। जबकि 80 प्रश परियोजना का हिस्सा इंदौर जिले में लगता है साथ ही यही हाल नर्मदा क्षिप्रा का भी है। इस दृष्टिकोण से न.घा. का एक संभाग धामनोद से इंदौर में या इंदौर में एक नया संभाग खोला जाना चाहिए। पर नर्मदा घाटी अंधेर नगरी चौपट राजा बन चुका है।

व्यक्तिगत स्तर पर अधिकारी-कर्मचारी करते हैं उपयोग, कार्यालयीन स्तर पर उपयोग क्यों नहीं?

उपग्रह व गूगल धरती के फोटो से बचाया जा सकता है अरबों रुपए

नागरिक, वन, खनन माफिया, अतिक्रमण, आपूर्ति आदि पर निगरानी के लिए अत्यधिक उपयोगी

देश के भाजपाई पाखंडी मूढ़ नेता यथार्थ भूखेरा जनपार्टी का गिरोह केवल नोंचने खाने और मोटे कमीशन पर निगाह रख पूंजीपतियों के इशारों पर नृत्य करता है। फिर उसके उच्च शिक्षित, प्राध्यापक स्तर के नेताओं को, सड़क के निहायत छिछोरे नेता, जिनका पूरा जीवन पैर छूकर अपने दुष्कर्मों पर पर्दा डाल जिसमें चाहे मोदी हो या अमित शाह से लेकर राज्यों तक बैठी पूरी लॉबी के अधिकांश नेता, विधायक, मंत्री, सांसद या केन्द्र के मंत्री हो, वर्तमान के जालसाजों, गुंडों, अपराधियों ने दरकिनार कर सत्ता हथियाई और तानाशाहों की तरह शासन कर रहे बिलकुल स्वयं, आईएएस अर्थात इंडियन एब्यूसिंग सर्विस या भारतीय प्रताड़ना सेवा बन नाचते हैं क्योंकि स्वयं की चवन्नी भर की अक्ल और सोच नहीं। जैसा वो नचायें नाचना ही पड़ेगा। क्योंकि छल, बल, दल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बनना आसान हो सकता है पर सत्ता चलाना बच्चों का खेल नहीं।

इसके विपरीत भारतीय प्रशासनिक वन सेल, आय या राजस्व सेवा, पुलिस, सेवा में परीक्षायें पास करके आये अधिकारी अपनी शक्तियों और कानून के दुरुपयोग करना है। ये इसके खिलाड़ी होते हैं। इसलिये वो सड़क पर धरने, प्रदर्शन करने नेताओं की आड़ में इनके चुनाव जीतने और शक्तियों के उपयोग करना उतना ही सिखाते है। ताकि ये कभी भारी न पड़ सके। इसलिये तो इन्हें तकनीकी, कानून सिखाने की अपेक्षा इनका सदुपयोग स्वहित में कर इन्हें, भ्रष्टाचार के कुछ टुकड़े डाल इनका सदुपयोग करते रहते हैं। इसलिये ये जानबूझकर 90 प्रश सच को मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के सामने नहीं आने देते, ये हर आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर अपनी वसूली के रास्ते खुले रखते हैं। पर मंत्रियों, संत्रियों को जानबूझकर कुछ नहीं बताते।

जब भारत सरकार के निगरानी वाले उपग्रह अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। साथ ही गूगल धरती भी, धरती के आंगन के चप्पे की यथार्थ तस्वीरे, उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवाता है। तो क्यों नहीं सरकारें, सरकार में बैठे अधिकारीगण, इन आसान, सटीक व विश्वसनीय साधनों का उपयोग नहीं करता। कृषि क्षेत्र में फसलों के उत्पादन,मौसम, वर्षा, सिंचाई सुविधायें, नहरों, तालाबों से कृषि को जलापूर्ति, कृषि की फसलों की बर्बादी क प्रकोप कृषि को शासकीय सुविधाओं के लाभ, फसलों की स्थिति, सूखे पड़ने बाढ़ से कीटों और मौसम के प्रकोप से फसलों की क्षति और बीमा व शासन से क्षतिपूर्ति के मामले,

इसी प्रकार वनों में, वन भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कटाई, वन प्राणियों की हलचल और आवाजाही, खनन माफिया, वृक्ष माफिया, भूमाफिया के कब्जे, वृक्षों की वनों में सूखे, अग्नि, वृक्षों पर कीट प्रकोप, वनोपज का अवैध दोहन उसके अपने कर्मचारियों अधिकारियों के कर्तव्यों और निष्ठा का आंकलन आदि सब पर उपग्रह से प्राप्त चित्रों, छाया चलित दृष्यावलों में आसानी से निगरानी की जा सकती है। हाल ही में छः करोड़ वृक्षों का पौधारोपण यथार्थ में कितना हुआ या आंकलन भी उपग्रहों और गूगल अर्थ से प्राप्त चित्रों को देखकर लगाया जा सकता है।

यही हाल लोक निर्माण विभाग जो भवन,पथ, पुलों और नागरिक सेवाओं की संरचना, रखरखाव और मरम्मत आदि के कार्यों, भवनों पथों की वास्तविक स्थिति का आंकलन मुख्यालय में बैठकर देख और निगरानी कर सकता है। ताकि न केवल जन-धन का सदपयोग वरन नागरिक सुविधाओं, यातायात की व्यवस्था का भी उपग्रहों व गूगल अर्थ की छवि दर्शन से सुचारू नियंत्रण व नियमन किया जा सके।

नागरिक सेवाओं से जुड़े भूतल पर किये जा रहे कार्यों, वास्तविकताओं, सेवाओं से जुड़े हर विभाग यथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन नगर व गृह निवेश सभी प्राधिकरण सभी नगर निगम पालिकायें, ग्राम पंचायतें, ग्रामीण विकास,उद्यानिकी, खनिज, स्वास्थ्य, रेशम, महिला व बाल विकास, शिक्षा, रेलवे, विद्युत, संचार, सभी सेनायें, सभी सैन्य बल पुलिस प्रशासन, खाद्य व नागरिक प्रशासन कर विभाग, पंजीयन, पुर्नवास आदि विभागों को उपग्रहों और गूगलअर्थ से प्रशासनिक व्यवस्थाओं और निगरानी के परिणामों से न केवल अरबों रुपए की बचत की जा सकती है वरन सटीक और 90 प्रश तक जनधन का उपयोग किया जा सकता है। अधिकांश कार्य विभागों के इंजिनियरों और अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर इसका उपयोग भी करते हैं। परंतु शासकीय और प्रशासकीय स्तर पर इसको मान्यता व शासकीय कार्यों से इसका उपयोग न करने से भ्रष्टाचार, जालसाजियां, करने में।

साप्ताहिक समय माया

मप्र परिवहन विभाग, कदम-कदम वैध-अवैध लूट का तांडव

केन्द्रीय परि. मंत्री गडकरी ने स्वीकारा परिवहन विभाग में घोर भ्रष्टाचार

पीथुसी के 90 प्रश अयोग्य 22 कर्मचारी का स्टॉफ, सबके पास एवजी, विभाग की साइट के हर भुगतान पर 75 से 80 रुपए अधिक, कम्प्यूटर शुल्क, नये वाहन की खरीद पर 500वितरक, विक्रेता का शुल्क, विक्रेता एजेन्ट का शुल्क भी वसूलता है। विभागीय रोकड़ा भुगतान सुविधा समाप्त। रूट परमिट फिटनेस के नाम मोटी वसूली नामांतरण अनापत्ति

भारत के केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अनेकों मंचों से स्वीकार कर चुके हैं कि राज्यों के परिवहन विभाग में भारी भ्रष्टाचार है। जालसाजी का लूट और वसूली का खुला तांडव यहां हर राज्यों के परिवहन कार्यालयों में होता है। ड्राइविंग लाइसेंस से चलकर, निजी और शासकीय स्तर पर चलने वाली परिवहन सेवाओं में जनता से न केवल खुली लूट, बत्तमीजियां, महिलाओं से छेड़खानी, बलात्कार, हत्याओं तक के लिये ये विभाग जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक वाहनों के चालकों परिचालकों के लाइसेंस में, चालकों, परिचालकों के चरित्र प्रमाण पत्र भी देखे जाने चाहिये, निजी स्तर की सार्वजनिक सेवाओं में अधिकांश आपराधिक प्रवृत्ति के के ही होते हैं। जो आसानी से चालक परिचालक बन, अपराध करने के बाद फरारी काटते रहते हैं। किराये पर चलने, सरकारी कार्यों में टैक्सियों में भी 90 प्रश चालकों के पास व्यावसायिक अनुज्ञति न होने के साथ ही 90 प्रश सरकारी कार्यालयों में टैक्सी परमिट के नाम पर 90 प्रश व्यक्तिगत वाहन चलाये जा रहे हैं। जिनका परिवहन अधिकारी के पास न तो स्वयं जांच करते हैं न कोई रिकार्ड होता है। यही हाल स्कूल के बच्चों व विद्यार्थियों के वाहनों में चाहे ऑटो रिक्शा हो मिनी बस व बसे, न तो व्यवसायिक वाहन होते हैं। न ही उनके चालकों के पास अनुज्ञपत्या। इसके साथ ही ही 90 प्रश आटो मिनी व बसों में क्षमता से तीन गुने से 5 गुने ज्यादा विद्यार्थी भरे वाहन नगरों की सड़कों पर घूमते हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं। जब तक दुर्घटनाएं न हों और 100-200 घरों के चिराग न बुझे, हर वर्ष सैकड़ों मौतें होने के बाद भी न केवल परिवहन विभाग सरकार और शिक्षा विभाग भी देखने को तैयार नहीं।

इंदौर परिवहन विभाग में मात्र 22 कर्मचारियों का स्टॉफ है, जबकि आवश्यकता है 70 से ज्यादा की जिसमें सहा. परिवहन जिला परिवहन, निरीक्षकों, बाबुओं से लेकर चपरासियों की, परंतु भर्तीयां न होने से भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए परमिटों,फिटनेस नामांतरण अनापत्ति के नाम पर कार्य ज्यादा होने से हर कर्मचारी का अपना निजी 2-3 एवजीयों का स्टाफ होता है। साथ ही ऐसे 60 प्रश कार्य वहां पर एजेन्टों व दलालों द्वारा करवाये व किये जाते हैं। अकेले वाहन चालक अनुज्ञप्ति के नाम पर 4 गुना से 6 गुना वसूली होती है। यही कारण है कि इंदौर का क्षे. परि. अधि. के पद की नीलामी रुपए 5 करोड़ तक की जाती है। बाद में हर तिमाही रायल्टी भी लाखों में जाती है। इसलिये सारे भ्रष्टाचारों और जालसाजियों के बाद और अनेकों शिकायतें व जालसाजियां पकड़े जाने के बाद भी सारे कर्मचारी निरीक्षक, जिला व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुंडली मारे जमे रहते हैं। चाहे वो फर्जी 8वीं की अंकसूची का मामला हो या दो पहिया वाहनों के नंबर पर बड़े 4 पहिया कारें, ट्रकों व बसों के चलने की जालसाजियां हों। लोकायुक्त के छापों के बाद वहां भी महीना पहुंचाया जाने लगा तो वो भी चुप हो गये। इससे खुलकर भ्रष्टाचार बढ़ा।

प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर खुलकर नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुये जिसमें केमिकल इंजिनियरिंग का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिये था। खुलकर न केवल इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर वरन पूरे देश में लाखों लेकर पीयूसी प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत एजेंट खड़े कर दिये जो छोटे-छोटे मिस्त्री जो 8-10वीं भी पास नहीं थे। बिना पर्याप्त छूटों में कार्बनडाइआक्साइड मोनोआक्साइड, गंधक आदि का अ ब स द भी नहीं जानते थे अधिकृते कर दिये गये। सूचना के अधिकार में उसका राज सामने आया जितने कानून उतने वसूली के हथियार, औचित्यहीन कर देते हैं। उन कानूनों को भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी, दूसरी तरफ 90 प्रश वाहनों में स्तर विधि नियमानुसार नं. प्लेट नहीं होती यातायात पुलिस और परिवहन निरीक्षक वर्षों से चलने वाले ऐसे वाहनों को पकड़कर कर्मचारी नहीं कर पाते तो प्रदूषण नियंत्रण क्या देख सकेंगे।

फिर घर बैठे ऐसे अधिकृत व्यक्ति जो स्वयं अनपढ़ हैं रुपए 500 से हजार तक लेकर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। वरन प्रदूषण से मनुष्यों व जीव-जंतुओं और वनस्पतियों पर भारी नुकसान करते शान से घूम रहे हैं। जबकि इस संबा में सबसे पहले वाहन निर्माताओं को उत्पादन के समय ही कड़े नियंत्रण और इंजिनों में ही ठोस व्यवस्था करना चाहिये। पर हालात इसके विपरीत ये हैं कि बीएस फोर के वाहन भी 25-50 हजार किमी चलने के बाद ही दम तोड़ने लगते हैं। और इंजिन खराब होने के कारण ज्यादा धुआं फेंकते हैं। 2010 के बाद 90 प्रश दो पहिया वाहनों के इंजिन 50000 किमी भी नहीं चल पाते और इंजिन का ब्लॉक पिस्टन का शीघ्र घिसावट भारी धुआं फेंकने लगते हैं। विदेशी कं. का ज्यादा गाड़ीयां बेचने का यह षड़यंत्र रोग भारतीय कं. को भी लग चुका है। बजाज, टीवीएस उसी ढरे पर चल रही है। जो प्रदूषण का बड़ा कारण बन रहा है। वरिवहन मंत्रालय को निर्देशित करना चाहिए। पर भ्रष्टों को महीना नहीं मिलेगा।

शासकीय स्तर पर भी लूट और वूसली के हथकंडे खूब चल रहे हैं। मप्र की मुखेरा जन पार्टी ने पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री पर 1 प्रश शुल्क तो वसूलना शुरू कर ही दिया, इसके साथ ही हर वाहन की बिक्री पर रुपए 500 व कार की बिक्री पर भी डीलर शुल्क के रुपए 20000 तक 7 प्रशित कर, स्मार्ट कार्ड जो कि हर रसीद पर रुपए 70-80 कम्प्यूटर शुल्क व्हीआईडी के साथ एजेन्ट शुल्क भी क्रेताओं से डीलर वितरक काट रहे हैं। परिवहन मंत्रालय और विभाग के हरामखोर जालसाज डकैतों नगदी, भुगतान सीधे ग्राहकों से ही क्यों नहीं लेते उस पर रुपए 1000-2000 की वसूली वाहन विक्रेताओं से क्यों अधिकृत करवाकर लूट रहे हो, जिसने कर्ज से वाहन खरीदा होता है उस रुपए 1000-2000 के उसे ऋण व ब्याज मिलाकर रुपए 5000 तक चुकाने पड़ते हैं।

विद्युत वितरण कं. में चल रहा अनाधुंध लूट का तांडव, पिस रही जनता फिर भी 4-4 घंटे अंधेरा

बंद करो कं. हटाओ भा.प्र. से अधिकारी, बंद करो हर कदम डकैती

तत्काल भर्ती करों स्थाई मीटर रीडरों, लाइनमेंनों से लेकर बाबुओं, इंजिनियरों की

पूरे देश में बिजली के नाम पर बनाई गई विद्युत कं. और उसमें बैठाई गई धूर्त जालसाज भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों की गिद्धों की फौज ने 1956 से सन् 2000 तक चल रहे राज्य विद्युत मंडलों को न केवल बर्बाद कर दिया वरन जब से इन गिद्धों को बैठाया गया इन श्वानों की फौज एक तरफ मंडल की संपत्तियों, प्लांटों, पाइप लाइनों एवं मोटा उ.दा. से निम्म दाब में परिवर्तित करने वाले स्टेशनों, सब स्टेशनों, वहां लगे ट्रांसफामर्स के रखरखाव रंग, रोंगन, तेल पानी का हर वर्ष हजारों करोड़ हजम करने के साथ ही अंट-शंट रीडिंग अस्थाई कर्मचारी से लिखवाकर 3 वाट व 5 वॉट के एलईडी बल्बों की खपत पर भी 500-300 यूनिट के बिल बनाकर वसूली का दबाब बनाने जैसी घटनायें 90 प्रतिशत आम उपभोक्ताओं के साथ की जा रही है। और अनाप-शनाप बिलिंग कर अत्याधिक तेज मीटर लगाकर तीन से चार गुना वसूली के बाद कंपनि में घाटा दिखाकर हर वर्ष 2-3 बार बिजली की कीमतें बढ़ाई जाकर लूटा जाता है। जबसे महाभ्रष्ट जालसाज पूर्व में सन् 2002 में निलंबित किया गया और वर्तमान में शहरीय वृत्त का अधीक्षय यंत्री सुब्रतों राय को बनाया गया है। पूरा इंदौर दिन में भी 4-68 घंटे की बिजली कटौती से रखरखाव के नाम पर पूरे साल से परेशान हो रहा है। इस हरामखोर की चारों तरफ से शिकायतें होने के साथ घेराव के बाद भी बैठाये रखा गया है। इसे सूचना के अधिकार में पत्र दिया गया जब उचित जवाब और जानकारी नहीं दी गई तो मुख्य अभियंता को अपील की गई पर उस जालसाज ने भी अपील की सुनवाई की तो दूर उल्टे ही अपील इसे ही भेज दी। छः महीने गुजर जाने के बाद भी अपील का निराकरण नहीं किया गया। न ही इस हरामखोर जालसाज अ.यं. ने जानकारी ही प्रदान की क्योंकि इसमें इसके कारनामें के दस्तावेजी सबूत थे।

अ.यं. सुब्रतों राय के आने के बाद न केवल जनता भारी भरकम फर्जी बिलों की वसूलियों से परेशान होती रही हैं शिकायतें सुनने और निराकरण करने की किसी को फुर्सत नहीं, यदि अच्छे अधिकारी इंजिनियर कहीं पदस्थ कर भी दिये जाते हैं तो उन्हें साल-छह महीने से ज्यादा काम नहीं करने दिया जाता। जैसे सहा. यं. तिवारी को इलेक्ट्रानिक्स कॉम्पलेक्स से छह माह में ही हटा दिया गया। जो कि हर उपभोक्ता से बड़े ही सभ्यता के साथ सुनकर परेशानी दूर करते थे। 70 प्रश स्टॉफ घोर बत्तमीज, भ्रष्ट जालसाज है। मीटर रीडरों की तो हरामखोरी जालसाजी अपने चरम पर हैं। जिन से महीना मिले उनका लाखों का बिल भी सैकड़ों में जिनसे न मिले या जो महिला इन गिद्धों की बात न मानें उनके सैकड़ों का बिल भी 300-500 यूनिट लिखकर हजारों में बना, बिजली काटने की धमकी देकर वसूली करना। सब करते है फिर न उपयंत्री, सहा यंत्री, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता तक फोन नहीं उठाते, पूरी गर्मी और अब बरसात में भी दिन में रात में 3-3 बार दो चार घंटे तक के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। कोई भी फोन नहीं उठाता।

अब जबकि मप्र में बिजली का अधिवय है। 8000 मेवा की मांग के विपरीत 1800 से 20 हजार मेवा बिजली उपलब्ध है तो कटौती क्यों? प्रदेश के उपभोक्ता को रुपए 7 प्रति यूनिट की बिजली और प्रदेश के बाहर विद्युत बिक्री रुपए 2.43 पै. प्रति यूनिट की दर से बेची जा रही है। जिसमें रुपए 2 प्रति यूनिट तक कमीशन मारकर हजारों करोड़ की कमाई की जा रही है। जबकि निजी ताप रिलायंस, टाटा, से रुपए 4.40 पै., सौर व पवन ऊर्जा को 5.50 पै. यूनिट की खरीदी में भी रुपए 4 प्रति यूनिट का कमीशन हजमकर सारे धूर्त और प्रताड़ना सेवा के अधिकारी जो विद्युत ट्रेडिंग कं. में बैठे है। से लेकर मुख्यमंत्री तक हजारों करोड़ हजम कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के ताप ऊर्जा संयंत्रों को निजी कं. से मोटे कमीशन के चलते ये गिद्ध शूकरों भा. प्र. से की फौज, कबाड़ बना नीलाम कर बंछ करने पर तुली है। सारणी के सारे ताप संयंत्र बंद कर दिये गये हैं। खंडवा का सिंगाजी पावर प्लांट को न्यूनतम उत्पादन करने का कह रखा है। गांधी सागर, इंदिरा सागर, पेंच, ओंकारेश्वर व अन्य की जल विद्युत का जानबूझकर पूरा सदुपयोग नहीं किया जा रहा, पर मोटे कमीशन के चलते सौर ऊर्जा और पवन विद्युत अवश्य खरीदी जा रही हैं विद्युत उत्पादन का अधिवय होने के बाद भी प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना विदेशों के समय बाधित परमाणु भट्टीयों जो कि पूर्णतः रेडियो एक्टिव हो चुकी है। कर्मचारियों और जनता कीजान जोखिम में डालने का षड़यंत्र है। उसकी आई संवर्धित पूरे नियम और प्लूटो नियम से भविष्य में युद्ध के लिए परमाणु बम बचाकर तैयार रखना है ताकि संभावित चीनी और पाकिस्तान परमाणु हमले का जवाब दिया जा सके, पर परमाणु विद्युत संयंत्रों की राख और कचरे से दुनिया के अधिकांश विकसित देश परेशान है। ये शिवराज को नहीं दिख रहा, उन्हें तो परमाणु ईंधन की खरीदी में मोटा कमीशन ज्यादा दिख रहा है।

भारत के अनेकों प्रदेशों तथा तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल में अभी भी मंडल तरीके से कार्य कर रहे हैं। मप्र में भी सारी विद्युत कं. तत्काल बंद की जाये, सारा काम जो ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जा रहा है। मंडल में स्थाई कर्मचारियों की स्थाई भर्ती कर करवाया जाये। हर तीन माह में मीटर रीडर्स बदल दिये गये। रीडिंग का कार्य संविदा या ठेका कर्मचारियों से बिलकुल न करवाया जाये। सारी कं. में से सारे भा. प्रशा. सेवा और राज्य प्रशासन सेवा के अधिकारियों को तत्काल हटा कर जिम्मेदार कं. अधिकारी पदस्थ किये जाये अन्यथा पूरी विद्युत व्यवस्था अंधेरे में डुबो देगी जनता को और प्रदेश के उद्योगों को।

बेचारा सरकारी शिक्षक

शिक्षक हूँ, पर ये मत सोचो,
बच्चों को सिखाने बैठा हूँ
मैं डाक बनाने बैठा हूँ,
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ

कक्षा में जाने से पहले
भोजन तैयार कराना है
ईंधन का इंतजाम करना
फिर सब्जी लेने जाना है
गेहूँ ,चावल, मिर्ची, धनिया
का हिसाब लगाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ

कितने एस.सी. कितने बी.सी.
कितने जनरल दाखिले हुए
कितने आधार बने अब तक
कितनों के खाते खुले हुए
बस यहाँ कागजों में उलझा
निज साख बचाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ

कभी एस.एम.सी कभी पी.टी.ए
की मीटिंग बुलाया करता हूँ
सौ - सौ भांति के रजिस्टर हैं
उनको भी पूरा करता हूँ
सरकारी अभियानों में मैं
ड्यूटियाँ निभाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ

लोगों की गिनती करने को
घर - घर में मैं ही जाता हूँ
जब जब चुनाव के दिन आते
मैं ही मतदान कराता हूँ
कभी जनगणना कभी मतगणना
कभी वोट बनाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ

रोजाना न जाने कितनी
यूँ डाक बनानी पड़ती है
बच्चों को पढ़ाने की इच्छा
मन ही में दबानी पड़ती है
केवल शिक्षण को छोड़ यहाँ
हर फर्ज निभाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ

इतने पर भी दुनियां वाले
मेरी ही कमी बताते हैं
अच्छे परिणाम न आने पर
मुझको दोषी ठहराते हैं
बहरे हैं लोग यहाँ
मैं किसे सुनाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ..
मैं नहीं पढ़ाने बैठा हूँ..

सबकुछ टिका है विश्वास और अविश्वास पर, प्रसार करो चीनी षड़यंत्रों का

पेज 1 का शेष

विदेशी पत्र-पत्रिकाओं और टीवी समाचारों के साथ सोशल मीडिया यथा फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम व अन्य सभी में बढ़ाचढ़ाकर प्रचारित कीजिये कि उसके बने मोबाइल फोन्स, खिलौनों से लेकर उसे संचार उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों, उसके बनाये विमानों तक में जासूसी कैमरे, रिकार्डर और ट्रांसपोर्टस जो सभी ऑटोमोड में होने के साथ सारी सूचनायें लक्ष्य प्रेषण के साथ अपने निर्माता को भी प्रेषित करते हैं। यह सब तथ्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सूर्खिया बटोरने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की अविश्वसनीयता की बत्तमीजियां सिद्ध कर चुके हैं। प्रचार-प्रसार माध्यमों में उसके हर वर्तमान के साथ भविष्य के छल-कपट का स्पष्ट संदेश सार्वजनिक माध्यमों की अपेक्षा सीधे मोबाइल फोनोंख ईमेल पर प्रेषित करें ताकि जिन देशों से यह रेलवे लाइन डालकर भविष्य में न केवल उनकी अर्थव्यवस्था चौपट कर,ऋणों के माध्यम से, अपने माल को बैचने वहां के उद्योग धंधे चौपट कर वहां की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने वहां पर चीनी नागरिकों को बसाने, जासूसी करने, लड़ाई-झगड़े करवाने,गृहयुद्ध करवाने के षड़यंत्र करेगा उसके बारे में उन देशों के साथ ही विश्व को भी सचेत किया जाये। रूस को इन परिभाषाओं से आगाह कर पुतिन की चीन की गलबहियों को बिखेरा जाये, यथार्थ में चीन ब्रिटेन की तरह षड़यंत्र रच, रेल के माध्यम से उस हर देश को गुलाम बनाने का सपना देख रहा है। शायद इस षड़यंत्रों की बदबू ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, कनाडा व अन्य राष्ट्रों को नहीं है। दूसरी ओर रेल की 14000 किमी लंबी लाइन बिछाकर वह अपने देश की 50 लाख आबादी का न केवल रोजगार देगा वरन हर देश में अपने नागरिक भी रखेगा। वर्कशाप बनायेगा। उत्पादन करेगा। रखरखाव करेगा। कालोनिया काटेगा। अपने माल को बेचने के लिए ये बाजार खड़े करेगा। कर्मचारियों, अधिकारियों, इंजिनियरों के चीनी स्टॉफ के माध्यम से रूस, ईरान, पाकिस्तान, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, लंका, कुआंलपुर, जर्काता, केन्या, इंडोनेशिया आदि राष्ट्रों की औरतों से चीनी शादी कर बच्चे पैदा करेंगे, घुलेंगे रखेंगे और ब्रिटेन की तरह रेल के माध्यम से पहले व्यावसायिक कं. खड़ी करेंगे वहां के अच्छे प्राकृतिक साधनों पर कब्जें करेंगे, फिर 10-15 वर्षों में कहानी समझ वहां की सरकारों और नेताओं को समझ मोटी रिश्वत देकर सत्ता में हस्तक्षेप बढ़ा, धीरे-धीरे अगले 50 वर्षों में उन देशों को गुलाम बनाने का षड़यंत्र करेंगे। एक बेल्ट-एक सड़क की कहानी रूस के पुतिन को जितनी अच्छी लग रही है, वह भविष्य में उसकी सार्वभौमिकता के लिए उतनी ही घातक होने वाली है। क्योंकि रूस के पास भूमंडल का विशाल क्षेत्र है और नागरिक आबादी बहुत कम, जबकि उसकी तुलना में चीन के पास उसका आधा भूभाग है और रूस की तुलना में आबादी उसकी 5 गुना ज्यादा है। चीन रूस के गले में हाथ डालकर पीछे से जो घातक वार करने की तैयारी में है। उसका अंदाजा रूस के अक्खड़ धूर्त को भी नहीं हैं पुतिन कब तक जियेगा 20-30 वर्ष। तब तक परिस्थितियां बहुत बदल चुकी होगी।

बेशक पाकिस्तान पश्चिमी शत्रु पड़ोसी बांग्लादेश, पूर्वी पड़ोसी लंका, दक्षिणी, इन तीनों को रेल मार्ग पर लाकर उसकी तैयारी पूरी तरह से भारत को घेरने की ही है। वर्तमान में भी और भविष्य में भी, निसंदेह भारत में वन बेल्ट, वन रोड के सम्मेलन में न जाकर बुद्धिमता का परिचय दिया।

भारत सरकार को तत्काल अपने दूतावासों और प्रचार माध्यमों से चीन की भविष्य की षड़यंत्रकारी चालों और वर्तमान में पूरे विश्व में बिकने वाले सभी प्रकार के स्तरहीन और अविश्वसनीय माल को विश्व स्तर पर इतना बदनाम कर देना चाहिये ताकि उसका माल हर छोटे-बड़े देशों में नकार उसकी वर्तमान आर्थिक हालातों को और घातक तरीके से बर्बाद किया जाये, ताकि उसकी कोई परियोजना पूरी तो दूर शुरू भी न हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि हमारी सरकार और धूर्त पूंजीपति, स्मगलर और नेता उसे सभी प्रकार के अयस्कों की आपूर्ति रोके जिसमें लौह, मैंगनीज, माइका धातुओं को निर्यात करने से रोका जाये, उसके द्वारा निर्मित माल को भारत में न्यूनतम कर पूर्णतः समाप्त किया जाये ताकि चीन को न तो कच्चा माल मिले और न तैयार माल को बाजार मिले, इससे वर्तमान मंदी में पूरी तरह से टूट जायेगा।

जिन देशों से रेलवे लाइन गुजरने की तैयारी की गई है वहां की जनता को चीनी उत्पादों को खरीदने से रोकने के लिए उन राष्ट्रों में बसे भारतीयों के माध्यम से सामाजिक साइटों के माध्यम से जनता को मानसिक रूप से प्रेरित किया जाये ताकि उसके निर्यात को गति शनैः-शनैः कम किया जाकर पूर्णतः रोक दिया जाये, वही हाल रेल बिछाने से रोकने के लिए भी वहां की जनता को प्रेरित कर सरकारों पर दबाव बना इस परियोजना को रोकने में उन देशों की जनता को खड़ा कर दिया जाना आवश्यक हैं इस मानसिक युद्ध में न केवल बहुत कम खर्च होगा और दीर्घ समय तक अप्रत्यक्ष हथियार का सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा जिससे वह भारत को घेरने और भारत के साथ युद्ध करने से ज्यादा आवश्यक अपनी अर्थव्यवस्था के संतुलन पर ध्यान देगा। हर युद्ध के बाद घोर मंदी और बर्बादी भी झेलनी पड़ती है। बेशक रेल लाइन बिछने के बाद चीन हमेशा के लिए आर्थिक रूप से मजबूत हो जायेगा क्योंकि जिस देश से वह रेल लाइन गुजरेगी वह उसकी माल की खतप का और मोटी कमाई का बाजार होगा, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे जिससे वह युद्ध, हड़पनीति के विस्तार के साथ ही अड़ोसी-पड़ोसियों को जिसमें मूल रूप से भारत को ही परेशानी खड़ी करने पाकिस्तान को युद्ध के लिए उकसाने जब सेना पाकिस्तान से लड़ रही होगी तो स्वयं भी युद्ध में कूद पूरा उत्तरी पूर्वी आसाम, नागालैंड, सिक्किम से लेकर मेघालय शिलांग तक हड़पेगा।

वर्तमान में भी चीन छोटे यूरोपीय देशों में ये खेल रहा है। पहले व्यापार के बहाने आस्ट्रेलिया में घुसा, फिर अपनी चीनी कंपनियों में आस्ट्रेलिया के राजनैतिक नेताओं के रिश्तेदारों के बड़े-बड़े पदों पर नौकरियों देकर बड़े-बड़े नेताओं को मोटी घूस मंत्री अब सत्ता में दखल देने लगा है। अर्थात वह इस खेल का खिलाड़ी बन चुका है, रेल लाइन के माध्यम से भी वह हर देश में यही खेल खेलते का षड़यंत्र रच रहा है। आवश्यकता है इस बात है कि प्रचार माध्यमों से इस युग में अपने आपको बचाने देश और देश की जनता, जनता को रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था को बचाने, शत्रुओं की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने, शत्रु के कुकर्मों, दुष्कर्मों, षड़यंत्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार कीजिये, उस हर देश में जहां चीनी माल बिकता है। चीनी कंपनियां काम कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर से 10-20 हजार लोगों को कम्प्युटरों पर बैठाकर विदेशों के हर समूह में घुसकर आसानी से जनता और उस देश के सत्ताधीशों के मस्तिष्क में इस हड़पो कब्जे करों की नीति का पर्दाफाश करते हुए संदेश भेजो। चीन में श्रमिकों को 12-12 घंटे काम लेकर जो शोषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध चीन के अंदर ही चीन के सत्ताधीशों के विरुद्ध माहौल खड़ाकर चीनी सत्ताधीशों को बुरी तरह से अपने ही घर में उलझा दोख, बाहर तो तब निगाह डालेगा, जब देश में शांति रहेगी। जब पूरा देश अंदर से सुलगेगा तो चीनियों के सारे षड़यंत्र रेल लाइन बिछाना, भारत पर युद्ध थोपने और कब्जे करने का षड़यंत्र रखा रह जायेगा।

बेशक भारतीय योग का प्रचार दुनिया के 180 देशों में किया जाकर पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित किया है, इससे यूरोप और चीन की दवा, स्वास्थ्य उपकरण निर्माता का जो युरोप चीन निर्मित और उत्पादित कर पूरी दुनिया में बेचते हैं जब दुनिया के 180 देशों की जनता योग से निरोग होने की राह पर चल पड़ी है तो उपयोग करो भारत के प्रति इस विश्वास का। भारत का माल पूरी दुनिया के बाजार में खड़ा करो, चीनी माल का अविश्वास का प्रचार प्रसार कर चीनी माल का बाजार भर बिगाड़ दो और चीनी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दों। सैनिकों को वेतन तो तब देगा, टैंकों, जहाजों में ईंधन तो तब भरेगा जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

मोदी जनधन बाप की जागीर नहीं, जिससे मौज उड़ाओ

पेज 1 का शेष

चाहे तो बैंकों के खातों की जानकारियां हो या मोबाइल डाटा की जानकारियां कोई भी थोड़ा सा कम्प्यूटर को ज्ञानी, घंटे-दो घंटे की मेहनत के बाद किसी भी साइट की रिकोडिंग कर आसानी से डाटा में सेंध लगाकर आसानी से सारी जानकारी एकत्रित कर पैसा यहां से वहां स्थानांतरित कर रहा है। सरकारी शूकरों की फौज मुश्किल से एक प्रतिशत प्रकरणों में भी पैसा लौटाने की जवाबदारी भी नहीं निभा रहे हैं। मोदी मात्र बहुराष्ट्रीय कं. की कठपुतली सारा डाटा, आधार कार्ड का, उससे जुड़े सारे लेन-देन आदि का डाटा का भारी सदुपयोग इस राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों की हर गतिविधि पर नजर रखने, उसके खाने-पीने की आदतों से लेकर कौन और किस क्षेत्र का किस बीमारी का शिकार हैं, और उसे क्या बेचा जा सकता है। किस से उसकी बातचीत किस संबंध में कहा कैसे और कब होती है पर मात्र हिन्दुओं की निगरानी के लिये लाद रही हैं, जो एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों और व्यक्ति जीवन की गोपनीयता का खुला हनन है। फिर आधार कार्ड से आम साधारण नागरिक से लेकर न्यायाधीशों, सुरक्षाकर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की जान जोखिम में डाला और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिये अपराधियों के लिये, सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो रहा है, हर दिन हजारों खातों से रु. 500 करोड़ की औसतन ठगी होती है। मात्र इसलिये कि आधार कार्ड से बैंक खाता मोबाइल नं. जुड़ा हुआ है पर इसके विपरीत सरकार और सरकार में बैठे कर्मचारी-अधिकारियों, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ही सरकारी कठपुतली, आखिर सरकार ही तो वेतन और सुख-सुविधायें, मान-सम्मान देती है। आमजनत को लुटवाने और बर्बाद करने के लिये आधार के पक्ष में फैसले दिये जा रहे हैं।

इसके विपरीत न केवल सरकारें, उसके सभी विभाग, सर्वोच्च, उच्च व अन्य सभी न्यायालय स्वयं संविधान की भावना के अनुरुप अपनी कितनी जिम्मेदारियां पर दर्शिता और जनधन जो केन्द्र व सभी राज्य सरकारों उनके सभी विभागों ने कहां, कैसे और क्यों उपयोग न केवल बताने, सूचना अधिकार अधि.05 की धारा 4 के अंर्गत अपनी विभागीय वेबसाइटों पर 12 वर्ष बाद भी बताने और डालने को तैयार नहीं है। जैसे जनधन जो जनता से मनमाना वसूला जा रहा हैं, माल व सेवाकर में 28% की सीमा के विपरीत पेट्रोल, डीजल, ईंधन वायु पर केन्द्र का 32% कस्टम व एक्साइज के बाद भी 10.5% अधिभार उस पर म.प्र. राज्य में 32% कर के साथ रु.5 पेट्रोल पर रु. 4/-, डीजल पर अलग से वसूले जा रहे हैं। अर्थात 76%-78% करों पर भी कर लगाकर जनता की जेबें, डकैती डाली जा रही है, इसके बाद भी कभी पत्रमुआ के विमुद्रीकरण से, कभी माल व सेवा कर या मसक इंग्लिश में जीएसटी लगाकर करोड़ों को बेरोजगार दाने-दाने को मोहताज किया जा रहा है पर स्वयं देश का प्रधानमंत्री न केवल अपने कार्यालय की स्वयं की अपनी सारी जानकारी, सूचना अधिकार में साइटों पर लोड कराने और जनता को देने को तैयार नहीं, जनता के पैसे से अपने आकाओं के लिये विदेश यात्राओं पर जाकर मौज मस्ती भी करो उनके लिये व्यावसायिक सौदे करो? बहुराष्ट्रीय कं. से मोटा कमीशन लेकर आधार कार्ड के डाटा बेचो, सौदेबाजी करो, वहां पर राष्ट्रपति से मिलने और सिवाय भोजन करने के भी अरबों रु. जनधन के चुकाओं पर जनता को ये भी न बताओ कि कहां पर कितने अरब रु. मिडिया में ताली ठुकवाने में, अपनी वाहवाही करवाने, अपने वस्त्रों पर, आने-जाने में बर्बाद किये? क्योंकि हम तानाशाह सत्ताधीश हैं।

वही हाल राज्यों में भी हैं, मु.मं. शिवराज ने म.प्र. में हर विभाग में चाहे वो कार्य विभाग, यथा लो. निर्माण स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य गृह, महिला बाल विकास, आदिम, अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग, कृषि उद्यानिकी आदि में मात्र अपनी ब्रांडिंग और वाहवाही करवाने में हजारों करोड़ के खर्च के साथ मीडिया में न केवल प्रदेश में वरन् देशभर में और विदेशों में भी विज्ञापन पर हर दिन हजारों करोड़ खर्च करके म.प्र. वाणिज्य कर के जून 17 तक 80% राजस्व प्राप्ति का खर्च कर दिया। अपने अत्याचारों और जालसाजियों को छुपाने हरामखोर जालसाज ने मौखिक आदेश से कर्मचारी अधिकारियों को सूचना के अधिकार में जानकारी देने से मना कर दिया। जैसे सभी भ्रष्ट, जालसाज कर्मचारी अधिकारियों के बाप की जागीर हो, जनधन और उससे जु सारे दस्तावेज, किसी भी विभाग ने मु.मं. कार्यालय से लेकर जिला व जनपद पंचायतों तक ने अपनी जानकारियां न तो धारा 4 में साइटों पर डाली और न ही हरामखोर गिद्धों की फौज ने 99% आवेदकों को उनकी चाही गई जानकारी दी गई, जैसे सब इनके बाप की जागीर हो, यही हाल प्रधानमंत्री और उसके कार्यालय में बैठे गिद्धों का भी है। जो पूरे देश का आधार कार्ड तो लेना चाहते हैं परन्तु शूकरों की फौज सूचना के अधिकार में जानकारी न देने के लिये कैसे और कितने बहाने कहती और बताती हैं, ये उसके पत्रों से मिलता है। जैसे वो कार्यालय देश के प्रधानमंत्री का नहीं वरन देश के किसी तानाशाह के कार्यालय हो, जिसमें वह जो करे सब सही कानून उसके बाप की जागीर, जनता का धन उनकी मौज, मस्ती रु. 25 करोड़ के सूट पहनने, अपनी ब्रांडिंग करने, अपनी वाहवाही करवाने में हर दिन रु. 2 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च करने की जागीर कैसे बतायें और क्यों बतायें करों में लूटा धन कहां गुल (उड़ाने) में कहां खर्च किया बस जनता दो नं. का कोई काम नहीं करें, कहां से कमाया कहां कितना खर्च किया, कमाया तो भी करों से लूटेंगे, बचाया और जमा किया तो भी लूटेंगे, वक्त जरूरत पर खर्च किया तो भी करों से लूटेंगे हम शहंशाह-तानाशाह हम,ल जो पूंजीपति पर खर्च करेगा, उसके हम जनधन से दिये गये लाखों करोड़ माफ करेंगे, परन्तु लाखों किसान आत्महत्याएं करें तो करें उनके दो लाख करोड़ रुपए माफ नहीं करेंगे, जितना ज्यादा और जल्दी मरो, जमीनें पूंजीपतियों को हथियाने का मौका मिलेगा, इसलिए हर गरीब आधार कार्ड बनवाने उसे मोबाइल से जोड़ों, बैंक खातों से जोड़े ताकि हम निगरानी कर सकें कि हमारी डकैती में तो आम आदमी सेंध नहीं लगा रहा, जिसने हमें वोट देकर हमें प्रधानमंत्री बनाया।

साप्ताहिक समय माया

पुराने पाप धोने, 6 करोड़ वृक्षारोपण कर, विश्व रिकार्ड

पेज 1 का शेष

तो 7.50 करोड़ की अपेक्षा 6 करोड़ ही माने ते 125 वर्ष में 66 करोड़ कटवाने के बाद गिनीज बुक में एक दिन 6 करोड़ पेड़ लगाने का कीर्तिमान बनाने की तैयारी। विश्व के लिए अजूबा हो सकती है। परंतु यथार्थ में 66 करोड़ हरे-भरे वृक्ष काटने और कमीशन में मात्र प्रति वृक्ष रुपए 1000 मिला तो रुपए 66000 करोड़ तो आप हजम कर गये औ उससे तीन गुना पूरा वन विभाग जिसमें वन भक्षण सेवा के अधिकारी भी थे। मात्र रुपए 1000 प्रति वृक्ष उन्होंने हजम किया तो भी रुपए 66000 करोड़ तो वो भी हजम कर गये, आखिर वैंकैया नायडू जो पूर्व में भाजपा के अध्यक्ष थे। आखिर क्यों अपने खास आई.ए.एस., आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों को चुन-चुन कर पिछले 20 वर्षों से मप्र में इसीलिये स्थापित कर रहा है कि जाओ लूटो खाओ कोई बोलने वाला नहीं। शांत प्रदेश है अथाह जनधन, वन धन और अपरारियों की पालन पोषण और समृद्धि की संरक्षण स्थली है। इंदौर कलेक्टर पी. नरहरि भी आंध्रप्रदेश का है। पूर्व में इंदौर का संभागीय वन मंडलाधिकारी कृष्णमूर्ति व अन्य 50 मप्र व छत्तीसगढ़ में इसीलिये पहुंचाये गये हैं। फिर 6 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण में 65 करोड़ करोड़ बटेंगे नहीं तो नये 6 करोड़ लगाकर विश्व कीर्तिमान कैसे बनायेंगे। अर्थात वृक्ष कटाई माफियाओं का पैसा जेब में और लगाठं संरक्षण का पैसा जनधन की जेब से। अब यदि एक पेड़ की पौध तैयार करने से लेकर लगाने तक में न्यूनतम रुपए 100 प्रारंभिक लागत और प्रशासनिक लागत रुपए 200 जबकि रुपए 500 से 2000 प्रति पेड़ तक भी हो सकती है, जैसे कि एक डॉक्टर, इंजिनियर, उप जिलाधीश को रुपए 70 से 1 लाख रुपए वेतन मिलता है। उससे सारे काम छुड़वाकर वृक्षारोपण का रिकार्ड बनवाने लगवा दिया तो, उसका एक दिन का वेतन रुपए 3000 था, उसने दो पेड़ लगाये। फिर एक प्रधान सचिव जिसका वेतन रुपए डेढ़ लाख है। वास्तविक कार्य छोड़ 200 किमी दूर सरकारी गाड़ी और ड्राइवर लेकर पेड़ लगाने गया तो एक की प्रशासनिक लागत रुपए 6-7000 हो गई ये किसकी गिनती में है।

सन् 2014 में भी जुलाई में 1 करोड़ पेड़ कागजों पर लगाये जाकर विश्व कीर्तिमान बनाया गया था। वरन 10 प्रश भी जीवित है। जो कि वास्तविकता में 30 प्रश ही लगाये गये थे। अब इन 6 करोड़ वृक्षों के रोपण में कागजों से उतरकर धरती पर यदि 3 करोड़ भी लगा दिये जाये तो देश की जनता से मात्र पेट्रोल डीजल में लूटी जा रही चौगुनी कीमत धन्य हो जायेगी। वैसे भी 6 करोड़ पेड़ लगाने के लिये कम डेढ़ करोड़ व्यक्तियों की जरूरतें पड़ेगी जो नहीं मिलेंगे अर्थात सारी पंचायतों 22824 के सरपंचों और कुल गांवों 54923 में यदि सभी ग्रामीणों ने पूर्ण तन्यमता से एक पेड़ भी लगाया तो भी 5,25,57424 ही लगा पायेंगे, पूरे इसके विपरीत पूरे मप्र की नर्सरियों में वन विभाग की, उद्यानिकी की भी मिला दी जाये तो भी अधिकतम डेढ़ से दो करोड़ वृक्षों के पौधे ही कागजों पर पैदा किये गये होंगे। जबकि उज्जैन जैसे जिले में भोपाल जिले में वास्तविकता में जंगल या तो हैं ही नहीं है भी तो नाम मात्र के। निजी रोपणीयों से भी यदि वृक्षों की पौध इकट्ठी करने की बात जैसे कि वन विभाग में चर्चा में सुना गया, इकट्ठे करें। दूसरे प्रदेशों से भी मंगायें जाये तो भी अधिकतम 3 करोड़ पौधों की व्यवस्था ही हो सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्वयं पूरा वन विभाग जब वनों की रक्षा और विकास लिया ही बनाया गया है। उसका उद्देश्य ही यही है तो क्या करता है और आजादी के बाद से अभी तक वृक्षों की कटाई और वनों को उजाड़ने के साथ उनकी बेशकीमती वृक्षों की लकड़ी और वनोपन कटवाने, सामग्री एकत्र करने के साथ मी भूमाफियाओं के साथ मिलकर पहले वेन साफ करो फिर उन पर कब्जे करवाओं। खेती के लिए बाले-बाले पट्टों पर दो शहर से लगी जमीनों पर कॉलोनियां कटवाओ, अवैध पत्थर, गिट्टी, मिट्टी, नदियों से रेत निकलवाकर आराम से बेंचों, खाओ, जंगली जानवरों के शिकार में प्रत्यक्ष भूमिका निभाकर मोटा हिस्सा हजम कर जाओ। फिर जिस मप्र में 1956 तक गिने-चुने आईएफएस हुआ करते थे उसमें सन् 2015 में 400 से ज्यादा आईएफएस, किसलिये और भर दिये गये केवल ये भारतीय वन भक्षण सेवा के अधिकारियों ने न केवल मप्र में वरन पूरे देश में वनों को उजाड़ने उनकी वन संपदाओं को बेंचने खानें में बर्बाद किया। एक तरफ भारतीय वन भक्षण सेवा के अधिकारी बढ़ते गये दूसरी तरफ वन रक्षक, बीट रक्षक व रेंजर के स्तरतक के कर्मचारी और वन प्राणी, वन संपदा घटते गये, यहां तक कि इन हरामखोर भा.वन. भक्षण सेवा अधिकारियों ने अपनी जालसाजियों और लूट मार को अंजाम देने 1984 में ही सर्वेवियर के पदों को समाप्त कर दिया जो हर रेंज में रहकर वनों की भौगोलिक स्थिति पर नजर रख वरिष्ठों को सूचित कर दस्तावेजों में संज्ञान में लाता था।

इसी वन विभाग में एक शाखा है। सामाजिक वानिकी, जिसका कार्य ही सतत वृक्षारोपण कर वनों का विकास करना क्या विकास केवल कागजों पर होकर ही खर्चों को जो कि पूरे मप्र में रुपए 2000 करोड़ से ज्यादा वार्षिक खर्च होता है कहां जा रहा है। वनों की भूमि पर फिर नेताओं, पूंजीपतियों, भूमाफियाओं की निगाहें भी रहती है। इंदौर निकट औंकारेश्वर में ही देखें तो जिस ओंकारेश्वर मंदिर की सीमा से लगते ही वन आच्छादित थे। वहां बड़े नेताओं और भूमाफियाओं ने वन भूमि साफ कर बड़े होटल और रेस्टोरेंट किमी आगे तक स्थापित कर लिये जिसमें खंडवा और खरगोन के जिलाधीशों की भूमिका नेताओं के इशारे पर संदिग्ध रही, होटल बनते रहे सब मोटा टुकड़ा खा रेंजर, वनमंडलाधिकारी कलेक्टर, कमिश्नर, जालसाज सब चुप बैठे बोटी निकलते टुकर-टुकर ताकते रहे, यही हाल बांधवगढ़, कान्हा पेंच, पंचमढ़ी, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, वन्य प्राणी कूनों पालपुर, नौरादेहीव अन्य सभी स्थानों पर इन्हीं वन विभाग के वन भक्षण सेवा के अधिकारियों के माध्यम से बड़े नेताओं पूंजीपतियों के संरक्षण में वन भूमि पर लगे हजारों वृक्षों पेड़ों का हर साल काटकर बड़े होटल रेस्टोरेंट खड़े करा वहां की सौभ्यता और शांति भंग की जा रही है। भाजपा के शासन काल में वनों का ज्यादा विनाश। हर साल करोड़ों की कटाई और सभी वानिकी पर्यटन स्थलों से जुड़े जंगलों के साथ गावों से स्नेह फालस धार्मिक स्थलों से जुड़े वनों व अन्य दशनीय स्थलों से जुड़े जंगलों के साथ गावों से जुड़ी वन भूमियों की सफाई-कटाई के बाद उस पर खेती करने के कारण वनों को भारी क्षति पहुंचाकर भाजपा शासन काल के 13 वर्षों में 20 करोड़ से ज्यादा पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई, इसके साथ इंदिरा सागर की डूब में हरसूद और उसके चारों तरफ फैले 50 हजार है. से ज्यादा जंगलों की सफाई, औंकारेश्वर, सरदार सरोवर बांधों के निर्माण में भी लगभग 1 लाख है. के वन डूबो दिये गये। सही आंकड़ों के लिये पिछले 19 वर्षों से सूचना के अधिकार में पत्र देने के बाद भी हरामखोर जालसाज इंजिनियरों और वन विभाग के अधिकारियों की भ्रष्ट निकम्मी और मक्कार फौज जानकारी न देने के विभिन्न बहानों, साइट और नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण की विभागीय साइटें एक तो खुलती ही नहीं और खुलती भी हैं, इन श्वानों ने कोई भी ईमानदारी से पूरी जानकारी डाली ही नहीं जाती। ताकि भ्रष्ट जालसाज मुख्यमंत्री शिवराज से लेकर नीचे तक सारा यथार्थ सामने न आ गये। वैसे ही न केवल देश की प्रधानमंत्री वरन प्रदेश प्रदेश का मुख्यमंत्री, वन मंत्री हैं वो सभी आपराधिक प्रवृत्ति के सबका एक ही उद्देश्य लूटो खाओ, कुकर्मों को छुपाने जनधन से नौटंकीयां करो। प्रचार माध्यमों को विज्ञापन बांटों उनका मुंह बंद रखो और अपनी वाहवाही में तालियां ठुकवाने में समय व्यतीत कर इतने अपराध करो कि जनता स्वयं अगले चुनाव में भगा दे। अन्यथा नौटंकियों से ज्यादा जरूरी था कि वन विभाग को कड़े निर्देश देकर हर दिन प्रदेश की काष्ठमंडियों में 1000 हरे पेड़ कहां से कटकर आ रहे हैं। उनको देखा जाता, सबसे मुख्य बात यह कि 50 प्रकार की पेड़ों की कटाई की जन से जून तक क्यों छूट दे रखी है, जिसकी आड़ साल, शीशम के पेड़ भी काट कर बेंच दिये जाते हैं। क्यों नहीं देखा जाता 30 लाख है. वन भूमि का आंकड़ा दिखाने वाले मुखिया कभी स्वयं भी गूगल अर्थ पर प्रदेश की निगरानी कर देख लिया करो कि मात्र 4-5 लाख है. में ही वन बचे हैं।

घोंटू सर्विस टैक्स अंबानी की जागीर पेट्रोल अलग क्यों?

40 लाख करोड़ के बदले मोदी लाया जीएसटी

पेज 1 का शेष

पर देश के संबंध में मोदी और उसकी भाजपा पर कांग्रेस से ज्यादा सटीक बैठती है।

लोकतांत्रिक सत्ताओं में चुनकर आये नेता को अपने कार्यकाल की औकात मालूम होती है, इसलिये वह न केवल देशी पूंजीपतियों वरन् विदेशी पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कं. का धन, मौजमस्ती, अय्याशी और ऐशोआराम के लिए धन की आवश्यकताओं के साथ मोटी वसूली के लिये सत्ता में रहने तक अपना सर्वस्व न्यौछावर करने, पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कं. के हितों के कमाई के लिये उनकी इच्छानुसार कानून बनाने,करों को हटाने, बदलने, कम करने के लिये मोटा धन लेकर सबकुछ करता है। इस समय माया की सत्यता पूर्व में भारत में थोपे गये खाद्य सुरक्षा मानक अधि. 06 में सिद्ध हो गई थी, जिसकी तैयारी इंडियन टोबेको कं. जो ब्रिटिश टोबेको कं. की भारतीय सहायक कं. हैं ने केन्द्र व राज्य सरकारों को महाधूर्त भ्रष्ट, जालसाज अधिकारियों को खरीद, सरकारी मंडी अधिनियम के बाहर जाकर छोटे जिलों, तहसीलों में मंडी प्रांगण से अलग अपनी आईटीसी चौपाल के बड़े भंडार गृह खोलकर किसानों से अपने दामों पर माल खरीदकर भुगतान के बदले में सूई से लेकर पेंट, शर्ट, खाद, बीज, खेती कीटनाशकों से लेकर ट्रैक्टर तक बेंचने शुरू कर दिये थे। 1995 से सरकारें आई-गई सबको टुकड़े डालकर न केवल वो मनमानी करते रहे वरन किसानों की पूरे देश में 12 लाख है. से ज्यादा जमीन भी अपने नाम करा ली जिसे उन्होंने स्वयं अपने दिये विज्ञापन में स्वीकारा। इसकी तैयारी में रिलायंस के धूर्त अंबानी बंधुओं ने लाखों करोड़ खर्च करके एक तरफ सरकार से खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06 की नींव रखी तो दूसरी विदेशी तर्ज पर रिलायंस फ्रेश के 5000 स्टोर खोल दिये गये थे। सन् 2005 तक, बाद में रुपए 25 लाख करोड़ लेकर जिसमें 550 करोड़ अमेरिकी डॉलर अकेले वालमार्ट ने दिया था जिसका 3.85 लाख भारतीय रुपए के साथ रुपए 5 लाख करोड़ आईटीसी, 5लाख करोड़ अंबानी, युनिलीवर, बिरला व अन्य ने दिया। कब खाद्य सुरक्षा मानक अधि. 16 पास हो गया जनता को मालूम ही नहीं पड़ा। सारे लोकसभा, राज्यसभा के सांसदों से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों,प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे धूर्त भा. प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों तक न्यूनतम रुपए 500 करोड़ से लेकर रुपए 5000 करोड़ तक सीधे मिलने पर चुपचाप सबने अंगूठा लगा अधिनियम आसानी से बिना बहस के पास हो गया था जिसमें तैयारी थी विदेश की सारी मंडियों को समाप्त कर सारी बहुराष्ट्रीय कं. को किसानों के खेतों से ही माल खरीदने के लाइसेंस दे दो ताकि वो किसानों की लागत और मेहनत मजदूरी से भी कम दाम पर माल खरीद, अपने शॉपिंग मालों से जनता को पैकिंग में मनमानी कीमतों पर माल बैच जिसका सीधा सा उदाहरण जनता के सामने आया था, रुपए 50-60 प्रति किलो की तुवर दाल का जो रुपए 250 से 300 प्रति किलो तक बेंची और 5 से 7 गुना मुनाफा कमाया।

दूसरी तरफ छोटे प्रतियोगी दुकानदारों को समाप्त करने, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण पैकेजिंग और बेचने के नियम इतने जटिल और बत्तमीजीपूर्ण बनाने के साथ उससे अर्थदंड की राशि न्युनतम रुपए 50000 से लेकर 5 लाख कर दी गई, ताकि सब्जी, चाय, चाट,खोमचो का ठेला लगाने वाले, स्वल्पाहार गृहों, मध्यमस्त के मिठाई, नमकीन बेचने, पैकिंग करने, वाले सब देश के 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाये और सारा सामान इन कुटिल नीचों के शॉपिंग मॉल से जनता लाइन लगाकर खरीदने पर मजबूर हो जाये और ये आसानी से हजारों करोड़ की कमाई कर सके। तब भी समय माया ने ही लगातार 2007 से इसका विरोध किया था। जब विरोध ने आग पकड़ी तो सरकार ने 2006 का पास किया हुआ अधि.06, 2011 तक नहीं लगा पाई।

माल व सेवा अधिनियम 16 सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजीपतियों के विभिन्न प्रकार के करों के झंझट और अलग-अलग संस्थाओं के सामने हर पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कं. सामने सर झुकाने और सबको बांटने लेने की परेशानियों को दूर करने के साथ उनके व्यवस्था को भारत में प्रोत्साहन देने उनसे मासिक, त्रेमाही, छह माही, वार्षिक मोटा धन कमीशन के रूप में वसूलने ही जीएसटी या भक्षक कानून लाया गया, ताकि ये बहुराष्ट्रीय कं. और भारत के डकैत पूंजीपति जनता को मसक कर वसूली करें और सरकार में बैठे गिद्धों को टुकड़ा डालकर चुप रखें, यहां भी 1 जुलाई से कर थोपने के साथ ही 90 प्रतिशत अधिकारियों को न तो स्वयं कर प्रणाली समझ आई है न व्यापारियों को समझा सके हैं। न ही कर वसूली का सॉफ्टवेयर पूर्ण रूप से कार्य करने योग्य बना पाये हैं। इसके साथ ही स्वयं कर अधिकारियों, कर्मचारियों की कोडिंग हुई है, न व्यापारियों और उनके सामान की कोडिंग की जा सकी है। इस चक्कर में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर बड़े विक्रेत तक अपना माल बेंचने में सक्षम नहीं है। बाजारों और उद्योगों में माल पड़ा है। ग्राहक भी खरीदने को तैयार खड़ा है। पर कानूनी उलझनों, सॉफ्टवेयर की परेशानी ट्रांसपोर्टरों की भी परेशानी बढ़ गई और सब जाम हो गया है। जैसे नोटबंदी के कारण पूरा भारत बंद हो गया था 50 दिन के लिये वैसे ही इस मसक में पूरे उद्योग व व्यापार जगत को मसक कर रख दिया है। सब चौपट पड़ा हुआ है। देश के अनेकों स्थान पर बाजार और शहर, महानगर तक बंद रहे। पर वो धूर्त प्रधानमंत्री धूर्त मोदी नोटबंदी की घोषणा कर जापान भाग गया था। और अब जीएसटी की थोपकर अमेरिकी राष्ट्रपति से गलबहियां कर, इजरायल के न्याहू के साथ हां हूं कर फिर जर्मनी के हैम्बर्ग में जी-2 की सभा में भाग लेने पहुंच गया। देश मरे तो मरे, जनता चीखे चिलाये उसकी बला से। 24 घंटे और 7 दिन मीडिया का मुंह बंद रखने हर दिन डेढ़ से दो हजार करोड़ के जनधन से एक कर एक देश के विज्ञापन बांटे जा रहे हैं। बस उसे देश और दुनिया के इतिहास में अमर होना है। इसलिये 30 जून की मध्यरात्रि में देश की संसद में मुखेरा जन पार्टी घंटे ठोककर अट्टाहस कर रही थी और वाह-वाह पूरे देश की जनता नार्द कर रही थी। जबकि एक देश, एक कर केवल छलावा है। मसक लगा दिया तो फिर आयकर वृत्तिक र वाहन खरीदने पर 7प्रश, सड़क कर, नगर निगमों पालिकाओं का पार्किंग कर तो देना ही पड़ेगा फिर कहां का एक देश-एक कर का छलावा क्यों? सड़कों पर टोल टैक्स क्यों? पेट्रोल-डीजल, ईंधन कर, शराब मसक कर से बाहर क्यों? उन पर केन्द्र का 32 प्रतिशत कस्टम, 2 प्रश शिक्षा, 2 प्रश स्वास्थ्य, 2 कृषि कर, 0.5 प्रश स्वच्छता कर आदि कुल 42.5 प्रतिशत कर फिर राज्यों का 32 प्रश वैट के साथ रुपए 5 पेट्रोल और रुपए 4 प्रति लीटर डीजल पर अधिक क्यों? लूटा जा रहा है। अर्थात केन्द्र के 42.5 प्रश राज्य के 32 प्रश कर थोपने पर भी रुपए 5 व 4 रुपए अधिक वसूली क्या केवल जनता का खून पसीने की कमाई लूटने के लिये है।

सितंबर 17 की तिमाही आते-आते चारों तरफ हा-हाकार मचेगी, सरकारों के पास खर्चों की तो दूर वेतन बांटने का भी धन नहीं रहेगा। बैंकों में जनता के जमा धन को निकालने पर भी करारोपण। शीघ्र ही बैंको की हालत भी गंभीर हो जायेगी, क्योंकि जनता अधिकांश लेन-देन नगद में ही करने लगेगी। नंगे भूखे राक्षसों को जालसाजी से सत्ता क्या मिली जनता को खून के आंसू रूलाने पर तुल गये।

देश का सबसे बड़ा खलनायक रतन टाटा

आयोडीन नमक, देश को बीमार और नपुंसक बनाने का षड़यंत्र

1970 में टाटा ने रुपए 2 करोड़ खर्च करके बनवाया था आयोडीन नमक कानून, 45 वर्ष में देश की निरोगी 60 प्रश आबादी बीमारियों से पीड़ित

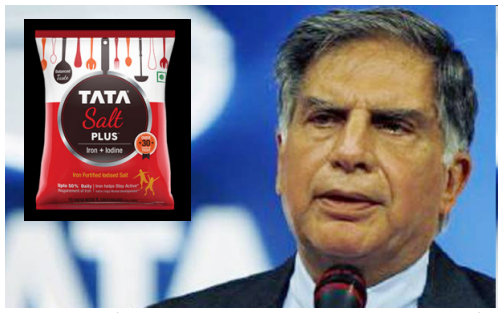

भगवान धंवतरि जो विष्णु के अवतार थे, फिर वेदों में चौथे वेद यजुर्वेद को ही आयुर्वेद जो मनुष्य को दीर्घआयु देता है में सेंधा नमक वात, पित और कफ को दूर करता है सैंधा नमक। आप सोच रहे होंगे कि यसे सेंधा नमक बनता कैसे है? आइयें आज हम आपको बताते हैं कि नमक मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है समुद्री नमक दूसरा होता है सेंधा नमक (चट्टानी नमक)। सेंधा नमक बनता नहीं है पहले से ही बनाया है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को 'सेंधा नमक' या 'सेन्धव नमक', लाहोरी नमक आदि नाम से जाना जाता है।

जिसका मतलब है 'सिंध या सिन्धु के इलाके से आया हुआ।' वहां नमक के बड़े-बड़े पहाड़ है सुरंगे है। वहां से ये नमक आता है। मोटे-मोटे टुकड़ों में होता है आजकल पीसा हुआ भी आने लगा है। यह हृदय के लिए उत्तम, दीपन और पाचन में मददरूप, त्रिदोष शामक, शीतवीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला, पचने में हल्का है। इससे पाचक रस बढ़ते हैं। तों अंत आप ये समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकले। काला नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करें। क्योंकि ये प्रकृति का बनाया है। ईश्वर का बनाया हुआ है। और सदैव याद रखे इंसान जरूर शैतान हो सकता है लेकिन भगवान कभी शैतान नहीं होता।

आयोडिन के नाम पर हम जो नमक खाते हैं उसमें कोई तत्व नहीं होता। आयोडिन और फ्रीफ्लो नमक बनाते समय नमक से सारे तत्व निकाल लिए जाते हैं और उनकी बिक्री अलक से करके बाजार में सिर्फ सोडियम वाला नमक ही उपलब्ध होता है, जो आयोडीन की कमी के नाम पर पूरे देश में बेचा जाता है, जबकि आयोडीन की कमी सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में ही पाई जाती है इसलिए आयोडीन युक्त नमक केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए जरूरी है।

भारत ने 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आजादी के पहले से उतरी हुई है, उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को समुद्र के पानी से निकला समुद्री नमक खिलाया जाता है। सबको आयोडीन की कमी हो गई है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आदि-आदि बातें पुरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई और जो नमक किसी जमाने में 5 से 10 पैसे किलो में बिकता था उसकी जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 1 रुपए प्रति किलो और आज तो भाव 20 रुपए भी पार कर गया है।

दुनिया के 56 देशों ने अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। अमेरिका में नहीं है। जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं, डेनमार्क में नहीं, यही बेचा जा रहा है। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया क्यों? उनकी सरकार ने कहा हमने में आयोडीन युक्त नमक खिलाया (1940 से 1956 तक)। अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा हो गया। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ तो उन्होंने बैन लगाया। और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में ये आयोडीन का खेल शुरू हुआ इस देश के बेशर्म नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक बिक नहीं सकता भारत में। वो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और ये बैन हटाया गया।

आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था सब सेंधा नमक ही खाते थें। सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं ये क्षारीय है। क्षारीय चीज जब अमल में मिलती है तो वो न्यूटल हो जाता है और रक्त अमलता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आपएक और बात पहचान सकते हैं कि उपवास, व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते है। तो आप सोचिये जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है?? सेंधा नमक शरीर में 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी ना पूरी होने के कारण ही लकवे का अटैक आने का सबसे बड़ा जोखिम होता है सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि यह आपको इसलिये खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। यह पाचन में सहायक होता है और साथ ही इसमें पौटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। यही नहीं आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण भाष्कर, पाचन चूर्ण आदि में भी प्रयोग किया जाता है।

समुद्री नमक- ये जो समुद्री नमक है आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है। क्योंकि कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही है। अब आयोडीन भी दो तरह का होता है। एक तो भगवान का बनाया हुआ जो पहले से नमक में होता है। दूसरा होता है औद्योगिक आयोडिन। ये बहुत ही खतरनाक है, तो समुद्री नमक जो पहले से ही खतरनाक है उसमें कंपनियां अतिरिक्त औद्योगिक आयोडीन डाल पूरे देश को बेच रही है। जिससे बहुत सी गंभीर बीमारियां हम लोगों को आ रही है। ये नमक मानव द्वारा फैक्ट्रीयों में निर्मित है। जो विभिन्न रासायनिक फैक्ट्रीयों में उपयोग किया जाता है।

आमतौर से उपयोग में लाये जाने वाले समुद्री नमक से उच्च रक्तचाप, डाइबिटीज आदि गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। इसका एक कारण ये है कि नमक अम्लीय होता है। जिससे रक्त अम्लता बढ़ती है और रक्त अमलता बढ़ने से ये सब 4 डिग्री रोग आते हैं। ये नमक पानी कभी पूरी तरह नहीं घुलता। हीरे की तरम चमकता रहता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर जाकर भी नहीं घुलता और अंत इसी प्रकार किडनी से भी नहीं निकल पाता और पथरी का भी कारण बनता है। और ये नमक नपुंसकता और लकवा का बहुत बड़ा कारण है। समुद्री नमक से सिर्फ शरीर को 4 पोषक तत्व मिलत है और बदले में अनेकों बीमारियां जरूर साथ में मिल जाती है।

रिफाइंड नमक में 98 प्रश सोडियम क्लोराइड ही है। शरीर इसे विजातीयत पदार्थ के रूप में रखता है। यह शरीर में घुलता नहीं है। इस नमक में आयोडीन को बनाये रखने के लिए ट्राइकैलियम फास्फेट, मैग्निशियम कार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट जैसे रसायन मिलाये जाते हैं,जो सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल होते है।

विज्ञान के अनुसार यह रसायन शरीर में रक्त वाहिनियों को कड़ा बनाते हैं। जिससे ब्लॉक्स बनने की संभावना और ऑक्सीजन जाने में परेशानी होती हैं जोड़ों का दर्द और गढिया,प्रोस्टेट आदि होती है। आयोडीन नमक से पानी की जरूरत ज्यादा होती है। 1 ग्राम नमक अपने से 23 गुना अधिक पानी खींचता है। यह पानी कोशिकाओं के पानी को कम करता है। इसी कारण हमें प्यास ज्यादा लगती है।

निवेदन- पांच हजार साल पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में भी भोजन में सेंधा नमक के ही इस्तेमाल की सलाह दी गई है। भोजन में नमक व मसाले का प्रयोग भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अधिक होता है। आजकल बाजार में ज्यादात्तर समुद्री जल से तैयार नमक ही मिलता है। जबकि 1960 के दशक में देश में लाहौरी नमक मिलता था। यहां तक की राशन की दुकानों पर भी इसी नमक का वितरण किया जाता था। स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। समुद्री नमक के बजाय सेंधा नमक का प्रयोग होना चाहिए।

आप इस अतिरिक्त आयोडीन युक्त समुद्री नमक खाना छोड़िए और उसकी जगह सेंधा नमक खाइये। सिर्फ आयोडिन के चक्कर में समुद्री नमक खाना समझदारी नहीं है, क्योंकि जैसा हमने ऊपर बताया आयोडीन हर नमक में होता है सेंधा नमक में भी आयोडीन होता है। बस फर्क इतना है इस सेंधा नमक में प्राकृतिक के द्वारा भगवान द्वारा बनाया आयोडीन होता है इसके अलावा आयोडीन हमें आलू, अरबी के साथ-साथ हरी सब्जियों से भी मिल जाता है।

भारत में साधारण नमक जो समुद्री जल के खाइयों में भरकर सुखाकर निकाला जाता था और भारतभर में 1960-70 के दशक में पै. किलो बिकता था, टाटा केमिकल लि. जो 1970 तक भारी घाटे में चल रही थी के रतन टाटा ने 1970 में इस कंपनी को घाटे से निकालने और पूरे देश के नमक पर कब्जा जमाने तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रुपए 2 करोड़ देकर आयोडीन नमक अधिनियम बनवाकर देश में आयोडीन नमक खाना अनिवार्य करवा दिया और जो पैसे. किलो में नमक मिलता था उसे सीधे ही 1 रुपए प्रति कि. बेचा जाने लगा। इससे टाटा केमिकल लि. 1974-75 में ही उस समय करोड़ों के लाभ में आ गई। आयोडीन नमक के आने से और उसके उपयोग के बाद ही देश में 1980 के दशक के बाद बीमारियों की बाढ़ आना शुरू हो गई, क्योंकि आयोडीन की मानव शरीर में अधिक मात्रा से हृदय और पूरे शरीर की धमनियां कमजोर होने लगती है। इसके विरोध में भाजपा केन्द्रीय सत्ता 1994 के पहले लगातार विरोध और धरने प्रदर्शन करती रही। पर सत्त में आते ही जो धन कांग्रेस व अन्य पार्टियों को मिलता था, वह भाजपा को मिलने लगा, तो वही आयोडीन नमक का अत्याधिक धीमा और मीठा विष इन मुखेरा जन पार्टी को अमृत लगने लगा।

आजाद भारत का आयोडीन नमक का उत्पादन करने वाला और खाद्य वस्तुओं के माध्यम से देश को बीमार करने वाला खलनायक है रतन टाटा और उसकी टाटा केमिकल्स कंपनी। इसके बाद से 5 पैसे प्रति किलो मिलने वाला खड़ा नमक जिसे उस समय की जनता घर लाकर पीसकर साग, सब्जी,आटे, दाल,चावल में मिलाकर खाती थी बाजार से ही गायब कर दिया गया। उसके सेवन करने और बैचने को अपराध घोषित कर दिया गया।

जबकि यथार्थ में जिस घेंघा रोग से इसको उपयोगी बताया गया था वह बीमारी मात्र भारत के छत्तीसगढ़ और हिमालय की तराई वाले इलाकों के मात्र उस समय के 16 और वर्तमान के 40 लाख लोगों में से मात्र 5 प्रतिशत लोगों में पाई जाती थी, परंतु टाटा ने मोटी कमाई के आड़े में सरकार को खरीद कानून के माध्यम से पूरे देश को खाने के लिए विवश कर दिया।

1965 के बाद देश में खाद्य और स्वास्थ्य से संबंधित बनाये गए सारे कानून बहुराष्ट्रीय कं. और पूंजीपतियों के इशारे पर ही जनता को बिना बताये अपनी मोटी कमाई के लिए जनता पर थोपे गये। चाहे वह बीज प्रमाणीकरण अधि. 1967 हो, कीटनाशक अधि. 1968 हो, जिसका परिणाम जनता ने युनियन कार्बाइड की अक्टू 1984 की त्रासदी भुगती थी। इसके बाद सबसे ज्यादा खतरनाक अधि. आया खाद्यान्न मानक अधिनियम 2006, यह भी पूंजीपतियों रुपए 25 लाख करोड़ से अधिक खर्चकर बनवाया था।

शादी करो, समाज और धर्म का हिस्सा बनो, बकवास है लिव इन

पेज 12 का शेष

ताकि स्थायित्व रहता और स्वयं के व लड़के के माता-पिता के सामने समाज में शान से हाथ थाम कर घूमती पर स्वयं के मन में भी तो ये पाप था कि अभी इससे अपना मतलब भी पूरा करो यौन सुख भोगो जब अच्दा मिलेगा जो धनाढ्य, पहलवान, रंग-रूप, रसूखवाला मिलेगा तब उससे शादी करेंगे वे ही ऐसे सहचर्य जीवन में रहना पंसद कर यथार्थ में साथी के तन, मन, धन से नहीं स्थायित्व की नींव रखनी थी, गृहस्थी बसा, बच्चों को जन्म दे, समाज का हिस्सा बनना था, अच्छे की प्रत्याशा में ही गुजर गया।

शादी जिसे हर धर्म और जाति में समाज की प्रगति और स्थायित्व का प्रथम और मजबूत आधार स्तंभ माना जाता है। यदि इतना कमजोर तथ्य होता है। सभी धर्मों और समाज के अनादिकाल से उसके महल और आवश्यकता पर इतनी व्यवस्थायें और व्याख्यायें नहीं गढ़ी और लिखी जाती। प्राचीन धर्मशास्त्रों, ग्रंथों के साथ विश्व के सभी देशों में लागू कानूनों में। धरती पर मानव समाज की अनादिकाल से वर्तमान तक की मानव यात्रा में सहस्त्रों पीढ़ियों से चले आ रहे धर्म और समाज की व्यवस्था इसी शादी के बंधन में विचरण कर गुफाओं में रह रहे होते, निसंदेह वर्तमान के सहचर्य जीवन की उच्च श्रृंखला की कबीलों में भी कल्पना नहीं की गई और न ही उच्च श्रृंखला की शास्त्रों से विवेचना ही की गई है। परन्तु इस तरह से सहचर्य जीवन में किसी लड़के या लड़की द्वारा एक-दूसरे के हाथ थाम कर चल देने को गंधर्व विवाह की संज्ञा दी जाकर जीवन पर्यन्त एक-दूसरे को निभाने और भगाकर ले जाने या लाने पर भी विवाह कर्म करना आवश्यक था।

अमेरिका में भी सदियों से चली आ रही इस व्यवस्था को ट्रंप प्रशासन के मंत्री ने दो टूक इस सहचर्य को अवैध घोषित करने, सहचर्य में वर्षों तक रहने के विपरीत शीघ्र शादी कर बच्चे पैदा करने की अपील की गई है, ताकि समाज और राष्ट्र व्यवस्थित रूप से चल सके, जहां पर समाज में खुलापन है दुनिया के दूसरे देश और युवा पीढ़ी वहां की संस्कृति को आदर्श मानती है, पर वहां भी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने इस सहचर्य जीवन को सिरे से ही नकार शादी के बाद स्त्री-पुरूष को सामाजिक मान्यता दी है।

भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी को इस सहचर्य लिव इन संबंधों को अवैध घोषित कर शादी को ही वैध मानना व समाज को विवाह पद्धति को मान्य करना चाहिये ताकि इन संबंधों को लेकर न केवल माता-पिता लड़के और लड़की के समाज व धर्म में शुचिता बरकरार और स्थायित्व रहने के साथ इन संबंधों को लेकर युवाओं में बढ़ती यौनाचार से संबंधित हत्यायें और अपराध न हों, न्यायालयों आर पुलिस में ऐसे प्रकरणों पर रोकथाम कर अनावश्यक परेशानियों से न केवल पुलिस, न्यायालयों, वरन समाज की वर्तमान व भविष्य की पीढ़ि को बचाया जा सके।

साप्ताहिक समय माया

बंद करो समाज, धर्म और राष्ट्र को बर्बाद करने वाली नीति और मान्यता

शादी करो, समाज और धर्म का हिस्सा बनो, बकवास है लिव इन

न्यायालयों और पुलिस को मजाक बना दिया, लड़के-लड़की के माता-पिता समाज और धर्म की बदनामी। अमेरिका ने भी चेतावनी दी, शादी करों और बच्चे पैदा करों

भारत की संस्कृति धर्म और सामाजिक मान्यताओं को नष्ट करने, विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. और ईसाई मिशनरियों के षड़यंत्रों का 300 वर्षों से ज्यादा पुराना इतिहास रहा है और वे ईस्ट इंडिया कं. उसके भारतीय ऐजेन्टों जिसमें 1820 के लार्ड मैकाले के भाषा और संस्कृति को नष्ट करने अंग्रेजी भाषा थोपने, गुरूकुलों में शिक्षा जो इस राष्ट्र की सहस्त्रों वर्षों की संस्कृति वेदों के ज्ञान, गणित, विज्ञान,अर्थशास्त्र, रसायन, चिकित्सा, कृषि, आदि के अध्ययन का अभिन्न अंग थी, उसे लार्ड मैकाले ने अवैध घोषित कर गुरूकुलों में नरसंहार करवा और उनके गुरूओं को बिना किसी अपराध के मरवाया। कारावासों में डाल दिया। जिसकी भारतीय इतिहास में कहीं चर्चा तक नहीं होती और इस प्रकार भारतीय संस्कृति में कहीं चर्चा तक नहीं होती और इस प्रकार भारतीय संस्कृति की आधारभूत शिक्षा समाज धर्म की संस्कृति को नष्ट किया गया। यह प्रारंभ था। जिस पर उस समय के तात्कालीन छोटी-छोटी रियासतों के राजाओं से कोई विरोध सशक्तरूप में नहीं किया गया। इस तरह आसानी से न केवल भाषा बदलने वरन संस्कृत रचित सभी ग्रंथों को नष्ट करने, संस्कृत से विरक्त कर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का 1832 का षड़यंत्र अभी भी आसानी से सफलतापूर्वक चला। बहुराष्ट्रीय कंपनी और ईसाई मशिनरियों के उद्देश्यों की पूर्ति कर हम, हमारा समाज हमारी सरकार स्वयं अपने ही हाथों अपने धर्म, समाज और राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हैं। जिसका सबसे विकृत रूप है बिना विवाह किये कारण और परिस्थिति वश जैसे सुरक्षा, खर्चे, उठाने रहने, खाने पीने के लिए सहचर्य या लिव इन में रहने की लिव इन में रहने की प्रथा जो कि विदेशों में ज्यादा चलित है, हमारे देश के भांड और भेड़ चाल चलने वाले मीडिया जिसमें मुद्रित माध्यम ही ज्यादा आगे थे, काफी प्रचारित प्रसारित कर सन् 2007-08 में सरकार से भी समलैंगिकता और सहचर्य जीवन को मान्यता दिलवा दी। इसके विपरीत समयमाया ने 2008 के समाचार पत्र में इसका यथार्थ उजागर कर इसकी बत्तमीजियों को उजागर किया तो 15 दिन के बाद ही आंग्ल दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने इस सत्य को समक्ष आंग्ल भाषा में प्रकाशित किया। उसके बाद इस लिव इन या सहचर्य जीवन पर हिंदी व अन्य भाषा के दैनिकों ने विराम लगाया। युवा अवस्था में शारीरिक आकर्षण और दैनिक जीवन की मजबूरियों और आवश्यकताओं के परिस्थिति जन्य सहचर्य जीवन गुजारने वाले स्त्री-पुरूषों से पूछिये तो कुछ दिनों साथ रहने के बाद ही एक-दूसरे के पीठ पीछे दुर्गुणों का ब्यान करने, मुक्ति पाने की ताक में रहते हैं। फिर लड़के भी नहीं चाहते कि उसकी संगति ज्यादा कमाई वाली हो और उसे खर्चों के मामले में नीचा दिखाये, फिर भी कारणवश रहना भी पड़े तो ज्यादा हो हल्ला नहीं करने पर स्त्रियों में ज्यादा धन और स्वर को लेकर सदा ही कहीं न कहीं अहंकार रहता ही है। जब अहंकार सामने आता है तो संबंधों में बिखराव होने लगता है। फिर जब पुरूष बगावत करता है तो स्त्रियों/लड़कियों फिर नीचा दिखाने और बदनामी से बचने लड़कों के खिलाफ यौन उत्पीड़न धोखा देना, बलात्कार का आरोप लगा उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लगा न्यायालय में घसीटती हैं। इससे न केवल स्वयं वरन स्वयं के माता-पिता के साथ लड़के के और उसके माता-पिता और समाज व धर्म की बदनामी और शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। लड़के-लड़की दोनों और दोनों के दो माताओं और पिताओं के साथ उन सबके रिश्तेदार समाज की मानसिक प्रताड़नाओं से अप्रत्यक्ष रूप से गुजरता है। चूंकि बिना शादी के सहचर्य में रहे तो समाज से कटे हुये, दोनों के माता-पिता से अलग-अलग बचे रहे, फिर बच्चे पैदा करने और गृहस्थी बसा समाज का हिस्सा बनने की तो दूर-दूर तक कोई संभावना ही नहीं। इसी सोच में साथ रहकर संसर्गकर जिंदगी गुजारते रहे कि मुफ्त में बिना किसी जिम्मेदारी के जीवन चल रहा है, तो चलने दो। ये सोचते-सोचते और इस भ्रम में ही जीवन के 2-7 वर्ष गुजय गये, जब तक लड़कियां गर्भ निरोधक गोलियां खाते-खाते कब सदा के लिए गर्भाशय खराब और सदा के लिए बंद हो गया, और लड़के द्वारा टोपी पहन संभोग करते-करते कब वीर्य के शुक्राणु पूरी तरह से कमजोर या नष्ट हो गये मालूम ही नहीं चला। इस प्रकार धरती पर आकर माता-पिता बनने के नैसर्गिक कार्य को ही पूरा नहीं कर पाये, अब यदि इस बीच लड़के को अच्छी नौकरी और लड़की मिल गई, और लड़की को मनपंसद शादी योग्य वर मिल गया। राजी मर्जी से अलग हो शादी कर भी ली तो क्या देंगे अपने साथी, अब माता-पिता बनने के लिये, परखनली शिशु केन्द्र जाकर किसी के शुक्राणु और किसी की कोख किराये पर लेकर बच्चे पैदा करवा रहे हैं। ऐसे 70-80 प्रश लड़के लड़कियां 30,32,35 के उम्र में ही, फिर तन अगर सौंप भी दिया तो जीवन भर मन में लड़के अपने इतिहास को भुला नहीं पाते, बेशक लड़कियां इस मामले में आगे रहती है। वे सब भूल जाती है। ये सब कारण वर्तमान में युवक-युवतियों की हत्या और आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। तो इसके साथ ही लड़कियां स्वयं पहले किसी कारणवश लड़कों के साथ सहचर्य जीवन में स्वयं रहने तैयार हो जाती है बाद में अनबन होने पर बलात्कार, शादी करने का वादा कर यौन शोषण का आरोप लगा न्यायालय तक मामले को खींच यथार्थ में तो अपनी चारित्रिक दोष और यौन लालसा का ही प्रदर्शन करती है। ठीक है कि कानून तौर पर वह बलात्कार की श्रेणी में है। इसके विपरीत यदि ऐसी लड़कियां थोड़ी सी समझदार और लालसा को त्याग लड़के को चाहती थी और लड़का भी चाहता था तो शादी कर लेती।

(शेष पेज 11 पर)

भारतीय वेदों, संस्कृति और हिन्दू में धर्म मार्च अंत में गुड़ी पड़वा से ही नववर्ष

मृत्यु का भय और अमर होने की कामना, 1 जन से सरकारी वित्तीय वर्ष मोदी का

अंग्रेजों ने भी भारतीय जलवायु और धर्म व वेदों की मान्यता के अनुसार ही 1 अप्रेल से रखा वित्तीय वर्ष

हमारे राष्ट्र के दृष्य-श्रव्य और मुद्रित प्रचार माध्यम शुद्धतः धन के लोभी भांडों बुद्धिहीन भेड़ों की फौज बन चुकी है। धन दाता गाडरिये मोदी ने जो कि 14-15 वर्ष की उम्र से 32-35 वर्ष की उम्र तक पर से भगाये जाने के बाद माफियाओं और अपराधियों के बीच रहा। जब ज्यादा मानसिक, सामाजिक संत्रास होने लगा तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अवैतानिक सेवक बन बुद्धिजीवियों के बीच समर्पित भाव से सेवा देकर 25-50 राष्ट्रभक्ति के वाक्य सीख भाषणबाजी करने लगा। उसे 35 से 40 की उम्र के बीच समझ आया कि राजनीति करने और हिंदुओं के बीच अपना नायक बनने के सपने को पूरा करने के लिए केवल रा. स्व. से. सं की सेवकों और प्रशिक्षकों की तरह केवल देशभक्ति और हिन्दुत्व की बात करना और थोड़ी सी हाथ-पैर मटकाकर नौटंकी करना नेता बनने के लिए पर्याप्त है। इसलिए सेवा करते-करते सारे बड़े नेताओं के राज इकट्ठा किए। विधानसभा चुनाव में टिकट झटका और पहले मुख्यमंत्री और बाद में इसी शैली से प्रधानमंत्री बन गया। स्वाभाविक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा 14 से 35 वर्ष का गुंडे, बदमाशों, माफियाओं के साथ गुजरा,पढ़ा-लिखा नहीं जैसे उसको बाबू, अधिकारी, नचाते हैं। नाचने लगता हैं, स्वाभाविक है, उसको हिन्दू धर्म वेदों पुराणों का रत्ती मात्र ज्ञान नहीं। फिर प्रधानमंत्री तो मीडिया और आईएएस लॉबी के लालच दे और खरीदकर बन गया, और अपने आप को अमर बनाने के लिए भारतीय पत्र मुद्रा बदल दी, जब उसके दिमाग में पूंजीपतियों का लाभ और अपनी महानता ही दिख रही थी उसे 125 करोड़ लोगों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का इतना अंदाजा नहीं था जब करोड़ों उसकी मौत की कामना की और गालियां बकी तो मौत का डर सताने लगा, तो अमर बनने के लिए कुछ तो उल्टा सीधा करना जरूरी था। इसलिए विश्व को ज्ञान का प्रकाश बिखेरने सिखाने वाले राष्ट्र के वैज्ञानिक आधार को छोड़कर विदेशी संस्कृति का पालन करने और बहुराष्ट्रीय कं. को लाभ पहुंचाने देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के यथार्थ को त्याग, वित्तीय वर्ष बदलने की धुन संवार हो गई और अपने कुकर्मों को ढांकने असफलताओं से पीछा छुड़ाने राष्ट्र के शिक्षण सत्र जो मार्च से समाप्त होते हैं मार्च अंत तक खरीफ और रबी की फसलों के उत्पादन, खपत, आयात, निर्यात की स्थिति मार्च अंत में स्पष्ट हो जाती है। से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष को बदल 1 जन से वित्तीय वर्ष प्रारंभ करने की घोषणा मात्र इतिहास पुरूष बन अमर बनने के लिए कर दी गई, जबकि जनवरी सबसे छोटे दिन होने के साथ भारत में शीत ऋतु और रबी की फसल बोने का समय होता है। मात्र खरीफ के उत्पादन से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का आंकलन, बजटिंग अगले वर्ष के नियोजन के लिए, आय-व्यय के निर्धारण का उचित समय कैसे हो सकता है। अच्छी, सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक आधार के वित्तीय वर्ष को मात्र अपने को अमर बनाने, इतिहास पुरूष बनने के लिए त्याग कर, विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. के हित लाभ को ध्यान में रख अपने कुकर्मों को ढांकने और नए कुकर्म करने से नजर बचाकर, बैंकों, कोषालयों में इसकी आड़ में मोटी हेरा-फेरी करने, देश के 100 करोड़ लोगों का वास्तविक हित हड़पने के लिए 1 जनवरी से वित्तीय वर्ष प्रारंभ करने का षड़यंत्र शायद इसलिये रचा गया है। भारत के बिकाऊ मीडिया जो भेड़ियों की फौज है, बस कुछ टुकड़े डालकर खरीद लीजिये, वो हुआ-हुआ करने लगेंगे, क्योंकि भारत के मीडिया में बुद्धिजीवियों, ज्ञानियों, ध्यानी नहीं होते, ये सत्ता के खरीदे भांड होते हैं। जिन्हें सम्पन्नता सुरा सुंदरी का भोग लगाईये, जो चाहते है करवाइये। इन्हें जनहित समाज और राष्ट्रहित से कोई मतलब नहीं होता, जिसका यथार्थ जनता भोग रही है। जब उसने 1 जन से नए वित्तीय वर्ष की घोषणा की तो मीडिया चाहे दृष्य, श्रव्य या मुद्रित हो उसके बिना वैज्ञानिक, आर्थिक आध्यात्मिक आधार के भी वो जनता को भ्रमित करने 1 जनवरी से वित्तीय वर्ष के गुण गाने लगे,वैसे भी पूरे युरोप के 400 वर्ष पूर्व का इतिहास देखा जाये तो सारा ज्ञान भाषा, गणित, विज्ञान,भूगोल, आयुर्वेद, रसायन, भौतिक, कृषि, धर्म आध्यात्म, उद्यानिकी, खगोल, वायुमंडल, नाप-तौल, कैलेंडर, चंद्र मास व सौर मास भारत से ही पहुंचा और वायुमंडलीय व जलवायु व भौगोलिक आधार पर उन परिस्थितियों के अनुसार उसका विकास हुआ। निसंदेह ऋषियों-मुनियों की गहन तपस्या, चिंतन, मनन के कारण हर क्षेत्र के ज्ञान और विज्ञान के आधार पर धर्म, आध्यात्म और समाज के नीति, नियम निर्धारित किये गये, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जितना अध्ययन, ज्ञानार्जन और कार्य शताब्दियों पूर्व ही हमारे ऋषि-मुनियों ने कर लिया था। जिसके आधार पर केवल गृहों की गति, सूर्य ग्रहण तक की हमारे ब्राह्मण पंडित बिना किसी आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के करते थे और करते है। वह आज भी विश्व के वैज्ञानिकों के लिए अचंभित करने वाला है। जो वर्तमान में भी पूरे विश्व के चंद्र और सौर वर्ष फल सभी ग्रहों, नक्षत्रों की गति उसका मानव जीवन पर पढ़ने वाले प्रभाव को सहस्त्रों वर्षों पूर्व गणितीय व वैज्ञानिक तरीके से भारत के ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों ने ही किया जो वर्तमान में भी पूरे विश्व में सर्वमान्य है, तो फिर खानदानी चोरों आपराधिक प्रवृत्ति के इस अनपढ़ मोदी को शासकीय वित्तीय वर्ष को अप्रैल से बदलकर जनवरी से करने की सूझ कहां से पढ़ गई ये है हिन्दूवादी पाखंडी, जो अपनी आपराधिक मानसिकता के चलते, मात्र अपने आप को महान प्रधानमंत्री बनने और इतिहास में अपना नाम अमर करने के लिए ईसाई वर्ष को शासकीय नववर्ष घोषित करना चाहता है।लानत है इस देश के बुद्धिजीवियों, प्रसार माध्यमों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुखों को जो कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को शासकीय कार्यों से भी समाप्त कर आने वाली पीढ़ियों को पूर्णतः पाश्चात्य संस्कृति में ढकेला, भारतीय नववर्ष की महत्ता को सदा के लिये एक सिरफिरे घोर लालची, मक्कार, जालसाज, अपराधी की सनक को पूरा करने, नष्ट कर देना चाहते हैं। जहां तक हिन्दुओं का सवाल हैं, तो हिन्दू वो घोर स्वार्थी अपने आपको महानज्ञानी ध्यानी होने के पाखंड में, दुनिया से सिमटकर भारत में भी नष्ट होने की कगार पर आ गया। परंतु हजारों वर्ष की गुलामी झेलने के बाद भी उसमें न तो राष्ट्र प्रेम है, न स्वाभिमान है और न ही अपने अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता। इसलिए उससे उम्मीद करना की वह गुड़ी पड़वा से शुरू होने वाले नववर्ष को हटाकर 1 जनवरी से प्रारंभ करने की मोदी की बत्तमीजी को रोकेगा, निरर्थक है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958, इंदौर कार्यालय- मोबा. 9425125569